NEXT IAS

PTS (GS): CSE 2026

PTS (जी.एस.): सिविल सेवा परीक्षा 2026

GENERAL STUDIES

Paper-I | Sectional Test-2

Polity, Governance and Current Affairs (February 2025)

Test Code: 02021725

DATE : 17/08/2025

Test Booklet Series

B

परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम

सामान्य अध्ययन

पेपर-I | सेक्शनल टेस्ट-2

राजव्यवस्था, शासन तथा समसामयिक मामले (फरवरी 2025)

Time Allowed*: *Two Hours ***Maximum Marks: 200***

Before attempting paper please read the instructions given on page no. 2 or 3 carefully and follow them.

समय : दो घण्टे **पूर्णांक : 200**

कृपया प्रश्न-पत्र हल करने से पहले पृष्ठ संख्या 2 अथवा 3 पर दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा उनका अनुसरण करें।

DELHI CENTRE:
Vivekananda House
6-B, Pusa Road, Metro Pillar No. 111,
Near Karol Bagh Metro
New Delhi-110060
Phone: 8081300200

DELHI CENTRE:
Tagore House
27-B, Pusa Road, Metro Pillar No. 118,
Near Karol Bagh Metro
New Delhi-110060
Phone: 8081300200

DELHI CENTRE:
Mukherjee Nagar
637, Banda Bahadur Marg,
Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phone: 9311667076

PRAYAGRAJ CENTRE:
31/31 Sardar Patel Marg,
Civil Lines, Prayagraj
Uttar Pradesh-211001
Phone: 9958857757

JAIPUR CENTRE:
Plot No. 6 & 7, 3rd Floor,
Sree Gopal Nagar,
Gopalpura Bypass, Jaipur-302015
Phone: 9358200511

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें।

अ नु दे श

1. परीक्षा प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर लें कि इसमें कोई बिना छपा, फटा या छूटा हुआ पृष्ठ अथवा प्रश्नांश आदि **न हो**। यदि ऐसा है, तो इसे सही परीक्षण पुस्तिका से बदल लें।

2. **कृपया ध्यान रखें कि OMR उत्तर-पत्रक में उचित स्थान पर रोल नम्बर और परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम A या B को ध्यान से एवं बिना किसी चूक या विसंगति के भरने और कूटबद्ध करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की है। किसी भी प्रकार की चूक/विसंगति की स्थिति में उत्तर-पत्रक निरस्त कर दिया जाएगा।**

3. इस परीक्षण पुस्तिका पर साथ में दिए गए कोष्ठक में आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। परीक्षण पुस्तिका पर और कुछ न लिखें।

4. इस परीक्षण पुस्तिका में **100** प्रश्नांश (प्रश्न) दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नांश **हिन्दी और अंग्रेज़ी** दोनों में छपा है। प्रत्येक प्रश्नांश में चार प्रत्युत्तर (उत्तर) दिए गए हैं। इनमें से एक प्रत्युत्तर को चुन लें, जिसे आप उत्तर-पत्रक पर अंकित करना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही हैं, तो उस प्रत्युत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगे। प्रत्येक प्रश्नांश के लिए **केवल एक** ही प्रत्युत्तर चुनना है।

5. आपको अपने सभी प्रत्युत्तर अलग से दिए गए उत्तर-पत्रक पर ही अंकित करने हैं। उत्तर-पत्रक में दिए गए निर्देश देखें।

6. **सभी** प्रश्नांशों के अंक समान हैं।

7. इससे पहले कि आप परीक्षण पुस्तिका के विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर उत्तर-पत्रक पर अंकित करना शुरू करें, आपको प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ प्रेषित अनुदेशों के अनुसार कुछ विवरण उत्तर-पत्रक में देने हैं।

8. आप अपने सभी प्रत्युत्तरों को उत्तर-पत्रक में भरने के बाद तथा परीक्षा के समापन पर **केवल उत्तर-पत्रक** अधीक्षक को सौंप दें। आपको अपने साथ परीक्षण पुस्तिका ले जाने की अनुमति है।

9. कच्चे काम के लिए पत्रक, परीक्षण पुस्तिका के अन्त में संलग्न हैं।

10. **गलत उत्तरों के लिए दण्ड:**

    सभी प्रश्नों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दण्ड दिया जाएगा।

    (i) प्रत्येक के लिए चार वैकल्पिक उत्तर है। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए हेतु नियत किए गए अंकों का एक-तिहाई दण्ड के रूप में काटा जाएगा।

    (ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जाएगा।

    (iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जाएगा।

11. **प्रश्नों से संबंधित चुनौती/आपत्ति:** यदि छात्रों को लगता है कि या तो प्रश्न/उत्तरों को संशोधित करने की आवश्यकता है या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो वे pts@nextias.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को न कहा जाए तब तक न खोलें।

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

INSTRUCTIONS

1. IMMEDIATELY AFTER THE COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION, YOU SHOULD CHECK THAT THIS TEST BOOKLET DOES ***NOT*** HAVE ANY UNPRINTED OR TORN OR MISSING PAGES OR ITEMS, ETC. IF SO, GET IT REPLACED BY A COMPLETE TEST BOOKLET.
2. **Please note that it is the candidate's responsibility to encode and fill in the Roll Number and Test Booklet Series A or B carefully and without any omission or discrepancy at the appropriate places in the OMR Answer Sheet. Any omission/kdiscrepancy will render the Answer Sheet liable for rejection.**
3. You have to enter your Roll Number on the Test Booklet in the box provided alongside.
4. This Test Booklet contains **100** items (Questions). Each item is printed in **Hindi** and **English** only. Each item comprises four responses (Answers). You will select the response which you want to mark on the Answer Sheet. In case you feel that there is more than one correct response, mark the response which you consider the best. In any case, choose ***ONLY ONE*** response for each item.
5. You have to mark all your responses ***ONLY*** on the separate answer sheet provided. See directions in the Answer Sheet.
6. ***All*** items carry equal marks.
7. Before you proceed to mark in the Answer Sheet the response to various items in the Test Booklet, you have to fill in some particulars in the Answer Sheet as per instructions sent to you with your Admission Certificate.
8. After you have completed filling in all your responses on the Answer Sheet and the examination has concluded, you should hand over to the invigilator ***only the Answer Sheet.*** You are permitted to take away with you the Test Booklet.
9. Sheets for rough work are appended in the Test Booklet at the end.
10. **Penalty for wrong answers:**

    THERE WILL BE PENALTY FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE.

    (i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, **one-third** of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.

    (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a **wrong answer** even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above to that question.

    (iii) If question is left blank, i.e., no answer is given by the candidate, there will be **no penalty** for that question.
11. **CHALLENGE THE QUESTION:** If students feel that either the question(s)/kanswer(s) needs to be modified or require clarification, they can email at **pts@nextias.com**

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

1. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. महाराष्ट्र के एक लोक सभा सदस्य के मत का मूल्य, गोवा के एक लोक सभा सदस्य के मत के मूल्य से अधिक होता है।
2. गुजरात के एक लोक सभा सदस्य के मत का मूल्य, गुजरात के एक राज्य सभा सदस्य के मत के मूल्य के बराबर होता है।
3. राजस्थान के एक विधायक के मत का मूल्य, राजस्थान के एक लोक सभा सदस्य के मत के मूल्य से कम होता है।
4. उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य, बिहार के एक विधायक के मत के मूल्य से भिन्न होता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

2. राज्य मंत्रीपरिषद् की संरचना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी राज्य में, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
2. किसी राज्य में, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।
3. पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत विनिर्दिष्ट क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में जनजातीय कल्याण का प्रभारी मंत्री होगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

3. भारत में मुख्यमंत्री के पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रधानमंत्री के विपरीत, जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, मुख्यमंत्री राज्य के निचले सदन (विधान सभा) का सदस्य होना चाहिए।
2. मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद-पर्यंत पद धारण करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

4. भारत में विधायकों की निम्नलिखित श्रेणियों पर विचार कीजिए:

1. राज्य सभा के परोक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य
2. लोक सभा के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य
3. राज्य सभा के नामित सदस्य
4. दिल्ली केंद्र-शासित प्रदेश की विधान सभा के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य

उपर्युक्त में से कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभा के उपसभापति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र होते हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) कोई नहीं

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

यदि किसी दिन केवल 54 सदस्य (अध्यक्ष को छोड़कर) उपस्थित हों, तो 18वीं लोक सभा की कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती।

कथन-II:

संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति, उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा होता है।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।

1. With reference to the election of the President of India, consider the following statements:
1. The value of the vote of a Lok Sabha member from Maharashtra is higher than that of a Lok Sabha member from Goa.
2. The value of the vote of a Lok Sabha member from Gujarat is equal to that of a Rajya Sabha member from Gujarat.
3. The value of the vote of an MLA from Rajasthan is lower than that of a Lok Sabha member from Rajasthan.
4. The value of the vote of an MLA from Uttar Pradesh is different from that of an MLA from Bihar.

How many of the statements given above are correct?
(a) Only one
(b) Only two
(c) Only three
(d) All four

2. With reference to the composition of the State Council of Ministers, consider the following statements:
1. The total number of Ministers, including the Chief Minister, in a State shall not exceed 15% of the total number of members of the Legislative Assembly of that State.
2. The number of Ministers, including the Chief Minister, in a State shall not be less than 12.
3. In every State having areas specified under the Fifth Schedule, there shall be a Minister in charge of Tribal Welfare.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

3. With reference to the constitutional provisions related to the Office of Chief Minister in India, consider the following statements:
1. Unlike the Prime Minister, who can be a member of either House of Parliament, the Chief Minister must be a member of the lower House of the State.
2. The Chief Minister holds office during the pleasure of the Governor.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

4. Consider the following categories of legislators in India:
1. Indirectly elected members of the Rajya Sabha
2. Directly elected members of the Lok Sabha
3. Nominated members of the Rajya Sabha
4. Directly elected members of the Legislative Assembly of the Union Territory of Delhi

How many of the above are eligible to vote in the elections for the President of India, the Vice-President of India, as well as the Deputy Chairperson of the Rajya Sabha?
(a) Only one
(b) Only two
(c) Only three
(d) None

5. With reference to the Indian polity, consider the following statements :

Statement-I:

Proceedings of the 18th Lok Sabha cannot be conducted if only 54 members, other than the Speaker, are present on a given day.

Statement-II:

The Quorum to constitute a meeting of either House of Parliament is one-tenth of the total number of members of the House.

Which one of the following is correct in respect of the above statements?
(a) Both Statement-I and Statement-II are correct and Statement-II is the correct explanation for Statement-I

(b) कथन–I और कथन–II दोनों सही हैं, तथा कथन–II, कथन–I की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन–I सही है, किंतु कथन–II गलत है।
(d) कथन–I गलत है, किंतु कथन–II सही है।

6. भारत के संविधान के अनुसार राज्य सभा की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य सभा में कुल सीटों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती।
2. राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 238 से अधिक नहीं हो सकती।
3. प्रत्येक राज्य की राज्य सभा में प्रतिनिधि, उस राज्य की विधान सभा और राज्य विधान परिषद-दोनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर चुनते हैं।
4. राज्यों को राज्य सभा में सीटें उनकी जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं, किंतु सभी केंद्र-शासित प्रदेशों का समान प्रतिनिधित्व है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

7. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कानूनी प्रणाली में "संज्ञानात्मक अपराध" की सबसे सही व्याख्या करता है?
(a) ऐसा अपराध जिसके लिए केवल एक मजिस्ट्रेट को ही केस दर्ज करने और जांच शुरू करने का अधिकार है।
(b) ऐसा अपराध जिसमें पीड़ित स्वेच्छा से केस वापस लेने या सुलह करने के लिए सहमत हो सकता है, जिससे आरोप वापस ले लिए जाते हैं।
(c) ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और जांच प्रारंभ कर सकता है।
(d) ऐसा अपराध जिसका विचारण विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा किया जाता है।

8. विधान परिषद् की सदस्यता हेतु अर्हता के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विधान परिषद् हेतु निर्वाचित होने के लिए, उस व्यक्ति को संबंधित राज्य के किसी विधान सभा क्षेत्र का निर्वाचक (Elector) होना चाहिए।
2. राज्यपाल के मनोनयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए, उस व्यक्ति को संबंधित राज्य का सामान्य निवासी होना चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

9. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. भारत का महान्यायवादी
2. भारत का राष्ट्रपति
3. वित्त मंत्री
4. लोक सभा अध्यक्ष
5. राज्य सभा का उपसभापति

उपर्युक्त में से किन्हें किसी भी सदन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति, जिसके वे सदस्य नामित किए जा सकते हैं, की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 2, 4 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

10. राज्यपाल के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यपाल की अनुशंसा के बिना राज्य विधानमंडल में अनुदान की कोई माँग नहीं की जा सकती है।
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है।
3. राज्यपाल के पास राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

(b) Both Statement-I and Statement-II are correct, but Statement-II is not the correct explanation for Statement-I
(c) Statement-I is correct, but Statement-II is incorrect
(d) Statement-I is incorrect, but Statement-II is correct

6. Consider the following statements regarding the composition of the Rajya Sabha as per the Constitution of India:
1. The total number of seats in the Rajya Sabha shall not exceed 250 as per the Constitution.
2. The maximum number of representatives of the States and Union territories in the Rajya Sabha shall not exceed 238.
3. The representatives of each State in the Rajya Sabha are elected by the elected members of both the Legislative Assembly and the Legislative Council of that State.
4. The allocation of seats to the States in the Rajya Sabha is based on their population, but all Union territories have equal representation.

How many of the statements given above are correct?
(a) Only one
(b) Only two
(c) Only three
(d) All four

7. Which of the following best describes the term "Cognizable offence" in the Indian legal system?
(a) An offence for which only a Magistrate has the authority to order registration of a case and start an investigation.
(b) An offence in which the victim can voluntarily agree to withdraw or settle the case, leading to the withdrawal of charges.
(c) An offence for which a police officer may arrest a person and start an investigation without prior permission from a Magistrate.
(d) An offence which is tried exclusively by a Sessions Court.

8. Consider the following statements with reference to the qualification for membership of a Legislative Council:
1. In order to be elected to the Legislative Council, a person must be an elector for an assembly constituency in the concerned state.
2. In order to be qualified for the governor's nomination, a person must be ordinarily resident in the concerned state.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

9. Consider the following:
1. Attorney General of India
2. President of India
3. Finance Minister
4. Speaker, Lok Sabha
5. Deputy Chairperson, Rajya Sabha

Which of the above have the right to speak in, and to take part in the proceedings of either House, any joint sitting of the Houses, and any committee of Parliament of which they may be named a member?
(a) 1 and 3 only
(b) 2, 3 and 4 only
(c) 1, 2, 4 and 5 only
(d) 1, 2, 3, 4 and 5

10. Consider the following statements with regard to the Governor:
1. No demand for a grant can be made in the state legislature except on the recommendation of the Governor.
2. The Governor is consulted by the President while appointing the judges of the concerned state high court.
3. The Governor has the power to appoint and remove the members of the State Public Service Commission.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 3 only
(d) 1, 2 and 3

11. भारत की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सी भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं?

1. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करना।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी दोषी को क्षमादान देना।
3. केंद्रीय मंत्रिपरिषद् से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

12. भारत में मंत्रिपरिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है, इसके क्या निहितार्थ हैं?

1. वह मंत्रिपरिषद् जो लोक सभा का विश्वास खो देती है, उसे इस्तीफ़ा देना अनिवार्य होता है।
2. सभी मंत्री लोक सभा के प्रति परिषद् द्वारा किए गए कृत्यों और चूक के लिए संयुक्त रूप से जवाबदेह होते हैं।
3. जब लोक सभा अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion) पारित करती है, तो सभी मंत्रियों को इस्तीफ़ा देना आवश्यक होता है।
4. यदि मंत्रिपरिषद् लोक सभा में अपना बहुमत खो देती है, तो सदन को भंग कर दिया जाना चाहिए

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

13. निम्नलिखित में से कौन-सा/से, राष्ट्रपति के संबंध में, प्रधानमंत्री का/के संवैधानिक रूप से अनिवार्य (Constitutionally-mandated) कर्त्तव्य है/हैं?

1. प्रधानमंत्री को विधान प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना आवश्यक है।
2. राष्ट्रपति द्वारा माँगे जाने पर प्रधानमंत्री को संघीय मामलों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान करनी होगी।
3. यदि राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षित हो, तो प्रधानमंत्री किसी भी ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद् के समक्ष रखेंगे, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो, लेकिन अभी तक उस पर मंत्रिपरिषद् ने विचार न किया हो।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 2
(b) केवल 1
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यद्यपि संविधान में, राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करने की सुविधा प्रदान की गई है, परंतु राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
2. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने मंत्रिपरिषद् की सलाह को राष्ट्रपति के साथ-साथ राज्यपाल के लिए भी बाध्यकारी बना दिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

15. भारत में राज्य विधान परिषद् की संरचना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लगभग एक-तिहाई सदस्य राज्य के स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
2. लगभग एक-तिहाई सदस्य राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
3. सदस्यों का लगभग छठवाँ हिस्सा राज्य में तीन वर्षों का अनुभव रखने वाले ऐसे शिक्षकों द्वारा चुना जाता है, जिनका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम नहीं होता है।
4. लगभग एक-चौथाई सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

11. With reference to the Indian Parliamentary System, which of the following is/are the discretionary powers of the President of India?

1. Recommending the imposition of President's Rule in a state after receiving the Governor's report under Article 356.
2. Granting pardon to a convict under Article 72 of the Constitution of India.
3. Asking the Union Council of Ministers to reconsider their decision at the first instance.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 2 and 3 only
(c) 3 only
(d) 1, 2 and 3

12. Which of the following are implications of the Council of Ministers being collectively responsible to the Lok Sabha in India?

1. The Council of Ministers that loses the confidence of the Lok Sabha is obliged to resign.
2. All Ministers bear joint responsibility to the Lok Sabha for acts of omission and commission by the Council.
3. When the Lok Sabha passes a no-confidence motion, all Ministers are required to resign.
4. If the Council of Ministers loses its majority in the Lok Sabha, the House must be dissolved.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 2 only
(b) 1, 2 and 3 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

13. Which of the following are the constitutionally-mandated duties of the Prime Minister (PM) in relation to the President?

1. The PM is required to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers (CoM) relating to the proposals for legislation.
2. The PM must provide any information relating to Union affairs if called for by the President.
3. If required by the President, the PM shall place before the Council of Ministers (CoM) any matter decided by an individual Minister but not yet considered by the CoM.

Select the correct answer using the codes given below:

(a) 2 only
(b) 1 only
(c) 1 and 2 only
(d) 1, 2 and 3

14. Consider the following statements:

1. While the Constitution provides for the possibility of the Governor acting at times in his discretion, no such provision exists for the President.
2. 42nd Constitutional Amendment, 1976 has made ministerial advice binding on the President as well as the Governor.

Which of the statements mentioned above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

15. Consider the following statements with reference to the composition of the State Legislative Council in India:

1. About one-third members are elected by the members of local bodies in the State.
2. About one-third members are elected by the members of the State Legislative Assembly.
3. About one-sixth members are elected by teachers of three years standing in the state, not lower in standard than secondary school.
4. About one-fourth members are nominated by the Governor.

How many of the statements given above are correct?

(a) Only one
(b) Only two
(c) Only three
(d) All four

16. हाल ही में संपन्न 'भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते' (TEPA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. EFTA के सदस्य देशों में आइसलैंड, लिख़्टेनश्टाइन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं।
2. EFTA, यूरोपीय संघ के बाद भारत के साथ व्यापार समझौते को औपचारिक रूप देने वाला दूसरा यूरोपीय समूह है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

17. हाल ही में समाचारों में रहे पद "जेवन्स विरोधाभास" (Jevons Paradox) का, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सर्वोत्तम वर्णन करता है?

(a) संसाधन उपयोग की दक्षता में वृद्धि से उस संसाधन का समग्र उपभोग बढ़ सकता है।
(b) विलासिता की वस्तुओं पर उच्च कर उनकी माँग को आनुपातिक रूप से कम कर देते हैं।
(c) उत्पादन में वृद्धि से वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है।
(d) दीर्घकाल में आर्थिक संवृद्धि का पर्यावरणीय क्षरण के साथ व्युत्क्रम संबंध (Inverse relation) होता है।

18. भारत के महान्यायवादी के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
2. संविधान के अनुसार, मंत्रिपरिषद् के त्याग-पत्र देने या भंग होने पर महान्यायवादी को भी त्याग-पत्र देना होता है।
3. उसे निजी स्तर पर कानूनी अभ्यास करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

19. निम्नलिखित में से किस/किन परिस्थिति/परिस्थितियों में, राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने का अधिकार है?

1. जब एक सदन किसी साधारण विधेयक को पारित कर देता है, लेकिन दूसरा सदन उसे पूर्णतः अस्वीकार कर देता है।
2. जब दोनों सदन किसी धन विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर असहमत होते हैं।
3. जब एक सदन संविधान संशोधन विधेयक पर कार्रवाई को छह माह से अधिक समय तक विलंबित करता है।
4. जब दूसरे सदन द्वारा विधेयक प्राप्त होने की तिथि से छह माह से अधिक का समय बीत चुका हो और विधेयक पारित न हुआ हो।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 4
(b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 3
(d) 1, 2, 3 और 4

20. किस संविधान संशोधन अधिनियम ने प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद् की अधिकतम संख्या लोक सभा की कुल सदस्य संख्या की 15% निर्धारित की?

(a) 93वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2005
(b) 52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1985
(c) 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003
(d) 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976

21. विभाग-संबंधी स्थायी समितियों (DRSCs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. DRSCs का मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
2. प्रत्येक DRSC में लोक सभा और राज्य सभा, दोनों के सदस्य होते हैं।
3. DRSCs के सदस्यों का निर्वाचन सदनों के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) केवल 3

16. Consider the following statements with reference to the recently concluded India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA):

1. EFTA member countries include Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.
2. EFTA is the second European bloc after the European Union to formalize a trade pact with India.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

17. Which of the following statements best describes the term "Jevons Paradox", as recently seen in the news?

(a) An increase in efficiency of resource use may lead to higher overall consumption of that resource.
(b) Higher taxes on luxury goods reduce their demand proportionally.
(c) Increased production leads to diminishing marginal utility of goods.
(d) Economic growth is inversely related to environmental degradation in the long run.

18. Consider the following statements regarding the Attorney General of India:

1. His term is not fixed by the Constitution and he holds office during the pleasure of the President.
2. Constitution mandates that the Attorney General must resign whenever the Council of Ministers resigns or is dissolved.
3. He is prohibited from engaging in private legal practice.

How many of the statements given above are correct?

(a) Only one
(b) Only two
(c) All three
(d) None

19. Under which of the following circumstances is the President empowered to summon a joint sitting of both Houses of Parliament under Article 108 of the Constitution?

1. When one House passes an ordinary bill, but the other House rejects it outright.
2. When the two Houses disagree on amendments to be made to a Money Bill.
3. When one House delays action on a Constitution Amendment Bill for more than six months.
4. When more than six months have elapsed from the date of the receipt of the bill by the other House without the bill being passed by it.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 4 only
(b) 1, 2 and 4 only
(c) 3 only
(d) 1, 2, 3 and 4

20. Which Constitutional Amendment Act fixed the maximum size of the Union Council of Ministers, including the Prime Minister, at 15% of the total strength of the Lok Sabha?

(a) 93rd Constitutional Amendment Act, 2005
(b) 52nd Constitutional Amendment Act, 1985
(c) 91st Constitutional Amendment Act, 2003
(d) 42nd Constitutional Amendment Act, 1976

21. With reference to the Departmentally-Related Standing Committees (DRSCs), consider the following statements:

1. The main objective of the DRSCs is to secure more accountability of the Executive to the Parliament.
2. Each DRSC consists of members from both Lok Sabha and Rajya Sabha.
3. The members of DRSCs are elected by the members of the Houses from amongst its own members.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 2 only
(d) 3 only

22. भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक कार्यकरण (Transaction of The Business) तथा मंत्रियों के मध्य उन कार्यों के आवंटन हेतु नियम बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है?
(a) राज्य के मुख्य सचिव
(b) राज्यपाल
(c) मुख्यमंत्री
(d) राज्य विधानमंडल

23. भारत की शासन-प्रणाली में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं उसकी भूमिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. मंत्रिमंडल सचिवालय भारत के राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करता है।
2. मंत्रिमंडल सचिव भारत में सिविल सेवाओं का पदेन प्रमुख होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

24. राज्य विधान सभा के सत्रों के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए-

	कार्य	:	**निष्पादन करने वाला**
1.	आहूत करना	:	पीठासीन अधिकारी
2.	अनिश्चितकालीन स्थगन	:	राज्यपाल
3.	स्थगन	:	पीठासीन अधिकारी
4.	सत्रावसान	:	मुख्यमंत्री
5.	विघटन	:	राज्यपाल

उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 2, 4 और 5
(d) केवल 3 और 5

25. भारत में केंद्र और राज्यों द्वारा उधार लेने के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केंद्र सरकार भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर भारत के भीतर और विदेश दोनों जगह उधार ले सकती है।
2. यदि कोई राज्य सरकार, केंद्र के प्रति ऋणी है, तो उसे ऋण लेने के लिए केंद्र सरकार की सहमति आवश्यक होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

26. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा व्यय भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) पर भारित नहीं होता है?
(a) राष्ट्रपति कार्यालय के वेतन और भत्ते
(b) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन
(c) मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन और पेंशन
(d) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देय भत्ते और पेंशन

27. भारत के निम्नलिखित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों पर विचार कीजिए:
1. कर्नाटक
2. महाराष्ट्र
3. पश्चिम बंगाल
4. जम्मू और कश्मीर

उपर्युक्त में से किन राज्यों में द्विसदनीय राज्य विधानमंडल (Bicameral State Legislature) है?
(a) केवल 2 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) केवल 1, 2 और 4

28. संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक (Money Bill) पर निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान लागू होते हैं?
1. राज्य सभा धन विधेयक में संशोधन की अनुशंसा कर सकती है, लेकिन इसे संशोधित नहीं कर सकती।
2. राज्य सभा को भेजे गए धन विधेयक अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जिसमें यह घोषित किया गया हो कि वह धन विधेयक है।
3. धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के साथ या बिना भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3

22. Who is empowered under the Constitution of India to make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of the State, and for the allocation among ministers of the said business?
(a) Chief Secretary of the State
(b) Governor
(c) Chief Minister
(d) State Legislature

23. With reference to the Cabinet Secretariat and its role in Indian governance, consider the following statements:
1. The Cabinet Secretariat operates under the direct supervision of the President of India.
2. The Cabinet Secretary is the ex-officio head of the civil services in India.

Which of the statements above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

24. Consider the following pairs with reference to the Sessions of the State Legislative Assembly:

	Action	*: Performed by*
1.	Summoning	: Presiding Officer
2.	Adjournment sine die	: Governor
3.	Adjournment	: Presiding Officer
4.	Prorogation	: Chief Minister
5.	Dissolution	: Governor

Which of the above pairs have been correctly matched?
(a) 1 and 3 only
(b) 2, 3 and 4 only
(c) 1, 2, 4 and 5 only
(d) 3 and 5 only

25. With reference to borrowing by the Centre and the States in India, consider the following statements:
1. The Central government can borrow both within India and abroad upon the security of the Consolidated Fund of India.
2. A State Government requires the consent of the Union government to raise loans if it is indebted to the Centre.

Which of the statements above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

26. Which of the following expenditures is not charged upon the Consolidated fund of India under Article 112 (3) of the Indian Constitution?
(a) Emoluments and allowances of the Indian President's office
(b) Pension of the Judge of High Courts
(c) Salary and pensions of Chief Election Commissioner
(d) Allowances, and pensions payable to Judges of the Supreme Court

27. Consider the following States/Union Territories of India:
1. Karnataka
2. Maharashtra
3. West Bengal
4. Jammu and Kashmir

Which of the above have a bicameral State Legislature?
(a) 2 and 3 only
(b) 1 and 2 only
(c) 1, 3 and 4 only
(d) 1, 2 and 4 only

28. Which of the following provisions is/are applicable to a Money Bill under Article 110 of the Constitution?
1. The Rajya Sabha may recommend changes to a Money Bill, but cannot amend it.
2. A Money Bill sent to the Rajya Sabha must bear the Speaker's certificate declaring it to be a Money Bill.
3. Money bills can be introduced with or without prior recommendation of the President.

Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 only
(d) 1, 2 and 3

29. भारत में अंतर-राज्यीय परिषद् (Inter-State Council) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक संवैधानिक निकाय है, जो संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित की गई है।
2. राष्ट्रपति, जब भी आवश्यक समझें, इसे स्थापित करने के लिए अधिकृत हैं।
3. यह एक स्थायी निकाय है, जिसकी बैठक कम-से-कम वर्ष में एक बार होती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

30. संसद की लोक लेखा समिति (PAC) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. लोक लेखा समिति का गठन सबसे पहले भारत शासन अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था।
2. कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र नहीं होता है।
3. लोक लेखा समिति का कार्यकाल लोक सभा के कार्यकाल के साथ समाप्त होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 1 और 3

31. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य
2. राज्य सभा के मनोनीत सदस्य
3. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
4. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य

उपर्युक्त में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, लेकिन उनके निर्वाचन में भाग नहीं लेते?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) केवल 4

32. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को प्रभावित करने वाला अध्यादेश, राष्ट्रपति के निर्देश के बिना जारी नहीं कर सकता।
2. यदि राज्यपाल की राय में कोई विधेयक उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को प्रभावित करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

33. निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) प्रकाशित करता है?

(a) विश्व आर्थिक मंच
(b) ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल
(c) विश्व बैंक
(d) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

34. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. जिन गांवों में कम-से-कम 50% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, वे इस योजना के अंतर्गत अवसंरचना विकास के लिए पात्र हैं।
2. गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति कौशल विकास और आय-सृजन योजनाओं के लाभ के लिए पात्र हैं।
3. इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

35. भारत की संसद में गैर-सरकारी विधेयकों (Private Member's Bills) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कोई भी मंत्री संसद में गैर-सरकारी विधेयक पुर:स्थापित नहीं कर सकता।

29. With reference to the Inter-State Council in India, consider the following statements:
1. It is a Constitutional body set up under Article 263 of the Constitution.
2. The President is empowered to establish it whenever considered necessary..
3. It is a permanent body that meets at least once every year.

Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

30. With reference to the Public Accounts Committee (PAC) of the Parliament, which of the following statements is/are correct?
1. It was first set up under the provisions of the Government of India Act, 1935.
2. A minister is not eligible to be elected as a member of the PAC.
3. Its term is co-terminus with that of the Lok Sabha.

Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1 and 3 only

31. Consider the following:
1. Elected members of Rajya Sabha
2. Nominated members of Rajya Sabha
3. Elected members of the legislative assemblies of states
4. Elected members of the legislative assemblies of the Union Territory of Delhi

Which of the above participate in the impeachment of the President but not in his/her election?
(a) 1 and 3 only
(b) 2 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) 4 only

32. Consider the following statements:
1. The Governor of a State cannot promulgate an ordinance affecting the constitutional position of the High Court without the President's instructions.
2. The Governor shall mandatorily reserve a bill for the President's consideration if, in his opinion, it affects the constitutional position of the High Court.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

33. Which of the following organisations publishes the Corruption Perceptions Index (CPI)?
(a) World Economic Forum
(b) Transparency International
(c) World Bank
(d) International Monetary Fund

34. With reference to the Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM-AJAY), consider the following statements:
1. Villages with at least 50% Scheduled Caste population are eligible for infrastructure development under the scheme.
2. SC persons living below the poverty line are eligible for benefits under the skill development and income-generating schemes.
3. The scheme is being implemented by the Ministry of Social Justice & Empowerment.

Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

35. With reference to Private Member's Bills in Parliament of India, consider the following statements:
1. No minister can introduce the private member bill in the Parliament.

2. गैर-सरकारी सदस्य संविधान (संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित नहीं कर सकते।
3. सदन में इसे पुर:स्थापित करने के लिए विधायिका में कम-से-कम तीन महीने पहले सूचना देना आवश्यक है।
4. केवल निचले सदन के सदस्य ही गैर-सरकारी विधेयक पुर:स्थापित कर सकते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

36. भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए:

सरकारी पहल	उद्देश्य	प्रशासनिक मंत्रालय
जलवाहक योजना	आंतरिक जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ावा देना	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
समुद्रयान मिशन	गहरे समुद्र की खोज	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
सागरमाला योजना	बंदरगाह-आधारित विकास को बढ़ावा देना	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

उपर्युक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही रूप से सुमेलित है?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) इनमें से कोई नहीं

37. किसान पहचान-पत्र (Farmer ID) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह किसानों की एक डिजिटल पहचान है, जो किसानों के भूमि अभिलेखों और पशुधन स्वामित्व से जुड़ी होती है।
2. इसका निर्माण और रख-रखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

38. संसदीय मामलों के संदर्भ में, 'लेखानुदान (Vote on Account)' शब्द का तात्पर्य है:

(a) अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए संसद द्वारा दिया गया अनुदान
(b) नव-निर्मित राज्यों के व्यय को पूरा करने के लिए एक विशेष प्रावधान
(c) बजट के अनुमोदन की प्रत्याशा में सरकार को धन निकालने की अनुमति देने वाला प्रावधान
(d) अतिरिक्त व्यय को सुधारने के लिए एक संवैधानिक तंत्र

39. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान ने संसद में कार्य संपादन हेतु हिंदी और अंग्रेज़ी को भाषाओं के रूप में घोषित किया है।
2. राजभाषा अधिनियम (1963) ने हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी को भी जारी रखने की अनुमति दी।
3. पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को सदन को उसकी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

40. भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगी।
2. राज्य में मंत्रिपरिषद् के त्याग-पत्र से आवश्यक रूप से राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. Private members can not introduce a Constitution (Amendment) Bill.
3. Its introduction in the House requires at least three months' notice in the legislature.
4. Only the members of the Lower House can introduce a private member's bill.

How many of the statements given above are correct?
(a) Only one
(b) Only two
(c) Only three
(d) All four

36. Consider the following information regarding various initiatives launched by the Government of India:

Government initiative	*Objective*	*Administrative ministry*
Jalvahak scheme	Promoting cargo transportation via inland waterways	Ministry of Ports, Shipping and Waterways
Samudrayaan mission	Deep ocean exploration	Ministry of Earth Sciences
Sagarmala scheme	Promoting port-led development	Ministry of Ports, Shipping and Waterways

In how many of the above rows is the given information correctly matched?
(a) Only one
(b) Only two
(c) All three
(d) None of the above

37. With reference to Farmer ID (Kisan Pehchaan Patra), consider the following statements:
1. It is a digital identity for farmers which is connected to farmer's land records and livestock ownership.
2. It is created and maintained by Union governments.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

38. With reference to parliamentary affairs, the term 'Vote on Account' refers to:
(a) A grant made by the Parliament for meeting unexpected expenditure.
(b) A special provision to meet the expenditure of newly created states.
(c) A provision allowing the government to withdraw money in anticipation of approval of Budget.
(d) A constitutional mechanism to rectify excess expenditure.

39. Consider the following statements:
1. The Constitution has declared Hindi and English to be the languages for transacting business in the Parliament.
2. The Official Languages Act, 1963 allowed English to be continued along with Hindi.
3. The presiding officer can permit a member to address the House in his mother-tongue.

Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

40. With reference to the Constitution of India, consider the following statements:
1. The Union Council of Ministers shall hold office during the pleasure of the President.
2. Resignation of the Council of Ministers in state does not necessarily lead to President's Rule.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

41. भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के पद के संदर्भ में, निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए:

1. राज्यपाल का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
2. राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करेगा।
3. राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
4. राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

उपर्युक्त में से कौन-से प्रावधान भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं?

(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) केवल 2 और 3

42. निम्नलिखित मामलों पर विचार कीजिए:

1. साधारण विधेयकों का पुर:स्थापन
2. राज्य से राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन
3. राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों का अनुमोदन
4. धन विधेयकों पर विचार

उपर्युक्त में से किस मामले में राज्य विधान परिषद् को राज्य विधान सभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं?

(a) केवल 1 और 4
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) केवल 1, 2 और 3

43. "इसका तात्पर्य दण्ड की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना है। उदाहरण के लिए, दो वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा को एक वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है।"

उपर्युक्त अनुच्छेद में राष्ट्रपति की निम्नलिखित में से कौन-सी क्षमादान शक्ति का वर्णन किया गया है?

(a) क्षमा (Pardon)
(b) विराम (Respite)
(c) परिहार (Remission)
(d) प्रविलंबन (Reprieve)

44. लोक सभा के विघटन (Dissolution) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय संविधान के अनुसार, अपनी पहली बैठक के दिन से पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर लोक सभा का विघटन हो जाता है।
2. राष्ट्रपति पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी लोक सभा को भंग कर सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

45. लोक सभा अध्यक्ष की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
2. यदि लोक सभा का कोई सदस्य भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, तो अध्यक्ष उसे अयोग्य घोषित कर सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

46. आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक (Index of Eight Core Industries - ICI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –

1. आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
2. आठ प्रमुख उद्योगों में, पेट्रोलियम रिफ़ाइनरी उत्पादों का भारांश सर्वाधिक है, जबकि उर्वरकों का सबसे कम है।
3. आठ प्रमुख उद्योग मिलकर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल वस्तुओं के कुल भार का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा रखते हैं।

41. With reference to the office of the Governor under the Constitution of India, consider the following provisions:

1. The term of office of the Governor is five years.
2. The President shall consult the Chief Minister of the concerned State before appointing the Governor.
3. A person shall be eligible for appointment as Governor only if he has completed the age of 35 years.
4. The Governor shall hold office during the pleasure of the President.

Which of the above provisions are explicitly mentioned in the Constitution of India?

(a) 1, 2 and 4 only
(b) 1 and 3 only
(c) 1, 3 and 4 only
(d) 2 and 3 only

42. Consider the following matters:

1. Introduction of Ordinary Bills.
2. Election of the members of the Rajya Sabha from the State.
3. Approval of ordinances promulgated by the Governor.
4. Consideration of Money Bills.

In which of the above matters, State Legislative Council has equal powers with the State Legislative Assembly?

(a) 1 and 4 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) 1, 2 and 3 only

43. "It implies reducing the period of a sentence without changing its character. For example, a sentence of rigorous imprisonment for two years may be remitted to rigorous imprisonment for one year".

Which of the following pardoning powers of the President has been described in the above paragraph?

(a) Pardon
(b) Respite
(c) Remission
(d) Reprieve

44. With reference to the dissolution of Lok Sabha, consider the following statements:

1. According to the Constitution of India, the completion of five years from the first day of its meeting amounts to dissolution of the Lok Sabha.
2. President may dissolve the Lok Sabha before the completion of its five-year term.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

45. With reference to the powers of the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements:

1. The decision of the Speaker on whether a Bill is a Money Bill is final.
2. The Speaker can disqualify a member of the Lok Sabha if the member holds an office of profit under the Government of India.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

46. With reference to the Index of Eight Core Industries (ICI), consider the following statements:

1. The Index of Eight Core Industries is published by the Ministry of Commerce and Industry.
2. Among the eight core industries, Petroleum Refinery Products have the highest weightage, while Fertilizers have the lowest.
3. The Eight Core Industries together comprise more than one-third of the total weight of the items included in the Index of Industrial Production (IIP).

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

47. लुप्तप्राय प्रजातियों की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करने के लिए भारत का पहला चिड़ियाघर-आधारित जैव बैंक (Zoo-based biobank) कहाँ स्थापित किया गया है?

(a) हेमिस राष्ट्रीय उद्यान
(b) पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान
(c) जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
(d) नीलगिरि जैवमंडल रिज़र्व

48. हाल ही में समाचारों में देखे गए प्रोजेक्ट वाटरवर्थ (Project Waterworth) का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वोत्तम रूप से वर्णित है?

(a) यह नासा और इसरो के मध्य एक संयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन है।
(b) यह हरित नौवहन मार्गों को बढ़ावा देने हेतु एक स्वच्छ ऊर्जा पहल है।
(c) यह इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से एक वैश्विक समुद्र-तल केबल परियोजना है।
(d) यह महासागर के तापमान में वृद्धि का पता लगाने के लिए एक जलवायु मॉडलिंग कार्यक्रम है।

49. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (Small Modular Reactors - SMRs) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –

1. SMRs को 1000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
2. SMRs आमतौर पर थोरियम को अपने प्राथमिक ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं।
3. SMRs को कारखानों में निर्मित किया जा सकता है और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1
(c) केवल 3
(d) केवल 2 और 3

50. हाल ही में एक नजदीकी आकाशगंगा के चारों ओर देखा गया "आइंस्टीन रिंग" नामक परिघटना निम्नलिखित का परिणाम है:

(a) दो दूरस्थ तारों से आने वाली प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण।
(b) एक दूरस्थ वस्तु से आने वाले प्रकाश का एक विशाल अग्रभूमि आकाशगंगा द्वारा गुरुत्वीय लेंसिंग।
(c) चुंबकीय क्षेत्र से कॉस्मिक किरणों का परावर्तन।
(d) अंतरतारकीय धूल के कारण प्रकाश का विवर्तन।

51. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

भारत में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति राज्यपाल की तुलना में व्यापक है।

कथन-II:

राष्ट्रपति उस व्यक्ति को माफ कर सकते हैं जिसे किसी राज्य की उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दिया हो, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते।

कथन-III:

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति उन मामलों तक भी प्रसरित होती है जो कोर्ट-मार्शल द्वारा सुनाए गए हों, जबकि राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति नहीं है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है?

(a) कथन-II और कथन-III दोनों सही हैं तथा दोनों कथन-I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन-II और कथन-III दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक ही कथन-I की व्याख्या करता है।
(c) केवल कथन-II या कथन-III में से एक सही है और वह कथन-I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन-II और न ही कथन-III सही है।

52. भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All-India Judicial Service) की स्थापना के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती।
2. संवैधानिक संशोधन विधेयक (Constitutional Amendment Bills) किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है।

Which of the statements given above are correct?

(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

47. India's first zoo-based biobank to preserve genetic material of endangered species has been set up at:

(a) Hemis National Park
(b) Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park
(c) Jim Corbett National Park
(d) Nilgiri Biosphere Reserve

48. Which of the following statements best describes the objective of Project Waterworth, recently seen in the news?

(a) It is a collaborative space exploration mission between NASA and ISRO.
(b) It is a clean energy initiative to promote green shipping routes.
(c) It is a global subsea cable project aimed at enhancing internet connectivity.
(d) It is a climate-modelling programme to track the rise in ocean temperatures.

49. Consider the following statements with reference to the Small Modular Reactors (SMRs):

1. SMRs are designed to produce up to 1000 MW electricity.
2. SMRs usually use thorium as their primary fuel.
3. SMRs can be manufactured in factories and deployed in remote locations.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 and 2 only
(b) 1 only
(c) 3 only
(d) 2 and 3 only

50. The phenomenon known as the Einstein ring, recently observed around a nearby galaxy, is a result of:

(a) Interference of light waves from two distant stars.
(b) Gravitational lensing of light from a distant object by a massive foreground galaxy.
(c) Reflection of cosmic rays from the magnetosphere.
(d) Diffraction of light due to interstellar dust.

51. Consider the following statements:

Statement-I:

The pardoning power of the President is wider than that of the Governor in India.

Statement-II:

The President can pardon a person sentenced to death by a High Court of a State, whereas the Governor cannot.

Statement-III:

The pardoning power of the President extends to cases tried by a court-martial, whereas the Governor does not have such power.

Which one of the following is correct in respect of the above statements?

(a) Both Statement-II and Statement-III are correct and both of them explain Statement-I
(b) Both Statement-II and Statement-III are correct, but only one of them explains Statement-I
(c) Only one of the Statements II and III is correct and that explains Statement-I
(d) Neither Statement-II nor Statement-III is correct

52. With reference to the Constitution of India, consider the following statements:

1. The creation of an All-India Judicial Service does not require a constitutional amendment under Article 368.
2. Constitutional Amendment Bills can be introduced in either House of Parliament, but the prior approval of the President is required.

उपर्युक्त में से कौन-सा कथन सही है?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

53. भारत में कैबिनेट सचिवालय के कार्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. भारत सरकार प्रशासन (कार्य संचालन) नियम, 1961
2. मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना।
3. प्रधानमंत्री का अनुमोदन प्राप्ति के बाद कैबिनेट बैठकों की चर्चाओं का रिकॉर्ड प्रसारित करना।
4. मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन।

इनमें से कितने कार्य भारत में कैबिनेट सचिवालय के हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

54. भारतीय राजनीति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य सभा की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो स्वयं उस सदन का सदस्य नहीं है।
2. लोक सभा का अध्यक्ष उसके सदस्यों में से चुना जाता है।

निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

55. भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग (Impeachment) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति का महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर किया जा सकता है।
2. राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर कम-से-कम 100 लोक सभा सदस्यों या 50 राज्य सभा सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
3. महाभियोग प्रस्ताव प्रत्येक सदन में उस सदन के कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

56. राष्ट्रपति के पद में रिक्तता या अनुपलब्धता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के संबंध में निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों को वरीयता के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. भारत के मुख्य न्यायाधीश
2. सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश
3. भारत के उपराष्ट्रपति

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही क्रम चुनिए:
(a) 3-2-1
(b) 2-1-3
(c) 2-3-1
(d) 3-1-2

57. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I:

केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) में प्रतिनिधित्व नहीं होता।

कथन II:

क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत गठित वैधानिक निकाय हैं।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(a) कथन–I और कथन–II दोनों सही हैं तथा कथन–II, कथन–I की सही व्याख्या है।
(b) कथन–I और कथन–II दोनों सही हैं, तथा कथन–II, कथन–I की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन–I सही है, किंतु कथन–II गलत है।
(d) कथन–I गलत है, किंतु कथन–II सही है।

58. भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कोई भी विधेयक जो किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करता है, धन विधेयक कहलाता है।

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

53. With reference to the functions of the Cabinet Secretariat in India, consider the following:
1. Administration of the Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961.
2. Ensuring inter-ministerial coordination.
3. Circulation of the record of discussions of Cabinet meetings after obtaining the approval of the Prime Minister.
4. Allocation of financial resources to the Ministries.

How many of the above are functions of the Cabinet Secretariat in India?
(a) Only one
(b) Only two
(c) Only three
(d) All four

54. With reference to the Indian Polity, consider the following statements:
1. Rajya Sabha is headed by an individual who is not a member of that body.
2. The Presiding officer of Lok Sabha is elected amongst its members.

Which of the above statements is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

55. Consider the following statements about the impeachment of the President of India:
1. The President can be impeached only on the grounds of violation of the Constitution.
2. Impeachment charges against the President must be signed by at least 100 members of the Lok Sabha or 50 members of the Rajya Sabha.
3. The impeachment resolution must be passed by each House with a two-thirds majority of the total membership of that House.

How many of the above statements are correct?
(a) Only one
(b) Only two
(c) All three
(d) None

56. Arrange the following constitutional functionaries in the correct order of precedence when it comes to discharging the functions of the President in case of vacancy or unavailability:
1. Chief Justice of India
2. Senior-most Judge of the Supreme Court
3. Vice-President of India

Select the correct sequence using the code given below:
(a) 3-2-1
(b) 2-1-3
(c) 2-3-1
(d) 3-1-2

57. Consider the following statements:

Statement I:

Union Territories are not represented in the Zonal Councils.

Statement II:

Zonal Councils are statutory bodies created under the States Reorganisation Act, 1956.

Which one of the following is correct in respect of the above statements?
(a) Both Statement-I and Statement-II are correct and Statement- II is the correct explanation for Statement-I
(b) Both Statement-I and Statement- II are correct and Statement-II is not the correct explanation for Statement-I
(c) Statement- I is correct but Statement-II is incorrect
(d) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct

58. With respect to the Constitution of India, consider the following statements:
1. Any bill declaring an expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of India is a money bill.

2. भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर लोक सभा द्वारा मतदान नहीं किया जाता, अपितु उसे विनियोग विधेयक में शामिल किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

59. निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम (Constitutional Amendment Act) भारत के संविधान में दल-बदल विरोधी (Anti-Defection Law) के प्रावधान जोड़ता है?

(a) प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1951
(b) 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1989
(c) 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002
(d) 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1985

60. दोहरी सदस्यता (Dual Membership) के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यदि राज्य सभा का कोई सदस्य लोक सभा के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो राज्य सभा में उसका स्थान रिक्त हो जाता है।
2. यदि कोई व्यक्ति राज्य सभा और राज्य विधान सभा दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो राज्य विधान सभा में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, जब तक कि वह 14 दिनों के भीतर राज्य सभा से त्यागपत्र न दे दे।

उपर्युक्त में से कौन सा/कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2
(d) न तो 1 और न 2

61. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान ने राज्य विधान सभा की अधिकतम सदस्य संख्या को निर्धारित किया है, लेकिन किसी न्यूनतम सदस्य संख्या का प्रावधान नहीं किया है।
2. राज्य विधान परिषद् की अधिकतम सदस्य संख्या, विधान सभा की सदस्य संख्या पर निर्भर करती है।
3. उत्तर प्रदेश की विधान सभा में सदस्यों की संख्या सभी राज्यों में सबसे अधिक है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3

62. भारत में कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कैबिनेट समितियाँ संविधान में नहीं दी गई हैं और इन्हें भारत सरकार (कारोबार लेन-देन) नियम, 1961 के तहत बनाया जाता है।
2. गैर-कैबिनेट मंत्री (Non-Cabinet Ministers) को कैबिनेट समितियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
3. आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs) की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

63. डोकरा कलाकृति (Dokra Artwork) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –

1. यह प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाई जाने वाली एक पारंपरिक चित्रकला शैली है।
2. यह मुख्यत: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

2. Expenditure charged upon the Consolidated Fund of India is not voted upon by the Lok Sabha, but are included in the appropriation bill.

Which of the following statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

59. Which of the following Constitutional Amendment Acts inserted the provisions of the Anti-Defection Law into the Constitution of India?
(a) 1st Constitutional Amendment Act, 1951
(b) 61st Constitutional Amendment Act, 1989
(c) 86th Constitutional Amendment Act, 2002
(d) 52nd Constitutional Amendment Act, 1985

60. With reference to the provisions regarding disqualification on grounds of dual membership, consider the following statements:
1. If a member of the Council of States is elected to the House of the People, their seat in the Council of States becomes vacant.
2. If a person is elected to both the Council of States and a State Legislative Assembly, their seat in the State Legislative Assembly shall become vacant unless they resign from the Council of States within 14 days.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

61. Consider the following statements:
1. The Constitution has fixed the maximum strength of the State Legislative Assembly but does not prescribe any minimum strength.
2. The maximum strength of the State Legislative Council depends upon the strength of the Legislative Assembly.
3. The Legislative Assembly of Uttar Pradesh has the highest strength among all the States.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 only
(d) 1, 2 and 3

62. Consider the following statements regarding Cabinet Committees in India:
1. Cabinet Committees are not mentioned in the Constitution, and are formed under the Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961.
2. Non-Cabinet Ministers may be invited to participate in Cabinet Committees.
3. The Cabinet Committee on Economic Affairs is chaired by the Union Finance Minister.

How many of the above statements are correct?
(a) Only one
(b) Only two
(c) All three
(d) None

63 Consider the following statements with reference to the Dokra artwork:
1. It is a traditional style of painting made using natural colours.
2. It is primarily practised in hilly regions of Himachal Pradesh.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

64. ईलाट की खाड़ी (Gulf of Eilat), जो अपनी लचीली प्रवाल भित्तियों (Coral reefs) के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है?
(a) उत्तर-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया
(b) लक्षद्वीप सागर
(c) लाल सागर
(d) पापुआ न्यू गिनी

65. निम्नलिखित में से फॉल्स किलर व्हेल (False Killer Whales) के संदर्भ में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. ये डॉल्फिन की एक प्रजाति हैं।
2. ये एकांतप्रिय जीव हैं और शायद ही कभी समूहों में देखे जाते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

66. यदि बजट के दौरान पेश किए गए कटौती प्रस्ताव में माँग की जाती है कि "माँग की राशि ₹100 कम की जाए", तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार के कटौती प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है?
(a) नीतिगत कटौती प्रस्ताव
(b) आर्थिक कटौती प्रस्ताव
(c) सांकेतिक कटौती प्रस्ताव
(d) अस्वीकृति कटौती प्रस्ताव

67. भारतीय संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग
2. राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति
3. राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव
4. संविधान संशोधन विधेयकों का पारित होना
5. राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करना

उपर्युक्त में से कितने विषयों में राज्य सभा की स्थिति लोक सभा के समान होती है?
(a) केवल दो
(b) केवल तीन
(c) केवल चार
(d) सभी पाँच

68. भारत और बांग्लादेश निम्नलिखित में से किन क्षेत्रीय समूहों के साझा सदस्य हैं?
1. BIMSTEC
2. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association)
3. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (Colombo Security Conclave)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

69. 2024 में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के संदर्भ में, निम्नलिखित पुराने कानूनों को उन अधिनियमों के साथ मिलाएँ जिन्होंने उन्हें प्रतिस्थापित किया:

सूची I (पुराने कानून)	सूची II (नए कानून)
1. भारतीय दंड संहिता, 1860	A. भारतीय न्याय संहिता, 2023
2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973	B. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
3. भारतीय साक्ष्य अधि नियम, 1872	C. भारतीय साक्ष्य अधि नियम, 2023

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(a) 1–B, 2–A, 3–C
(b) 1–A, 2–B, 3–C
(c) 1–A, 2–C, 3–B
(d) 1–C, 2–A, 3–B

70. भारत में आर्द्रभूमि (Wetlands) संरक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention) का सदस्य है।
2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 ही आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 का मूल कानून है।
3. 'हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा' विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का विषय है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

64. The Gulf of Eilat, known for its resilient coral reefs, is situated in which of the following areas?
(a) North-eastern Australia
(b) Lakshadweep sea
(c) Red sea
(d) Papua New Guinea

65. Which of the following statements with reference to False Killer Whales is/are correct?
1. They are a species of dolphin.
2. They are solitary animals and are rarely seen in groups.

Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

66. If a cut motion moved during the Budget demands that "the amount of the demand be reduced by ₹100", it is known as which of the following types of cut motion?
(a) Policy Cut Motion
(b) Economy Cut Motion
(c) Token Cut Motion
(d) Disapproval Cut Motion

67. In the context of Indian Parliament, consider the following matters:
1. Election and impeachment of the President
2. Approval of ordinance issued by the President
3. Resolution to discontinue National Emergency
4. Passing of Constitution Amendment Bills
5. Authorizing the Parliament to make law on subjects enumerated in State List

In how many of the above matters the Rajya Sabha has equal status with the Lok Sabha?
(a) Only two
(b) Only three
(c) Only four
(d) All five

68. India and Bangladesh are common members of which of the following regional groupings?
1. BIMSTEC
2. Indian Ocean Rim Association
3. Colombo Security Conclave

Select the correct answer using the codes given below:
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

69. With reference to the new criminal laws that came into force in 2024, match the following older laws with the Acts that have replaced them:

List-I (Older laws)	*List-II (New laws)*
1. Indian Penal Code, 1860	A. Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
2. Code of Criminal Procedure, 1973	B. Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023
3. Indian Evidence Act, 1872	C. Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

Select the correct answer using the code given below:
(a) 1–B, 2–A, 3–C
(b) 1–A, 2–B, 3–C
(c) 1–A, 2–C, 3–B
(d) 1–C, 2–A, 3–B

70. With reference to wetlands conservation in India, consider the following statements:
1. India is a party to the Ramsar Convention on Wetlands of International Importance.
2. The Environment (Protection) Act, 1986 is the parent legislation for Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.
3. 'Protecting Wetlands for Our Common Future' is the theme for World Wetlands Day 2025.

Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

71. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प "प्रीडेटरी प्राइसिंग" (Predatory Pricing) को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है, जिसे कभी-कभी बाज़ार प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है?

(a) प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करने और बाज़ार में प्रभुत्व हासिल करने के लिए किसी उत्पाद को लागत से कम कीमत पर बेंचना।

(b) संयुक्त लाभ को अधिकतम करने के लिए कार्टेल में कीमतें बढ़ाना।

(c) एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग उपभोक्ताओं से अलग-अलग कीमत वसूलना।

(d) घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए आयातित वस्तुओं को घरेलू उत्पादों से अधिक कीमत पर बेचना।

72. निम्नलिखित युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं:

	अभ्यास	भारत से जुड़े देश	सम्मिलित बल
1.	ट्रोपेक्स (Tropex)	सिंगापुर	नौसेना
2.	धर्म गार्जियन (Dharma Guardian)	जापान	थल सेना
3.	कोमोडो (Komodo)	इंडोनेशिया	वायु सेना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2

(d) केवल 3

73. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. NDB की सदस्यता BRICS समूह से बाहर के देशों के लिए भी खुली है।
2. अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों के विपरीत, एनडीबी का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, और न ही 2

74. संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सांसद की अयोग्यता का कारण नहीं बनेगी?

(a) कोई निर्वाचित स्वतंत्र सदस्य छह महीनों के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए।

(b) कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के पार्टी व्हिप के खिलाफ मतदान करे।

(c) कोई नामित सदस्य उस दिनांक से चार महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, जिस दिन वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है।

(d) कोई निर्वाचित सांसद स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग दे।

75. प्रोटेम अध्यक्ष (Speaker pro tem) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वह नव-निर्वाचित लोक सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता/करती है।
2. उसे नव-निर्वाचित लोक सभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
3. वह नव-निर्वाचित लोक सभा सदस्यों को शपथ दिलाता/दिलाती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

76. भारत में प्रधानमंत्री के पद/संस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता।
2. संविधान यह आवश्यक करता है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व व्यक्ति को लोक सभा में अपना बहुमत सिद्ध करना चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, और न ही 2

71. Which of the following options best defines "predatory pricing", sometimes seen in news in context of market competition?
(a) Selling a product below cost to eliminate competitors and gain market dominance.
(b) Increasing prices in a cartel to maximize joint profits.
(c) Charging different prices from different consumers for the same product.
(d) Selling imported goods at higher prices than domestic products to protect local industry.

72. Which of the following pairs are correctly matched?

	Exercise	*Associated Countries with India*	*Force involved*
1.	Tropex	Singapore	Navy
2.	Dharma Guardian	Japan	Army
3.	Komodo	Indonesia	Airforce

Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 only
(b) 1 and 3
(c) 2 only
(d) 3 only

73. Consider the following statements regarding the New Development Bank (NDB):
1. Membership of the NDB is open to countries outside the BRICS group.
2. The NDB does not maintain a permanent headquarters, unlike many other multilateral development banks.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

74. Under the provisions of the Tenth Schedule of the Constitution, which of the following situations will ***not*** result in disqualification of a Member of Parliament?
(a) An elected independent member joins a political party within six months.
(b) A member votes against party whip without prior permission
(c) A nominated member joins a political party after four months from the date on which he takes his seat in the House.
(d) An elected member of Parliament voluntarily gives up his membership of such political party

75. With reference to the Speaker pro tem, consider the following statements:
1. He/She presides over the first sitting of the newly elected Lok Sabha.
2. He/She is elected by the newly elected members of the Lok Sabha.
3. He/She administers the oath to newly elected members of Lok Sabha.

Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

76. With reference to the office/institution of the Prime Minister in India, consider the following statements:
1. A person who is not a member of either House of Parliament can not be appointed as Prime Minister.
2. The Constitution requires that a person must prove his majority in the Lok Sabha before he is appointed as the Prime Minister.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

77. संसद में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

	प्रश्नों के प्रकार	आवश्यक उत्तर	पूरक प्रश्न
I.	तारांकित (Starred)	मौखिक उत्तर	अनुमति नहीं
II.	अतारांकित (Unstarred)	लिखित उत्तर	अनुमति है
III.	अल्प सूचना (Short Notice)	लिखित उत्तर	अनुमति है

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?

(a) केवल I और II
(b) केवल II और III
(c) I, II और III
(d) इनमें से कोई नहीं

78. निम्नलिखित में से कौन-सा/से राज्य विधान सभा के सदस्यों के अयोग्य होने के कारणों के रूप में भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं?

1. किसी राज्य सरकार के तहत किसी लाभकारी पद (Office of Profit) पर होना
2. मानसिक रूप से अस्वस्थ होना और इसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया जाना
3. किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना और दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

79. भारत की संसद में बजटीय प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विनियोग विधेयक में कर लगाने के लिए सरकार के प्रस्ताव शामिल होते हैं।
2. विनियोग विधेयक उस समय पेश किया जाता है और पारित किया जाता है जब अनुदान के लिए मांगों (Demands for Grants) पर मतदान पूर्ण हो जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2
(d) न तो 1 और न ही 2

80. निम्नलिखित मानवाधिकार संधियों पर विचार कीजिए:

1. यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड के खिलाफ संधि।
2. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि।
3. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता।
4. महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों की समाप्ति पर संधि।
5. बच्चों के अधिकारों पर संधि।

उपर्युक्त में से कितनी संधियों की भारत ने पुष्टि की है?

(a) केवल दो
(b) केवल तीन
(c) केवल चार
(d) सभी पाँच

81. भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से "लेमडक (lame duck)" शब्द सबसे सही रूप से किसे दर्शाता है?

(a) संसद का ऐसा सत्र जिसमें बार-बार स्थगन के कारण कोई विधायी कार्य नहीं होता।
(b) पिछली लोक सभा के सदस्य जो नई लोक सभा में दोबारा निर्वाचित नहीं हो सके।
(c) ऐसा विधेयक जिसे संसद के एक सदन ने पारित कर दिया हो लेकिन दूसरे सदन में छह महीने से अधिक समय तक लंबित हो।
(d) ऐसी स्थिति जिसमें सत्तारूढ़ दल के पास लोक सभा में बहुमत है लेकिन राज्य सभा में नहीं, जिससे कुछ विधेयक पारित करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

77. Consider the following pairs with respect to various types of questions during Question hour of the Parliament:

	Types of Questions	*Answer Required*	*Supplementary Questions*
I.	Starred	Oral Answer	Not Allowed
II.	Unstarred	Written Answer	Allowed
III.	Short Notice	Written Answer	Allowed

Which of the above pairs are correctly matched?
(a) I and II only
(b) II and III only
(c) I, II and III
(d) None of the above

78. Which of the following are explicitly mentioned in the Constitution of India as grounds for disqualification of a member of the State Legislature?
1. Holding any office of profit under the Government of any State.
2. Being of unsound mind and so declared by a competent court.
3. Being convicted for any offence and sentenced to imprisonment of two years or more.

Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

79. Consider the following statements regarding the budgetary process in the Parliament of India:
1. The Appropriation Bill contains the Government's proposals for the imposition of taxes.
2. The Appropriation Bill is introduced and passed after the Voting on Demands for Grants has been completed.

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

80. Consider the following Human Rights Conventions:
1. The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
2. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
3. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
4. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
5. The Convention on the Rights of the Child.

How many of the above mentioned Conventions have been ratified by India?
(a) Only two
(b) Only three
(c) Only four
(d) All five

81. Which of the following best describes the term "lame duck" in the context of the Indian Parliament?
(a) A session of Parliament in which no legislative business is transacted due to repeated adjournments.
(b) Members of the previous Lok Sabha who could not get re-elected to the new Lok Sabha.
(c) A Bill that has been passed by one House of Parliament but is pending in the other House for more than six months.
(d) A situation where the ruling party has a majority in the Lok Sabha but not in the Rajya Sabha, limiting its ability to pass certain Bills.

82. जब किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. यदि यह एक धन विधेयक (Money Bill) है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल को इसे पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेजने का निर्देश दे सकते हैं।
2. यदि यह एक साधारण विधेयक (Ordinary Bill) है और पुनर्विचार के बाद राज्य विधानमंडल इसे पुनः पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति पर संवैधानिक रूप से इसे अपनी स्वीकृति देने की बाध्यता होती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

83. सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. SEBCs की केंद्रीय सूची संसद द्वारा घोषित की जाती है।
2. SEBCs की केंद्रीय सूची में कोई भी संशोधन केवल राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

84. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice - ICJ) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र प्रमुख अंग है, जो न्यूयॉर्क शहर में स्थित नहीं है।
2. ICJ को किसी विवाद पर अधिकार-क्षेत्र (Jurisdiction) तभी प्राप्त होता है, जब दोनों पक्ष इसकी सहमति दें।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

85. निम्नलिखित में से कौन-से देश लेबनान के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं?

1. तुर्की
2. इज़राइल
3. इराक़
4. सीरिया
5. ईरान

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 2, 3 और 5
(d) केवल 1, 3 और 4

86. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन "त्रिशंकु संसद" (Hung Parliament) शब्द को सही प्रकार से परिभाषित करता है?

(a) ऐसी स्थिति, जिसमें कोई भी एकल राजनीतिक दल या पूर्व-निर्वाचन गठबंधन, स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत सीटें हासिल नहीं करता।
(b) ऐसी स्थिति, जो निवर्तमान संसद के विघटन और नव-निर्वाचित संसद के आह्वान के मध्य उत्पन्न होती है।
(c) ऐसी स्थिति, जिसमें संसद के दोनों सदन किसी संवैधानिक संशोधन पर सहमति नहीं बना पाते।
(d) ऐसी स्थिति, जिसमें संसद के अध्यक्ष या सभापति बहस के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो जाते हैं।

87. हाल ही में समाचारों में देखा गया 'धिम्सा (Dhimsa)' नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जनजातीय समुदायों द्वारा किया जाता है?

(a) राजस्थान
(b) आंध्र प्रदेश
(c) अरुणाचल प्रदेश
(d) लद्दाख

88. राज्य के महाधिवक्ता (Advocate-General) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफ़ारिश पर की जाती है।

82. When a Bill passed by a State Legislature is reserved by the Governor for the consideration of the President, which of the following statements is/are correct?

1. If it is a Money Bill, the President may direct the Governor to return it to the State Legislature for reconsideration.
2. If it is an Ordinary Bill and is passed again by the State Legislature after reconsideration, the President is constitutionally bound to give his assent.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

83. Consider the following statements with reference to Socially and Educationally Backward Classes (SEBCs):

1. The Central list of the SEBCs is declared by the Parliament.
2. Any modification to the central list of the SEBCs can be done only by the President.

Which of the statements given above is/are correct ?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

84. With reference to International Court of Justice (ICJ), consider the following statements :

1. It is the only principal organ of the United Nations that is not located in New York City.
2. The ICJ exercises its jurisdiction over a dispute only if both parties consent to it.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

85. Which of the following countries share a land border with Lebanon?

1. Turkey
2. Israel
3. Iraq
4. Syria
5. Iran

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1, 2 and 4 only
(b) 2 and 4 only
(c) 2, 3 and 5 only
(d) 1, 3 and 4 only

86. Which of the following statements correctly defines the term "Hung Parliament"?

(a) A situation where no single political party or pre-poll alliance secures a majority of seats required to form the government independently.
(b) A situation arising between the dissolution of the outgoing Parliament and the convening of the newly elected Parliament.
(c) A situation where both Houses of Parliament fail to agree on a constitutional amendment.
(d) A situation where the presiding officer of the Parliament fails to maintain order during debates.

87. Dhimsa' dance, recently seen in news, is mainly performed by the tribal communities of which of the following regions?

(a) Rajasthan
(b) Andhra Pradesh
(c) Arunachal Pradesh
(d) Ladakh

88. With reference to the Advocate-General for the State, consider the following statements:

1. He is appointed by the President of India on the recommendation of the Governor of the concerned state.

2. अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में, उन्हें भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त होता है।
3. वह छह वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक पद पर रहते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही नहीं हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

89. भारत के उपराष्ट्रपति के पद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उपराष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक पद पर रहते हैं, भले ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया हो।
2. उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय भारतीय निर्वाचन आयोग करता है।
3. राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते समय, उपराष्ट्रपति को मत बराबरी की स्थिति में कास्टिंग वोट (Casting Vote) का अधिकार नहीं होता।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) इनमें से कोई नहीं।

90. भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के किसी ऐसे प्रावधान में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता जिसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की आवश्यकता हो।
2. जब लोक सभा को स्थगित (Prorogued) कर दिया गया हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता।
3. राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

91. लोक सभा में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षित सीटों का वर्तमान आवंटन, निम्नलिखित में से किस जनगणना पर आधारित है?
(a) 1971 की जनगणना
(b) 2011 की जनगणना
(c) 1991 की जनगणना
(d) 2001 की जनगणना

92. भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव के मध्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध लाया जा सकता है।
2. निंदा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही पेश किया जा सकता है।
3. यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद् के लिए इस्तीफ़ा देना बाध्यकारी नहीं होता, जबकि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद् को सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा देना पड़ता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

93. राज्यपाल के पद की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यपाल के वेतन और भत्ते संसद द्वारा, विधि के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं।
2. यदि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो वेतन और भत्ते उन राज्यों के बीच, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में, बाँटे जाएँगे।
3. राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) पर भारित होते हैं।

2. In the performance of his duties, he shall have right of audience in all courts in the territory of India.
3. He holds office for a period of six years or upto the age of 62 years, whichever is earlier.

Which of the statements given above are ***not*** correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

89. With reference to the office of the Vice-President of India, consider the following statements:
1. The Vice-president continues in office until the successor assumes charge, even if the term has expired.
2. Disputes regarding the election of the Vice-President are decided by the Election Commission of India.
3. While acting as Chairperson of the Rajya Sabha, the Vice-President does not have a casting vote in case of a tie.

How many of the above statements are correct?
(a) Only one
(b) Only two
(c) All three
(d) None of the above

90. With reference to power of the President of India to promulgate ordinances, consider the following statements:
1. An ordinance cannot be issued to amend a provision of the Constitution that requires amendment under Article 368.
2. Ordinance can not be issued by the President when Lok Sabha has been prorogued.
3. Ordinance may be withdrawn at any time by the President.

How many of the statements given above are correct?
(a) Only one
(b) Only two
(c) All three
(d) None

91. The present allocation of seats in the Lok Sabha reserved for the Scheduled Castes (SCs) and the Scheduled Tribes (STs) is based on which of the following Census?
(a) 1971 Census
(b) 2011 Census
(c) 1991 Census
(d) 2001 Census

92. Consider the following statements regarding the difference between a Censure Motion and a No-confidence Motion in the Indian Parliament:
1. A Censure Motion can be moved against an individual minister, whereas a No-confidence Motion can only be moved against the entire Council of Ministers.
2. A Censure Motion can be introduced in either House of Parliament, whereas a No-confidence Motion can be introduced only in the Lok Sabha.
3. If a Censure Motion is passed, the Council of Ministers is not bound to resign, whereas if a No-confidence Motion is passed, the Council of Ministers must resign collectively.

Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

93. With reference to the conditions of office of the Governor, consider the following statements:
1. The emoluments, and allowances of the Governor are determined by Parliament by law.
2. If the same person is appointed as Governor of two or more States, the emoluments and allowances shall be shared between such States in the proportion determined by the President.
3. The emoluments and allowances of the Governor are charged on the Consolidated Fund of State.

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2
(d) 1, 2 और 3

94. निम्नलिखित में से कौन-से निकाय राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाए जा सकते हैं?
1. राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner)
2. राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य (Members of State Human Rights Commission)
3. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य (Members of State Public Service Commission)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

95. भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई विशेष आधार का उल्लेख नहीं है।
2. हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए
4. संसद के किसी भी सदन के नामित सदस्य, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, फिर भी उनके महाभियोग में भाग ले सकते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

96. भारत में अंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित किया गया है।
2. राष्ट्रपति को जब भी आवश्यक समझा जाए, इसे स्थापित करने का अधिकार है।
3. यह एक स्थायी निकाय है जिसकी बैठक प्रतिवर्ष कम से कम एक बार होती है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

97. भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदस्य के रूप में नामित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है।
2. कोई व्यक्ति तभी लोक सभा का सदस्य बनने के लिए पात्र है, जब वह भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो।
3. लोक सभा में राज्यों को इस प्रकार सीटें आवंटित की जाती हैं कि, यथासंभव, प्रत्येक राज्य में सीटों और जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए समान हो।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 2 और 3

98. निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व भारत के संविधान की रक्षा और बचाव की शपथ लेनी होगी?
(a) प्रधानमंत्री
(b) संसद के सदस्य
(c) किसी राज्य के राज्यपाल
(d) लोकसभा के अध्यक्ष

99. यदि राज्यसभा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत एक प्रस्ताव पास करती है, जिसमें,संसद को राज्य सूची (State List) के किसी विषय पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक बताया गया हो, तो निम्नलिखित में से कौन-से निहितार्थ लागू होते हैं?
1. संसद संवैधानिक रूप से बाध्य हो जाती है कि वह प्रस्ताव में निर्दिष्ट विषय पर पूरे भारत या किसी भाग के लिए कानून बनाए।

Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 only
(d) 1, 2 and 3

94. Which of the following bodies are appointed by the Governor of a state but can be removed only by the President of India?
1. State Election Commissioner
2. Members of State Human Rights Commission
3. Members of State Public Service Commission

Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

95. With reference to the removal of Vice President of India, consider the following statements:
1. Constitution does not mention any specific ground for the removal of the Vice-President.
2. The resolution for removal can be introduced in any House of the Parliament.
3. The resolution for removal must be passed by a majority of all the then members of both Houses of the Parliament.
4. The nominated members of either House of Parliament can participate in the impeachment, although they do not participate in his election.

How many of the statements given above are correct?
(a) Only one
(b) Only two
(c) Only three
(d) All four

96. With reference to the Inter-State Council in India, consider the following statements:
1. It is a constitutional body set up under Article 263 of the Constitution.
2. The President is empowered to establish it whenever considered necessary.
3. It is a permanent body that meets at least once every year.

Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3

97. With reference to the Indian Parliament, consider the following statements:
1. The minimum age to be eligible for nomination by the President as a member of Parliament is 35 years.
2. A person is qualified to become a member of the Lok Sabha only if he is an elector for any Parliamentary constituency in India.
3. Seats in the Lok Sabha are allotted to States in such a manner that, as far as practicable, the ratio between the number of seats and the population of each State is the same for all States.

Which of the statements given above are correct?
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 2 and 3 only

98. Which of the following constitutional functionaries must take an oath to protect and defend the Constitution of India before entering their office?
(a) Prime Minister
(b) Members of Parliament
(c) Governor of a State
(d) Speaker of Lok Sabha

99. If the Rajya Sabha passes a resolution under Article 249 declaring it necessary in the national interest for Parliament to make laws on a matter in the State List, which of the following implications follow?
1. Parliament becomes constitutionally bound to legislate on the matter specified in the resolution for the whole or any part of India.

2. संसद द्वारा ऐसे प्रस्ताव के अंतर्गत बनाया गया कानून स्थायी रूप से लागू रहेगा जब तक कि संसद उसे रद्द न करे।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2
(d) न तो 1 और न 2

100. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I:

संसद सदस्य (MPs) को सदन के सत्र के दौरान आपराधिक मामलों में गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता।

कथन-II:

जब तक संसद किसी कानून द्वारा परिभाषित न करे, सांसदों के विशेषाधिकार वही रहेंगे, जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के लागू होने से ठीक पहले प्रभावी थे।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन-I सही है, किंतु कथन-II गलत है।
(d) कथन-I गलत है, किंतु कथन-II सही है।

2. A law made by Parliament under such a resolution will remain in force permanently unless repealed by Parliament.

Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

100. Consider the following statements:

Statement-I:

Members of Parliament (MPs) cannot be arrested in criminal cases during the session of the House.

Statement-II:

Until defined by Parliament by law, privileges of the MPs are the same as those in force immediately before the commencement of the 44th Constitutional Amendment Act, 1978.

Which one of the following is correct in respect of the above statements?
(a) Both Statement-I and Statement-II are correct and Statement-II is the correct explanation for Statement-I
(b) Both Statement-I and Statement-II are correct, but Statement-II is not the correct explanation for Statement-I
(c) Statement-I is correct, but Statement-II is incorrect
(d) Statement-I is incorrect, but Statement-II is correct

Space for Rough Work

NEXT IAS

GENERAL STUDIES

CSE Prelims Test Series (PTS): 2026

17th August, 2026 | Test-2 [Sectional Test]

Answer Key

1. (c)	21. (c)	41. (c)	61. (b)	81. (b)
2. (b)	22. (b)	42. (b)	62. (b)	82. (d)
3. (b)	23. (b)	43. (c)	63. (d)	83. (d)
4. (a)	24. (d)	44. (c)	64. (c)	84. (c)
5. (d)	25. (c)	45. (a)	65. (a)	85. (b)
6. (b)	26. (c)	46. (d)	66. (c)	86. (a)
7. (c)	27. (b)	47. (b)	67. (b)	87. (b)
8. (c)	28. (a)	48. (c)	68. (d)	88. (d)
9. (a)	29. (a)	49. (c)	69. (b)	89. (a)
10. (a)	30. (b)	50. (b)	70. (d)	90. (b)
11. (c)	31. (b)	51. (a)	71. (a)	91. (d)
12. (b)	32. (c)	52. (a)	72. (c)	92. (c)
13. (d)	33. (b)	53. (c)	73. (a)	93. (d)
14. (a)	34. (d)	54. (c)	74. (c)	94. (d)
15. (b)	35. (a)	55. (b)	75. (c)	95. (a)
16. (a)	36. (c)	56. (d)	76. (d)	96. (a)
17. (a)	37. (a)	57. (d)	77. (d)	97. (d)
18. (a)	38. (c)	58. (c)	78. (a)	98. (c)
19. (a)	39. (d)	59. (d)	79. (b)	99. (d)
20. (c)	40. (c)	60. (a)	80. (c)	100.(d)

DELHI CENTRE:
Vivekananda House
6-B, Pusa Road, Metro Pillar No. 111,
Near Karol Bagh Metro
New Delhi-110060
Phone: 8081300200

DELHI CENTRE:
Tagore House
27-B, Pusa Road, Metro Pillar No. 118,
Near Karol Bagh Metro
New Delhi-110060
Phone: 8081300200

DELHI CENTRE:
Mukherjee Nagar
637, Banda Bahadur Marg,
Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phone: 9311667076

PRAYAGRAJ CENTRE:
31/31 Sardar Patel Marg,
Civil Lines, Prayagraj
Uttar Pradesh-211001
Phone: 9958857757

JAIPUR CENTRE:
Plot No. 6 & 7, 3rd Floor,
Sree Gopal Nagar,
Gopalpura Bypass, Jaipur-302015
Phone: 9358200511

© Copyright: NEXT IAS

General Studies
Test-2

Sectional Test:
Polity, Governance & Current Affairs

1. (c)

- **Statement 1 is not correct but Statement 2 is correct:** The value of the vote of a Member of Parliament (MP), whether from Lok Sabha or Rajya Sabha and from any state, is calculated by dividing the total value of votes of all MLAs of all states by the total number of elected members of both Houses of Parliament. **Thus, every MP's vote carries equal value, regardless of the state they represent or the House they belong to.**

$$\text{Value of vote of an MP} = \frac{\text{Total value of votes of all MLAs}}{\text{Total elected MPs (LS + RS)}}$$

- **Statement 3 is correct:** The value of the vote of an MLA is determined by the population of the state divided by the number of elected MLAs (multiplied by 1/1000). The value of an MP's vote is generally higher than that of an MLA, because the sum total value assigned to all MLAs is divided among comparatively fewer MPs. Therefore, a Lok Sabha member from Rajasthan will have a vote whose value is higher than an MLA from Rajasthan. The value of vote of each MP in the country is currently 700. Whereas, the value of vote of MLA varies from 7 (Sikkim) to 208 (Uttar Pradesh). The value of vote of a MLA from Rajasthan is currently 129.

$$\text{Value of vote of an MLA} = \frac{\text{Population of State (1971 Census)}}{\text{Total elected MLAs of State} \times 1000}$$

- **Statement 4 is correct:** As stated above, **The value of an MLA's vote depends on the population of the respective state and the number of MLAs therein, leading to varying vote values between states**. Since Uttar Pradesh and Bihar differ in population and number of MLAs, the vote value for their MLAs cannot be the same.
- **Additional information:** Article 55 of the Constitution of India states that:
  - There shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.
  - There should be parity between the States as a whole and the Union.

2. (b)

- **Statements 1 and 2 are correct:** Article 164(1A) of the Constitution provides that the total number of Ministers, **including the Chief Minister**, in the Council of Ministers in a State **shall not exceed fifteen per cent of the total number of members of the Legislative Assembly of that State**. Provided that the number of Ministers, including the Chief Minister in a State **shall not be less than twelve. This provision was added by the 91st Amendment Act of 2003.**
- **Statement 3 is not correct:** Article 164(1) specifies that a dedicated Minister for Tribal Welfare is provided only in the States of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, and Odisha. It is not applicable to every state having areas covered under the Fifth Schedule. The minister in charge of tribal welfare in these states may also be given the charge of the welfare of the Scheduled Castes and backward classes or any other work. (**Note:** 94th Amendment Act of 2006 removed the state of Bihar from this provision).
- **Additional information:**
  - Chief Minister is appointed by the Governor, and other Ministers are appointed on the advice of the Chief Minister.
  - The State Council of ministers (CoM) shall hold office during the pleasure of the Governor.
  - State CoM is collectively responsible to the Legislative Assembly of the State.
  - The salaries and allowances of the State CoM are determined by the state legislature, and until so determined, as per the Second Schedule of the Constitution.

3. (b)

- **Statement 1 is not correct**: The Chief Minister can be a member of either House of the State Legislature — the Legislative Assembly (lower house) or the Legislative Council (upper house), wherever such a council exists. A person who

is not a member of either House of the State Legislature can still be appointed as a minister. However, he must secure membership in either House (through election or nomination) within six months; otherwise, he will automatically lose his position as minister.

- **Statement 2 is correct:** The Chief Minister as well as other ministers hold office during the pleasure of the Governor.

4. (a)

- **Option (a) is the correct answer:** Among the given options, only the indirectly elected members of the Rajya Sabha participate in all three elections mentioned —President of India, the Vice-President of India, as well as the Deputy Chairperson of the Rajya Sabha.

Category of Legislator	Election of President	Election of Vice-President	Election of Deputy Chairperson, Rajya Sabha
Indirectly elected members of Rajya Sabha	Yes	Yes	Yes
Directly elected members of Lok Sabha	Yes	Yes	No
Nominated members of Rajya Sabha	No	Yes	Yes
Directly elected members of Legislative Assembly of UT Delhi	Yes	No	No

5. (d)

- **Statement-I is not correct:** The quorum for conducting proceedings in the Lok Sabha is one-tenth of the total number of members, including the presiding officer. In the 18th Lok Sabha, which has 543 members, one-tenth is 54.3, rounded up to 55. Since the Statement mentions 54 members, other than the Speaker, are present, the total comes to 55 including the Speaker. Therefore, proceedings can be conducted and Statement-I is not correct.
- **Statement-II is correct:** The Quorum to constitute a meeting of either House of Parliament is indeed one-tenth of the total number of members of the House, including the presiding officer. It implies the Quorum is 55 members for Lok Sabha and 25 members of Rajya Sabha.
- **Additional information:**
  - **Quorum in Joint sitting:** The quorum to constitute a joint sitting is one-tenth of the total number of members of the two Houses.
  - **Quorum in State legislature:** Until the State legislature otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of a House of State legislature shall be ten members or one-tenth of the total number of members of the House, whichever is greater.
  - **Absence of Quorum:** If a meeting of the House lacks the required quorum, it is the duty of the presiding officer to either adjourn the sitting or suspend it until the quorum is met.

6. (b)

- **Statements 1 and 2 are correct:** As per Article 80(1) of the Constitution of India, the total number of seats in the Rajya Sabha (Council of States) shall not exceed 250. This includes up to 12 nominated members and not more than 238 representatives of the States and Union territories.
  - The present strength of Rajya Sabha, however, is 245, out of which 233 are representatives of the States and Union territories of Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir and 12 are nominated by the President.
- **Statement 3 is not correct:** According to Article 80(4), the representatives of each State in the Rajya Sabha are elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State, not by both the Legislative Assembly and Legislative Council.
- **Statement 4 is not correct:** The Fourth Schedule to the Constitution provides for allocation of seats to the States and Union Territories in Rajya Sabha. The allocation of seats is made on the basis of the population of each State. However, Union territories do not have equal representation. Currently, only the UTs of of Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir are represented in the Rajya Sabha.
- **Additional information:**
  - **Election of representatives of State in RS:** To be elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State in accordance with the system of proportional

representation by means of the single transferable vote.

- **Election of representatives of UTs in RS:** They shall be chosen in such manner as Parliament may by law prescribe.
- **Nomination of 12 members:** Nominated by the President are persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as literature, science, art and social service.

7 (c)

- **Option (c) is the correct answer:** Criminal Procedure Code (Cr.P.C.) and now Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) classifies the all the crimes into two categories: (i) Cognizable and (ii) Non cognizable. A Cognizable offence or case is defined as the one which an officer in-charge of a police station may investigate without the order of a magistrate and effect arrest without warrant. The Police have a direct responsibility to take immediate action on the receipt of a complaint or of credible information in such crimes, visit the scene of the crime, investigate the facts, apprehend the offender and arraign him before a Court of law having jurisdiction over the matter. Cognizable offences are usually serious in nature
- Non-Cognizable crimes are defined as those which cannot be investigated by police without the order of a competent magistrate. The Police do not initiate investigation in Non-Cognizable crimes except with magisterial permission. Non-cognizable offences are not as serious in nature as cognizable offences.
- **Additional information:**
  - **Compoundable offence:** A compoundable offence is one in which the aggrieved person (the complainant) decides to dismiss the accusations against the accused. The result of compounding an offence is essentially the dismissal of accusations made against the accused.

8. (c)

- The **qualifications for membership of the State Legislature** are provided for in **Article 173** of the Constitution. The **additional qualifications** are mentioned in the **Representation of People Act (1951)**.
- **Statement 1 is correct:** According to the RPA, 1951, a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Council of a State to be filled by election unless he is an **elector for any Assembly constituency in the concerned State.** (Same provision exists for qualification to be a member of the State legislative assembly).
- **Statement 2 is correct:** According to the Article 171 of the Constitution, the members to be nominated by the Governor in the Legislative Council shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely:— Literature, science, art, co-operative movement and social service. According to RPA, 1951, a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Council of a State to be filled by nomination by the Governor unless he is ordinarily resident in the State.

9. (a)

- **1 and 3 are correct: Article 88** of the Constitution says that **every Minister** and the **Attorney-General of India** shall have the **right to speak in**, and otherwise to **take part in the proceedings of either House,** any **joint sitting** of the Houses, and any **committee of Parliament** of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote.
- **2 is not correct:** Though the President is an integral part of Parliament (since a bill passed by both the Houses cannot become law without his assent), he is not a member of either House and hence does not have a right to sit in the Parliament to attend its meetings or take part in its proceedings. However, please note that under Article 86 of the Constitution, the President may address either House of Parliament or both Houses assembled together. Similarly, under Article 87, the President shall address both Houses of Parliament assembled together at the commencement of the first session after each general election to the Lok Sabha and at the commencement of the first session of each year.
- **4 is not correct**: The Speaker presides over the Lok Sabha and is a member of that House. They can speak and vote in the Lok Sabha, but not in the Rajya Sabha.
- **5 is not correct:** The Deputy Chairperson presides over the Rajya Sabha and is a member

of that House. They can speak and vote in the Rajya Sabha, but not in the Lok Sabha.

10. (a)

- **Statement 1 is correct:** As per **Article 203** of the Constitution, **no demand for a grant shall be made except on the recommendation of the Governor**.
- **Statement 2 is correct:** Judges of the High Court are appointed in accordance with **Article 217** by the **President.** The present method as evolved with the *Three Judges Cases* in which it was held that the President shall appoint a Judge of a High Court **after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the state**, and in the case of a Judge (not Chief Justice), also the Chief Justice of the High Court.
- **Statement 3 is not correct:** Although the chairman and members of a SPSC are appointed by the governor, they can be removed only by the president (and not by the governor). As per **Article 317,** the **president can remove the members of SPSC on the same grounds and in the same manner as he can remove a chairman or a member of the UPSC.** The grounds include the following:
  - ♦ If he is adjudged an insolvent (i.e., has gone bankrupt); or
  - ♦ If he engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office; or
  - ♦ If he is, in the opinion of the president, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body.

11. (c)

- **Statement 1 is not correct:** Article 356 of the Constitution of India gives the President of India the power to impose President's rule on a state on the advice of the Union Council of Ministers. It is not a discretionary power of the President.
  - ♦ However, note that when the Governor has to recommend for the imposition of the President's Rule in the state, it is his discretionary power.
- **Statement 2 is not correct:** Under Article 72, the President has the power to grant pardons, reprieves, respites, or remissions. However, this power is exercised on the aid and advice of the Council of Ministers.
  - ♦ Note that in the United States of America (USA), the President exercises the pardoning power independently without the advice of the Council of Ministers.
- **Statement 3 is correct:** 44th Constitutional Amendment Act of 1978 authorised the President to ask the Council of Ministers to reconsider their advice, exercising discretion in the process. However, he 'shall' act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. Although the Council can resend the same advice, the President's request for reconsideration carries significant weight.

12. (b)

- The principle of collective responsibility is a cornerstone of parliamentary democracy in India, and it ensures the government remains accountable to the legislature.
- **Statement 1 is correct:** It is a direct implication of collective responsibility. If the government loses the confidence of the majority in the Lok Sabha, it can no longer function and must resign. This is often demonstrated through a vote of no-confidence.
- **Statement 2 is correct:** It also directly follows from the principle of collective responsibility. It means that the entire Council of Ministers is a single entity in the eyes of the Lok Sabha. Decisions are made jointly, and therefore, all ministers are responsible for those decisions, even if they personally disagreed with them during the internal discussions. That is why it is said for the Council of ministers that "they swim together and they sink together".
- **Statement 3 is correct:** A no-confidence motion is the primary mechanism through which the Lok Sabha expresses its loss of confidence in the Council of Ministers. As stated above, the entire Council, including the Prime Minister, must resign if it loses the confidence of the majority in the Lok Sabha.
- **Statement 4 is not correct:** Loss of majority by the Council of Ministers **does not mandate dissolution of the Lok Sabha**. In such cases, the **President may invite another party or coalition** to form the government. **Dissolution of the House is not an automatic** consequence.

13. (d)

- **1, 2 and 3 are correct:** According to the Article 78 of the Constitution of India, It shall be the duty of the Prime Minister—
  (a) to **communicate to the President all decisions of the Council of Ministers** relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation;
  (b) to furnish such **information relating to the administration of the affairs of the Union** and proposals for legislation as the President may call for; and
  (c) if the President so requires, to **submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister** but which has not been considered by the Council.

14. (a)

- **Statement 1 is correct: Article 163** explicitly allows the **Governor to act in his discretion** in certain situations as permitted by the Constitution. In contrast, the **President is always expected to act on the aid and advice of the Council of Ministers** under Article 74. Thus, there is **no constitutional provision for discretionary powers** of the President similar to the Governor (Though the President does exercise certain **situational** discretionary powers).
- **Statement 2 is not correct:** The **42nd Amendment (1976) made the advice of the Council of Ministers binding on the President**. However, it did **not make such advice binding on the Governor**. The Governor still retains discretionary powers under Article 163 in specific circumstances.

15. (b)

- **About Legislative Council:** It is the **upper house in the bicameral state legislature**s. Currently, only **six states** in India have a Legislative Council: Uttar Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana, and Andhra Pradesh.
- **Statement 1 and 2 are correct**: The **composition of State Legislative Council** is as follows:
  - About **one-third** are **elected by the members of local bodies** in the state like municipalities, district boards, etc. Thus, **Statement 1 is correct.**
  - About **one-third** are elected by the **members of the legislative assembly** of the state from amongst persons who are not members of the assembly. Thus, **Statement 2 is correct.**
  - About one-twelfth are elected by graduates of three years standing and residing within the state,
  - About **one-twelfth** are elected by **teachers of three years standing** in the state, **not lower** in standard **than secondary school**. Thus, **Statement 3 is not correct.**
  - About **one-sixth** of the total number of members are **nominated by the governor** from amongst persons who have a **special knowledge** or practical experience of **literature, science, art, cooperative movement and social service**. Thus, **Statement 4 is not correct.**

16. (a)

- **Statement 1 is correct**: The European Free Trade Association (EFTA) is the **intergovernmental organisation of Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland**. It was set up in 1960 by its then seven Member States for the promotion of free trade and economic integration between its members. EFTA is one important economic block out of the three (other two - EU &UK) in Europe. **Among EFTA countries, Switzerland is the largest trading partner of India followed by Norway.**
- **Statement 2 is not correct:** The recently concluded India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA), positions EFTA as the **first European bloc to formalize a trade pact with India.**
- **Additional information:** Important highlights of the India-EFTA TEPA:
  - For the first time, India is signing an FTA with four developed nations - an important economic bloc in Europe.
  - For the first time in history of FTAs, binding commitment of $100 bn investment and 1 million direct jobs in the next 15 years has been given.
- EFTA has committed to promote investments with the aim to increase the stock of foreign direct

investments by USD 100 billion in India in the next 15 years, and to facilitate the generation of 1 million direct employment in India, through such investments. The investments do not cover foreign portfolio investment.

- For the first ever time in the history of FTAs, a legal commitment is being made about promoting target-oriented investment and creation of jobs.
- The agreement comprises of 14 chapters with main focus on market access related to goods, rules of origin, trade facilitation, trade remedies, sanitary and phytosanitary measures, technical barriers to trade, investment promotion, market access on services, intellectual property rights, trade and sustainable development and other legal and horizontal provisions.

17. (a)

- **Context:** Recently, the concept of "Jevons paradox" is being much talked about in the world of Artificial intelligence. Microsoft CEO Satya Nadella has also highlighted the emergence of this 160-year-old economics paradox in the field of AI.
- **Option (a) is the correct answer:** The Jevons Paradox, proposed by economist William Stanley Jevons in 1865, states that improvements in the efficiency of using a resource often lead to an increase, rather than a decrease, in the total consumption of that resource. This happens because increased efficiency lowers the effective cost of using the resource, which increases demand and thus total usage.
- For example, more fuel-efficient vehicles reduce the cost of driving, which encourages more travel, leading to increased fuel consumption overall despite efficiency gains.
- This paradox challenges the common assumption that efficiency improvements always conserve resources and has significant implications for environmental and energy policies.

18. (a)

- **Statement 1 is correct:** According to Article 76, the Attorney General of India does not have a fixed tenure. He holds hold office during the pleasure of the President
- **Statement 2 is not correct:** Though conventionally the Attorney-General of India resigns when the Union Council of ministers resigns as he is appointed by it, he does not **necessarily need to resign as per the Constitution.**
- **Statement 3 is not correct:** Attorney General is not a full-time counsel for the Government and is not considered a government servant. Therefore, he is allowed to engage in private legal practice.
- **Additional information about Attorney General:**
  - Without the permission of the Government of India, he cannot accept the post of director in any company or corporation.
  - He must not advise or represent cases against the Government of India.
  - He cannot defend accused persons in criminal prosecutions unless permitted by the Government of India.

19. (a)

- **1 and 4 are correct:** Under Article 108 of the Constitution, the President can summon a joint sitting of both Houses of Parliament if:
  - One House passes an ordinary bill but the other House rejects it outright.
  - Houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the Bill
  - More than six months have elapsed from the date of receipt of the bill by the other House without the bill being passed by it.
- **Statement 2 is not correct:** Article 108 explicitly excludes Money Bills from the scope of joint sittings. Disagreements on amendments to a Money Bill cannot result in a joint sitting of the Houses. Rajya Sabha has no power to amend or reject a money bill. Moreover, RS can not even delay the money bill for more than 14 days. So, there can not be a deadlock between the two Houses over a money bill.
- **Statement 3 is not correct:** The provision for joint sittings does not apply to Constitution Amendment Bills. Article 108 only applies to ordinary bills, not Money Bills or Constitutional Amendment Bills. Constitution Amendment Bills need to be passed by the both Houses separately.

20. (c)

- **Option (c) is the correct answer:** 91st Constitutional Amendment Act, 2003 mandated

that the total number of ministers, **including the Prime Minister**, in the Union Council of Ministers shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha.

21. (c)

- **Statement 1 is correct:** On the recommendation of the Rules Committee of the Lok Sabha, 17 Departmentally-Related Standing Committees (DRSCs) were set up in the Parliament in 1993. In 2004, seven more such committees were setup, thus increasing their number from 17 to 24. The main objective of the standing committees is to secure more accountability of the Executive (i.e., the Council of Ministers) to the Parliament, particularly financial accountability. They also assist the Parliament in debating the budget more effectively. They also examine Bills referred to them by Parliament and analyse other relevant policy issues.
- **Statement 2 is correct:** Each standing committee consists of 31 members (21 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha).
- **Statement 3 is not correct:** The members of the Lok Sabha are nominated by the Speaker from amongst its own members, just as the members of the Rajya Sabha are nominated by the Chairman from amongst its members.
- **Additional information about DRSCs:**
  - The term of Office of these Committees does not exceed one year.
  - Out of 24 Committees, 8 Committees are serviced by the Rajya Sabha Secretariat and 16 Committees by the Lok Sabha Secretariat.
  - Ministers can not be appointed to any DRSC.

22. (b)

- **Option (b) is the correct answer:** Article 166 of the Constitution states that the Governor shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of the State, and for the allocation among Ministers of the said business in so far as it is not business with respect to which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion.

23. (b)

- **Statement 1 is not correct:** The Cabinet Secretariat functions directly under the Prime Minister. Business of the Government of India allocated to the Cabinet Secretariat is deemed to have been allotted to the Prime Minister. The business allocated to Cabinet Secretariat under Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 includes (i) Secretarial assistance to the Cabinet and Cabinet Committees; and (ii) Rules of Business.
- **Statement 2 is correct:** The administrative head of the Secretariat is the Cabinet Secretary who is also the ex-officio Chairman of the Civil Services Board.

24. (d)

- **1 is not correct: Article 174** mentions that the **Governor summons each House of state legislature to meet**. The **maximum gap** between the two sessions of state legislature **cannot be more than six months**, ie, the state legislature should meet at least twice a year. A session of the state legislature consists of many sittings.
- **2 is not correct: Adjournment sine die** means **terminating a sitting of the state legislature for an indefinite period**. It is done by the **Presiding Officer**.
- **3 is correct:** An **adjournment suspends the work in a sitting for a specified time** which may be hours, days or weeks. The power of the adjournment as well as adjournment sine die lies with the **presiding officer** of the House.
- **4 is not correct: Article 174** mentions that the **Governor prorogues** the Houses of the State Legislature. It ends a session of the House, but not the House itself. This is done after the Presiding Officer adjourns the House sine die.
- **5 is correct:** The power to **dissolve the Legislative Assembly** lies with the **Governor** of the State, as mentioned under **Article 174.** It ends the life of the existing House, requiring new elections to be held

25. (c)

- **Statement 1 is correct:** The Central government has the authority to borrow both within India and from abroad upon the security of the Consolidated Fund of India. It can also give guarantees. These powers are subject to limits set by Parliament, although no such law has been enacted so far.
  - Whereas, State government has the power to borrow money within India, using the Consolidated Fund of the State as security.

But this borrowing can only be done within the limits decided by the State Legislature through law.

- **Statement 2 is correct:** Under Article 293 (3) of the Constitution, state governments are required to take the Centre's permission for fresh borrowing, if they are indebted to the Government of India.
- **Additional information:**
  - "Public debt of the State" is a subject under the State List of the Constitution of India.

26. (c)

- **Option (c) is correct:** Salary and pensions of Chief Election Commissioner of India is not charged on consolidated funds of India.
- **The expenses charged upon the Consolidated fund of India are as follows:**
  - Emoluments and allowances of the President and other expenditure relating to his office
  - Salaries and allowances of the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States and the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People
  - Debt charges for which the Government of India is liable including interest, sinking fund charges and redemption charges, and other expenditure relating to the raising of loans and the service and redemption of debt
  - Sums required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal
  - Salaries, allowances and pensions payable to or in respect of Judges of the Supreme Court
  - Pensions payable to or in respect of Judges of the Federal Court
  - Pensions payable to or in respect of Judges of any High Court
  - Salary, allowances and pension of CAG
  - Expenses of the UPSC including any salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the members or staff of the Commission

27. (b)

- **1 and 2 are correct:** A bicameral legislature is a system of government where the legislative body is divided into two separate assemblies, chambers, or houses. In India, most states are unicameral, but some of them are bicameral. Currently, only six states in India have a Legislative Council: **Uttar Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana, and Andhra Pradesh.**
- **Note:** Prior to the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, J&K had a bicameral legislature. However, with its conversion into a Union Territory, it now has a unicameral legislature.

28. (a)

- **Statement 1 is correct:** The Rajya Sabha (Council of States) may recommend changes to a Money Bill, but it cannot amend or reject the Bill. The Lok Sabha (House of the People) may choose to accept or reject these recommendations. If the Lok Sabha does not accept any of the recommendations, the Bill is deemed to have passed in the form it was initially passed by the Lok Sabha.
- **Statement 2 is correct:** Every Money Bill, when transmitted to the Rajya Sabha under Article 109 and when presented to the President for assent under Article 111, must bear the Speaker's certificate signed by him, declaring that it is a Money Bill.
- **Statement 3 is not correct:** Money Bills must be introduced in the Lok Sabha only and require the prior recommendation of the President. They cannot be introduced without the President's recommendation.

29. (a)

- **Statement 1 is correct:** The Inter-State Council is a constitutional body set up under Article 263 of the Constitution of India. Article 263 provides for the establishment of such a council to ensure better co-ordination between the States and the Union and between the States.
- **Statement 2 is correct:** The President of India is empowered to establish the Inter-State Council whenever it appears necessary in public interest, by order, as provided under Article 263.
- **Statement 3 is not correct:** The Constitution does not make the Inter-State Council a permanent body, nor does it mandate that it must meet at least once every year.
- **Additional information:** Inter-State council can be assigned the following duty as per the Constitution:

- Inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between States;
- Investigating and discussing subjects in which some or all of the Slates, or the Union and one or more of the States, have a common interest; or
- Making recommendations upon any such subject and, in particular, recommendations for the better co-ordination of policy and action with respect to that subject

30. (b)

- **Statement 1 is not correct:** This committee was set up first in 1921 under the provisions of the Government of India Act of 1919 and has since been in existence. At present, it consists of 22 members (15 from the Lok Sabha and 7 from the Rajya Sabha).
- **Statement 2 is correct:** The members are elected by the Parliament every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote. Thus, all parties get due representation in it. A minister cannot be elected as a member of the committee.
- **Statement 3 is not correct:** The term of office of the members is one year. The function of the committee is to examine the annual audit reports of the Comptroller and Auditor General of India (CAG), which are laid before the Parliament by the President.

31. (b)

- **Option (b) is correct:** Among the given options, the nominated members of Rajya Sabha participate in the impeachment of the President but not in his/her election

Participants	*Presidential Election*	*Presidential Impeachment*
1. Elected members of Rajya Sabha	Yes	Yes
2. Nominated members of Rajya Sabha	**No**	**Yes**
3. Elected members of the legislative assemblies of states	Yes	No
4. Elected members of the legislative assemblies of the UT of Delhi	Yes	No

32. (c)

- **Both Statements 1 and 2 are correct:** Under Article 213, the Governor shall not promulgate any such Ordinance without instructions from the President if he would have deemed it necessary to reserve a Bill containing the same provisions for the consideration of the President. **One of the circumstances in which a Governor is mandatorily required to reserve a Bill for the President's consideration is if, in the Governor's opinion, the proposed law affects the constitutional position, powers, or jurisdiction of the High Court** (Article 200). Since such a Bill necessarily requires Presidential consideration, **an Ordinance on the same subject also cannot be promulgated by the Governor without the President's instructions**.

33. (b)

- **Context:** India ranked 96 out of 180 countries in the Corruption Perceptions Index (CPI) for 2024 as its overall score dropped a point to 38.
- Option (b) is the correct answer: Corruption Perceptions Index (CPI) is an annual index that ranks countries and territories based on how corrupt their public sector is perceived to be. It is compiled by Transparency International, a non-governmental organization dedicated to fighting corruption.
- **Other information about the index:**
  - The index uses a scale of zero to 100, where "zero" is highly corrupt and "100" is very clean.
  - Among India's neighbours, Pakistan (135) and Sri Lanka (121) grappled with their respective low rankings, while Bangladesh's ranking stood further down at 149. China ranked 76.
  - Denmark topped the list of being the least-corrupt nation, followed by Finland and Singapore.

34. (d)

- **About Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojna (PM-AJAY): It** is a comprehensive initiative by the Government of India, launched in **FY 2021-22**, aimed at the **socio-economic upliftment** of **Scheduled Castes (SCs)**. It is a **merger scheme** of three erstwhile Centrally Sponsored Schemes, namely, **Pradhan Mantri Adarsh Gram**

Yojana (PMAGY), **Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub Plan (SCA to SCSP)** and **Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojana (BJRCY)**.

- **1 and 2 are correct: Eligibility for the scheme is as follows:**
  - Scheduled Castes persons living below the poverty lines are eligible for getting benefits under the various Income Generating Schemes and Skill Development Programmes**.**
  - In case of Infrastructure Development, the villages having 50% or more SC population are eligible for grants under the Scheme.
  - As far as definition of poverty line and selection of SC families living below poverty line is concerned, the guidelines issued by the erstwhile Planning Commission and the procedure laid down by the Ministry of Rural Development for selecting the beneficiaries through the Panchayati Raj institutions, is adopted.
- **3 is correct:** The scheme is implemented by the Ministry of Social Justice & Empowerment.
- **Additional information:** The objectives of the Scheme are:
  - To reduce poverty of the SC communities by generation of additional employment opportunities through skill development, income generating schemes and other initiatives.
  - To improve socio-economic developmental indicators by ensuring adequate infrastructure and requisite services in the SC dominated villages.
  - To increase literacy and encourage enrolment of SCs in schools and higher educational institutions by providing adequate residential facilities in quality institutions, as well as residential schools where required, especially in the aspirational districts/ SC dominated blocks and elsewhere in India.

35. (a)

- **Statement 1 is correct:** A **Private Member** is any **MP who is not a Minister** (i.e. not part of the government/executive). Therefore, **ministers cannot introduce a Private Member's Bill**.
- **Statement 2 is not correct:** There is no restriction on a Private Member introducing a Constitution Amendment Bill.
- **Statement 3 is not correct:** Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha states that a Private Member must give at least one month's notice before the bill is listed for introduction.
- **Statement 4 is not correct:** Both Lok Sabha and Rajya Sabha members (who are not ministers) can introduce and pass Private Member's Bills.

36. (c)

- **Row 1 is correctly matched:** The **Ministry of Ports, Shipping and Waterways** has launched the **Jalvahak Scheme** to **boost the movement of long-haul cargo via National Waterways** 1 (river Ganga) as well as for National Waterways 2 (river Brahmaputra) and National Waterways 16 (river Barak). The 'Jalvahak' scheme offers reimbursement up to 35% of total operating expenditure incurred while transporting cargo via waterways on NW 1 (Ganga River), NW 2 (Brahmaputra River) & NW 16 (Barak River) via Indo Bangladesh Protocol (IBP) route.
- **Row 2 is correctly matched:** The **Ministry of Earth Sciences** has launched the **Samudrayaan Mission**. The Mission aims to develop a self-propelled manned submersible to carry three human beings to a water depth of 6000 meters in the ocean with a suite of scientific sensors and tools for **deep ocean exploration.**
- **Row 3 is correctly matched:** The **Sagarmala Programme** is the flagship programme of the **Ministry of Ports, Shipping and Waterways** to promote **port-led development** in the country by taking advantage of India's 7,500 km long coastline, 14,500 km long potentially navigable waterways and the strategic location on major maritime trade routes. The core vision of the Sagarmala programme is to reduce the logistics cost for EXIM and domestic trade with minimal infrastructure investment.

37. (a)

- **Statement 1 is correct:** Farmer ID is an Aadhaar-linked unique digital identity that is linked dynamically to the state's land records, besides having information like **demographic, crops sown, livestock ownership and ownership details.**

- **Statement 2 is not correct:** The creation and maintenance of the Farmer ID **are managed by state governments and Union Territories.**

38. (c)

- **Option (c) is the correct answer:** The Vote on Account is a parliamentary provision under Article 116 of the Constitution. It is used when:
  - The Union Budget is not passed before the beginning of the new financial year.
  - The government seeks approval from Parliament to withdraw funds from the Consolidated Fund of India to meet its regular expenses (salaries, subsidies, interest payments, etc.).

39. (d)

- **Statements 1 and 2 are correct:** Article 120 of the Constitution of India provides that the business in Parliament shall be transacted in Hindi or English. The use of English in Parliament was originally meant to end 15 years after the Constitution began (i.e., after 1965), unless Parliament passed a law to continue it. However, the Official Languages Act, 1963 was enacted to provide for the continued use of English, in addition to Hindi, for official purposes of the Union and for transaction of business in Parliament, even after January 26, 1965.
- **Statement 3 is correct:** Chairman of the Council of States or Speaker of the House of the People, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the House in his mother-tongue.

40. (c)

- **Statement 1 is correct:** As per the Article 75 of the Constitution of India, Council of Ministers as well as Prime Minister shall hold office during the pleasure of the President.
- **Statement 2 is correct:** According to Article 356, President's Rule can be imposed on any state of India on the grounds of the failure of the constitutional machinery. Resignation of the Council of Ministers does not automatically imply the failure of Constitutional machinery In case the CoM resigns, the Governor of the state first explores the possibility of forming an alternative government. If another party or a coalition can prove it has the required majority to form a stable government, the Governor will invite them to do so. President's Rule (Article 356) is only imposed as a last resort when the Governor's report to the President indicates that no stable government can be formed and the constitutional machinery in the state has failed.

41. (c)

- **Statement 1 is correct: Article 156** explicitly provides that the **Governor shall hold office for a term of five years** from the date on which he enters upon his office.
- **Statement 2 is not correct:** While appointing the governor, the **President is required to consult the chief minister of the state concerned**, so that the smooth functioning of the constitutional machinery in the state is ensured. However, this is **not a requirement mentioned under the Constitution but a Convention** which has evolved over the years.
- **Statement 3 is correct:** As per **Article 157**, a person shall not be eligible for appointment as Governor unless he has completed the age of **35 years**.
- **Statement 4 is correct: Article 156** states that the Governor shall hold office during the **pleasure of the President**.

42. (b)

- **1 and 3 are correct:** In the following matters, the powers and status of Legislative Council are broadly equal to that of the Legislative Assembly:
  - **Introduction of ordinary bills**. However, in case of disagreement between the two Houses, the will of the assembly prevails over that of the council. Thus, **Statement 1 is correct.**
  - **Approval of ordinances issued by the governor**. Thus, **Statement 3 is correct.**
  - Consideration of the reports of the constitutional bodies like State Finance Commission, state public service commission and Comptroller and Auditor General of India.
  - Enlargement of the jurisdiction of the state public service commission.
- **2 and 4 are not correct:** However, the Legislative Assembly enjoys greater powers in the following matters:

- **The council does not participate in the election of** the president of India and **representatives of the state in the Rajya Sabha**. Thus, **Statement 2 is not correct.**
- **A Money Bill can be introduced only in the assembly** and not in the council. The **council cannot amend or reject a money bill**. It should return the bill to the assembly within 14 days, either with recommendations or without recommendations. Thus, **Statement 4 is not correct.**

43. (c)

- **Option C is the correct answer:** Article 72 of Constitution of India states the Power of the President to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases. Remission implies reducing the period of sentence without changing its character. For example, a sentence of rigorous imprisonment for two years may be remitted to rigorous imprisonment for one year.
- **Additional information:**
  - **Pardon**: It removes both the sentence and the conviction and completely absolves the convict from all sentences, punishments and disqualifications.
  - **Commutation:** It denotes the substitution of one form of punishment for a lighter form. For example, a death sentence may be commuted to rigorous imprisonment, which in turn may be commuted to a simple imprisonment.
  - **Respite**: It denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special fact, such as the physical disability of a convict or the pregnancy of a woman offender.
  - **Reprieve:** It implies a stay of the execution of a sentence (especially that of death) for a temporary period. Its purpose is to enable the convict to have time to seek pardon or commutation from the President.

44. (c)

- **Statement 1 is correct:** According to Article 83(2) of the Constitution, the Lok Sabha, unless sooner dissolved, continues for five years from the date appointed for its first meeting. Upon the completion of this five-year term, the Lok Sabha is automatically dissolved by the operation of the Constitution.
- **Statement 2 is correct:** President of India may dissolve the Lok Sabha before the completion of its five-year term. This power enables the President to dissolve the House on the advice of the Council of Ministers, or under certain circumstances, if the government has lost majority support and no alternative government can be formed

45. (a)

- **Statement 1 is correct: Article 110(3)** of the Constitution of India explicitly states that "if any question arises whether a Bill is a Money Bill or not, the decision of the Speaker of the House of the People thereon shall be final.
- **Statement 2 is not correct:** The power to disqualify a member of the Lok Sabha for holding an **office of profit** rests with the **President**, not the Speaker. The President's decision, however, is made on the advice of the **Election Commission of India**. The Speaker's power to disqualify a member is limited to the disqualifications under the **Anti-Defection Law** (Tenth Schedule of the Constitution)

46. (d)

- **Statement 1 is correct:** Index of Eight Core Industries (ICI) is a monthly production index published by the Office of the Economic Adviser (OEA), which falls under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry.
- **Statement 2 is correct:** Among the eight core sectors, Petroleum Refinery Products hold the highest weight (28.04%), while Fertilizers have the lowest weight (2.63%).
- **Statement 3 is correct:** ICI measures the combined and individual performance of production of eight core industries viz. Cement, Coal, Crude Oil, Electricity, Fertilizers, Natural Gas, Refinery Products and Steel. The Eight Core Industries comprise 40.27 percent of the weight of items included in the Index of Industrial Production (IIP).

47. (b)

- **Option B is correct:** The **first zoo-based bio bank in India** was established at Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling, becoming **operational in July 2024**

in partnership with the **Centre for Cellular and Molecular Biology (CCMB)** under the Ministry of Science & Technology.

- The facility—an institutional **bio banking cellular lab**—preserves **DNA, tissue, reproductive cells**, and gametes from endangered or deceased animals. Its key purpose is to strengthen conservation breeding using **assisted reproductive technologies (ART)** through long-term genetic safeguarding.
- It collaborates with **CCMBLaCONES**, enabling national-level conservation genetics support and training

48. (c)

- **Option (c) is the correct answer:** It is an AI-powered subsea cable system, spanning 50,000 km across five continents (Asia,Africa,North America, South America and Australia). It is the longest and highest-capacity subsea cable system, linking the U.S., India, Brazil, South Africa, and other key regions. The cables will be laid at depths of up to 7,000 meters in deep waters and advanced burial techniques in high-risk shallow waters will protect the cables from ship anchors and environmental hazards. Greater connectivity will enhance international cooperation, digital inclusion, and technological advancements.

49. (c)

- **Context:** A key highlight of the Union Budget 2025-26 is the launch of a Nuclear Energy Mission, which is focused on research and development (R&D) of **Bharat Small Modular Reactors (BSMRs)**. The government has allocated ₹20,000 crore for this initiative, aiming to develop at least five indigenously designed and operational SMRs by 2033.
- **Statement 1 is not correct:** SMRs, are advanced nuclear reactors with a power generation capacity ranging from less than **30 MWe to 300+ MWe**, provide a flexible, scalable, and cost-effective alternative to conventional large nuclear reactors.
- **Statement 2 is not correct:** BSMRs are modified versions of India's existing Pressurised Heavy Water Reactor (PWHR) and will each have a capacity of 200 MW (Megawatt). They will be fuelled by "slightly enriched uranium" and are being jointly designed and developed by the Bhabha Atomic Research Centre and Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL).
- **Statement 3 is correct:** Given India's growing energy demands and the need for reliable, low-carbon power, SMRs can play a **transformative role** in complementing renewable energy sources and stabilizing the grid. Their modular design allows for **factory-based manufacturing**, reducing construction timelines and costs, making them suitable for both **on-grid** and **off-grid applications**, including deployment in **remote locations**.

50. (b)

- **Context:** Recently, the Euclid space mission of the European Space Agency (ESA) spotted an Einstein ring in the galaxy NGC 6505, just 590 million lightyears from the earth.
- **Option (b) is the correct answer:** An Einstein ring is a ring of light around a form of dark matter, galaxy or cluster of galaxies. It is essentially an example of gravitational lensing. Gravitational lensing is a phenomenon which occurs when a massive celestial body — such as a galaxy or cluster of galaxies — creates a gravitational field which distorts and amplifies the light from distant galaxies that are behind it but in the same line of sight

51. (a)

- **Statement I is correct:** President's pardoning powers under Article 72 are wider than the Governor's powers under Article 161.
- **Statement II is correct and correctly explains Statement I:** Under Article 72 of the Constitution, the President has the power to pardon a death sentence. The Governor, under Article 161, can only suspend, remit, or commute a death sentence; they cannot pardon it completely. A death sentence can only be pardoned by the President. This is a direct example of the President's wider power.
- **Statement III is correct and correctly explains Statement I:** The power to pardon, reprieve, or commute sentences of individuals convicted by a court-martial (a military court) rests solely with the President under Article 72. The Governor does not have any power over military courts. This is another difference that makes the President's power wider.

52. (a)

- **Statement 1 is correct:** If the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest so to do, **Parliament may by law provide fo**r the creation of one or more all-India services **(including an all-India judicial service)** common to the Union and the States. This can be done by an ordinary law and does not require a constitutional amendment under Article 368.
- **Statement 2 is not correct:** While a Constitutional Amendment Bill can be introduced in either House of Parliament (Lok Sabha or Rajya Sabha), it does not require the prior approval of the President.

53. (c)

- **1, 2 and 3 are correct:** Functions of the cabinet secretariat includes:
  - **Administration of the Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961** and Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 facilitating smooth transaction of business in Ministries/ Departments.
  - It assists in decision-making in Government by ensuring **Inter-Ministerial coordination**, ironing out differences amongst Ministries/ Departments and evolving consensus through the instrumentality of the standing/ adhoc Committees of Secretaries
  - **Secretarial assistance to the Cabinet and Cabinet committees:** It includes — Convening of the meetings of the Cabinet & its Committees on the orders of the Prime Minister, Preparation and circulation of the agenda, Circulation of papers related to the cases on the agenda, C**irculation of the record of discussions after obtaining the approval of the Prime Minister**, Monitoring implementation of decisions taken by the Cabinet and its Committees
  - Management of major crisis situations in the country and coordinating activities of various ministries in such a situation
- **4 is not correct:** Cabinet Secretariat does not allocate financial resources to ministries; that function typically falls under the Ministry of Finance.

54. (c)

- **Statement 1 is correct**: **Vice President of India** is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha, While the Vice President presides over the Upper House, he is not a member of the Rajya Sabha itself.
- **Statement 2 is correct:** Speaker of the Lok Sabha is elected by a simple majority from among the sitting members of the House. The Speaker is thus an elected representative and a member of the Lok Sabha.

55. (b)

- **Statement 1 is correct:** According to Article **61(1), t**he President can be removed from office only for "violation of the Constitution". No other ground is permitted for impeachment. The resolution to impeach the President can be moved in either House of Parliament. Such a resolution can be moved only after a notice has been given by at least one-fourth of the total number of members of the House.
- **Statement 2 is not correct:** When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament. No such charge shall be preferred unless— the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least fourteen days' notice in writing **signed by not less than one-fourth of the total number of members of the House** has been given of their intention to move the resolution.
- **Statement 3 is correct:** Such a resolution charging the President for violation of the Constitution must be passed by a majority of not less than two-third of the total membership of that House before it goes to the other House for investigation.

56. (d)

- **Option (d) is the correct answer:** The order of precedence for discharging the functions of the President in case of a vacancy or unavailability is as follows:
  - **Vice-President of India:** As per Article 65(1) of the Constitution, "In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the President by reason of his death, resignation or removal, or otherwise, the Vice-President shall act as President, or

discharge his functions during his absence, illness or any other cause."

- ♦ **Chief Justice of India**: If the office of the President and the Vice-President both fall vacant due to death, resignation, removal, or otherwise, the Chief Justice of India discharges the functions of the President. This provision is not explicitly mentioned in the Constitution but was established by the President (Discharge of Functions) Act, 1969.
- ♦ **Senior-most Judge of the Supreme Court**: If the office of the President, Vice-President, and Chief Justice of India all fall vacant, then the senior-most Judge of the Supreme Court available discharges the functions of the President. This is also established by the President (Discharge of Functions) Act, 1969.

57. (d)

- **About Zonal Councils:** In the light of the vision of Pandit Nehru, five Zonal Councils were set up vide Part-III of the States Reorganisation Act, 1956. The present composition of each of these Zonal Councils is as under:
  - ♦ The Northern Zonal Council, comprising the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Chandigarh;
  - ♦ The Central Zonal Council, comprising the States of Chhattisgarh, Uttarakhand, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh;
  - ♦ The Eastern Zonal Council, comprising the States of Bihar, Jharkhand, Orissa, Sikkim and West Bengal;
  - ♦ The Western Zonal Council, comprising the States of Goa, Gujarat, Maharashtra and the Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli;
  - ♦ The Southern Zonal Council, comprising the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and the Union Territory of Puducherry.
- **Statement I is not correct:** Zonal Councils were established to foster interstate cooperation, and their membership includes both states and Union Territories. The Northern Zonal Council, comprises the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, **National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Chandigarh.** Similarly, Western Zonal Council, comprises the States of Goa, Gujarat, Maharashtra and the **Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli**.
- **Statement II is correct:** Zonal Councils are statutory bodies created under the States Reorganisation Act, 1956.

58. (c)

- **Statement 1 is correct:** As per **Article 110**, a **Bill shall be deemed to be a Money Bill if** it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely:--
  - (a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;
  - (b) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the Government of India, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the Government of India;
  - (c) the custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of India, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such Fund;
  - (d) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India;
  - (e) the **declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of India** or the increasing of the amount of any such expenditure;
  - (f) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of India or the public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the Union or of a State; or
  - (g) any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f).
- **Statement 2 is correct:** The Constitution states that 'no money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under appropriation made by law'. Accordingly, an **appropriation bill** is introduced to provide for the appropriation, out of the Consolidated Fund of India, all money required to meet:
  - (a) The grants voted by the Lok Sabha.
  - (b) The **expenditure charged on the Consolidated Fund of India.**

Thus, expenditures charged on the Consolidated Fund of India, though not subject to voting in the Lok Sabha, are included in the appropriation bill for record purposes.

59. (d)

- **Option (d) is the correct answer:** 52nd Constitutional Amendment Act, 1985 inserted the Tenth Schedule into the Constitution of India, which contains the provisions for the Anti-Defection Law. The law was enacted to prevent political defections by members of Parliament and State Legislatures from one party to another. It was a response to the prevalent phenomenon of "Aaya Ram Gaya Ram" politics, where elected representatives would frequently switch parties, often for personal gain, leading to political instability

60. (a)

- **Statement 1 is correct:** If a sitting member of one House is also elected to the other House, his seat in the first House becomes vacant. This implies that if a member of the Council of States is elected to the House of the People, their seat in the Council of States becomes vacant.
- **Statement 2 is not correct:** If a person is elected to both Parliament and a State Legislature, his seat in Parliament will become vacant if he does not resign his seat in the State legislature within 14 days. So, in this case, seat in the Council of states will get vacant, and not the seat in the State Legislative Assembly.

61. (b)

- **Statement 1 is not correct:** Under **Article 170**, the Constitution specifies **both the minimum and maximum strength** of a **State Legislative Assembly**. It states that the Legislative Assembly shall consist of **not less than 60 and not more than 500 members**, although **some exceptions exist for smaller states** like **Sikkim** (32 members), **Goa** (40), etc.
- **Statement 2 is correct:** According to **Article 171**, the **strength of the Legislative Council** is linked to the strength of the Legislative Assembly. The total number of members in the Council shall **not exceed one-third of the total members of the Assembly** and shall **not be less than 40**.
- **Statement 3 is correct:** The **Legislative Assembly of Uttar Pradesh** has **403 members**, which is the **highest among all Indian states**.

62. (b)

- **Statement 1 is correct:** Cabinet Committees are **not mentioned in the Constitution**. They are formed under the **Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961** to assist the Cabinet in decision-making on specific issues.
- **Statement 2 is correct: Non-Cabinet Ministers** or other officials can be **invited to participate** in Cabinet Committees as special invitees, though they are not formal members.
- **Statement 3 is not correct:** The **Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA)** is **chaired by the Prime Minister**, not the Finance Minister.
- **Additional Information:**
  - Cabinet Committees help in **speedy decision-making** and reduce the burden on the full Cabinet.
  - Examples include the **Cabinet Committee on Security, Cabinet Committee on Political Affairs, and Cabinet Committee on Economic Affairs**.
  - Membership and composition of committees are decided by the **Prime Minister**.
  - Non-Cabinet Ministers or experts are sometimes invited **to provide specific inputs** but do not have voting rights.

63. (d)

- **Statement 1 is not correct:** Dokra craft is a **traditional metal-casting technique**. It is believed to be **older than 4000 years**. The artform requires precise and intricate craftmanship, and the structures are **usually made of brass, nickel and zinc alloys.**
- **Statement 2 is not correct:** Dokra is **primarily practiced in Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, West Bengal, and Telangana**.

64. (c)

- **Option (c) is the correct answer:** The **Gulf of Eilat** (also called the **Gulf of Aqaba**) is a **narrow extension of the northern Red Sea**, located **between the Sinai Peninsula (Egypt) and western Saudi Arabia**. Israel and Jordan are situated at its northern tip.
- The Gulf of Eilat is known for its **unique and resilient coral reef ecosystems**, which **thrive even in warmer waters where corals**

elsewhere are bleaching. It is **also home to one of the northernmost coral reefs in the world (29.5° N)** due to comparatively warmer waters than other water bodies at the same latitudes (between 22 °C and 28 °C).

65. (a)

- **Context:** Recently, **Australian authorities have euthanised around 100 false killer whale**s which were stranded on a beach in Tasmania, citing **impossible conditions for rescue** of the whales.
- **Statement 1 is correct: False killer whales** are **one of the world's largest dolphin species.** They can grow up to six meters (19 feet) and weigh up to 1.5 tonnes.
- **Statement 2 is not correct:** They are known for their **strong social bonds**, which often lead to **entire pods stranding together**.
- **Additional information:** False killer whales are **generally found in tropical and temperate waters between latitudes of 30° and 30° N**. While they appear to occur more frequently in deeper open ocean waters, they can occasionally move into nearshore areas.

66. (c)

- **About Cut Motions:** A motion that is m**oved in the legislatures by the members to reduce any demand for grant** is known as 'cut motion'. Cut Motions are of three kinds.
- **Option (c) is the correct answer:** A **Token Cut Motion** is **used not to reduce government expenditure substantially, but to symbolically highlight a specific grievance or issue**. The motion demands that the **amount of the demand be reduced by ₹100 only**, making it **tokenistic** in nature.
- The main **purpose** of this motion is **not financial reduction but to draw Parliament's attention** to a matter of concern within the jurisdiction of the government.
- **Additional information:** Other types of cut motions:
  - **Economy Cut Motion:** It represents the economy that can be affected in the proposed expenditure. It states that the **amount of the demand be reduced by a specified amount** (which may be either a lumpsum reduction in the demand or omission or reduction of an item in the demand).
  - **Policy Cut Motion:** It is **moved to express disapproval of the policy underlying a particular demand.** It proposes that the amount of the demand be reduced to Re 1, and **provides members the opportunity to propose alternative policies.**

67. (b)

Statements 1, 2 and 4 are correct: In the following matters, the powers and status of the Rajya Sabha are equal to that of the Lok Sabha:

1. **Introduction and passage of ordinary bills.**
2. **Introduction and passage of Constitutional amendment bills. (Hence, Statement 4 is correct)**
3. Introduction and passage of financial bills involving expenditure from the Consolidated Fund of India.
4. **Election and impeachment of the president. (Hence, Statement 1 is correct)**
5. Election and removal of the Vice-President. However, Rajya Sabha alone can initiate the removal of the vice-president. He is removed by a resolution passed by the Rajya Sabha by an effective majority (which is a type of special majority) and agreed to by the Lok Sabha by a simple majority.
6. Making recommendation to the President for the removal of Chief Justice and judges of Supreme Court and high courts, chief election commissioner and comptroller and auditor general.
7. **Approval of ordinances issued by the President. (Hence, Statement 2 is correct)**
8. Approval of proclamation of all three types of emergencies by the President.
9. Selection of ministers including the Prime Minister. Under the Constitution, the ministers including the Prime Minister can be members of either House. However, irrespective of their membership, they are responsible only to the Lok Sabha.
10. Consideration of the reports of the constitutional bodies like Finance Commission, Union Public Service Commission, comptroller and auditor general, etc.

Statements 5 is not correct: It is a special power of Rajya Sabha under Article 249. If the Rajya Sabha (Council of States) passes a resolution —

supported by at least two-thirds of the members present and voting — saying that it is necessary in the national interest for Parliament to make laws on a subject from the State List, then Parliament gets the power to make such laws for the whole or any part of India, as long as that resolution remains in force.

Additional Information:

(1) Unequal Status of Rajya Sabha vis-à-vis Lok Sabha

1. Money and Financial Bills

- A Money Bill can be introduced only in the Lok Sabha (Art. 110).
- Rajya Sabha cannot amend/reject a Money Bill; it must return it within 14 days, with or without recommendations.
- Lok Sabha may accept or reject these recommendations; in either case, the bill is deemed passed.
- The Speaker of Lok Sabha has the final authority to decide whether a bill is a Money Bill.

2. Budgetary Powers

- Rajya Sabha may discuss the budget but cannot vote on demands for grants (an exclusive power of Lok Sabha).

3. Joint Sittings

- In a joint sitting, the Speaker of Lok Sabha presides.
- With its larger strength, Lok Sabha normally prevails unless the ruling party is in minority across both Houses.

4. Control over Government

- Only the Lok Sabha can pass a no-confidence motion against the Council of Ministers (as they are collectively responsible to Lok Sabha alone).
- Rajya Sabha can merely discuss and criticise government policies.

5. National Emergency

- A resolution to discontinue national emergency can be passed only by Lok Sabha, not Rajya Sabha. (Hence, Statement 3 is not correct)

(2) Special Powers of Rajya Sabha

1. **Legislative Power under State List:** Authorises Parliament to make laws on a State List subject (Art. 249). (Hence, Statement 5 is not correct)
2. **Creation of All-India Services:** Can empower Parliament to establish new All-India Services (Art. 312).
3. **Removal of Vice-President:** Only Rajya Sabha can initiate a resolution for the Vice-President's removal (Art. 67).
4. **Emergency Situations:** When Lok Sabha is dissolved, Rajya Sabha's approval alone is sufficient to keep a proclamation of National Emergency, President's Rule, or Financial Emergency in force (Arts. 352, 356, 360).

68. (d)

- **About The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)**: It is a grouping of **seven Member States lying in the littoral and adjacent areas of the Bay of Bengal**. It is a unique link connecting South Asia with South-East Asia - five Members from South Asia (**Bangladesh**, Bhutan, **India**, Nepal and Sri Lanka) and two from South-East Asia (Myanmar and Thailand). **Thus, 1 is correct.**
- **About The Indian Ocean Rim Association (IORA):** It is an **intergovernmental organization focused on promoting regional cooperation and sustainable development among countries bordering the Indian Ocean**. It was established in 1997 and currently has 23 member states. Its members include Australia, **Bangladesh**, France, **India**, Indonesia, Singapore, Thailand, UAE etc. **Thus, 2 is correct.**
- **About The Colombo Security Conclave (CSC):** It is a **regional security grouping focused on the Indian Ocean Region. Established in 2020**, it aims to enhance cooperation among member states to address transnational threats and challenges. The current members include **India**, Sri Lanka, Maldives, Mauritius, and **Bangladesh. Thus, 3 is correct.**

69. (b)

- **The correct answer is (b), that is, 1–A, 2–B, 3–C.**
- **Indian Penal Code, 1860 (IPC)** has been repealed and replaced by **Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023.** It focuses on crimes like **murder, theft, mob lynching, terrorism** etc.
- **Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC)** has been replaced by **Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023.** It governs the **procedure** of **investigation, trial, appeal** etc. It also introduces **time-bound trials, e-FIRs, forensic evidence, and digitization of criminal procedure**.
- **Indian Evidence Act, 1872** has been replaced by **Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA), 2023.** It governs admissibility of evidence. It also expands scope of **electronic & digital evidence**, strengthens rules for documentary proof etc.

70. (d)

- **Statement 1 is correct:** India became a party to the **'Convention on Wetlands', also known as the Ramsar Convention on 1st February 1982.**
- **Statement 2 is correct:** The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) has notified **Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986** as the regulatory framework for conservation and management of wetlands in India.
- **Statement 3 is correct:** Celebrated annually on 2 February, World Wetlands Day aims to raise global awareness of the vital role of wetlands for people, nature and culture. **2025 year's theme, 'Protecting Wetlands for Our Common Future', reminds us of the benefits wetlands provide for biodiversity and human wellbeing.**

71. (a)

- **Context:** The Competition Commission of India (CCI) has released the draft Competition Commission of India (Determination of Cost of Production) Regulations, 2025, seeking stakeholder input to modernise its approach to determining predatory pricing under competition law.
- **Option (a) is the correct answer:**
  - The law defines **"predatory pricing"** as the **sale of goods or services "below the cost of production", with the intent to reduce or eliminate competition.**
  - The new draft regulations seek to "modernise cost benchmarks" to ensure consistency with contemporary "economic theories, judicial interpretations, and global competition practices".
  - The Competition Act, 2002 prohibits predatory pricing under Section 4(2)(a)(ii) as an abusive practice by dominant enterprises.

72. (c)

- **Pair 1 is not correctly matched:** Tropex **(Theatre Level Operational Readiness Exercise)** is a domestic exercise, but involves multiple forces, not just the Navy. It is a tri-service exercise coordinated by the Indian Navy, but it also includes units from the Indian Army, Air Force, and Coast Guard.
- **Pair 2 is correctly matched: Exercise 'DHARMA GUARDIAN' is an annual exercise and conducted alternatively in India and Japan** involving the Armies of both nations. It focuses on joint military operations in semi-urban and jungle terrain.
- **Pair 3 is not correctly matched: Exercise Komodo is a multilateral naval exercise hosted by Indonesia,** with participation from navies around the world, including India.

73. (a)

- **Statement 1 is correct:** The initial members were the five BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, and South Africa). However, the bank's Articles of Agreement allow for the admission of new members. **Membership of the NDB is open to countries beyond the BRICS nations**, allowing for expansion in the future. Since its establishment, the NDB has expanded its membership to include countries like Bangladesh, Egypt, the United Arab Emirates (UAE), and Algeria.
- **Statement 2 is not correct:** The NDB maintains its permanent headquarters in Shanghai, China. This is a central hub for its operations, decision-making, and administration, much like other multilateral development banks.

- **Additional Information:**
  - The New Development Bank was established in 2014 by the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) to mobilize resources for infrastructure and sustainable development projects. The bank also aims to complement existing international financial institutions and promote global financial stability.

74. (c)

- **Option C is the correct answer:** A *nominated member* may join any political party **within six months** of taking his seat. If he joins after six months, he is disqualified. Here, the member joins **after four months (within the six-month window)**.
- **Additional Information: Disqualification under the Tenth Schedule (Anti-Defection Law)**
  - A member of Parliament can be disqualified under the provisions of the Tenth Schedule on the following grounds:
  - **For Party Members:** If the member voluntarily gives up the membership of the political party on whose ticket he/she was elected. If the member votes or abstains from voting in the House against the direction (whip) issued by his/her political party.
  - **For Independent Members:** If an independent member (elected without party affiliation) joins a political party after the election.
  - **For Nominated Members:** If a nominated member joins a political party after six months from the date of nomination.
  - **Authority to Decide:** The Chairman of the Rajya Sabha (for its members) and the Speaker of the Lok Sabha (for its members) decide on questions of disqualification under this Schedule. This power does not lie with the President of India.
  - **Judicial Review:** In Kihoto Hollohan vs. Zachillhu (1992), the Supreme Court held that the decision of the Speaker/Chairman on disqualification is subject to judicial review.

75. (c)

- **Statement 1 is correct: As per the Constitution, the Speaker of the outgoing Lok Sabha vacates office just before the first sitting of the newly elected House.** The Speaker Pro Tem has all the powers of the Speaker. He presides over the first sitting of the newly-elected Lok Sabha.
- **Statement 2 is not correct: The President appoints a member of the Lok Sabha as the Speaker pro tem,** generally choosing the senior-most member. The oath of office to the Speaker pro tem is administered by the President.
- **Statement 3 is correct:** The primary responsibility of the **Speaker pro tem** is to **administer the oath** to the **newly elected members** of the **Lok Sabha** and to **conduct the proceedings** for the **election of the new Speaker**. Once the House **elects its Speaker**, the **office of the Speaker pro tem** automatically **ceases to exist**.

76. (d)

- **About the Prime Minister:** The Prime Minister is the **real executive authority (de facto executive) and the head of the government** under the parliamentary system of government provided by the constitution.
- **Statement 1 is not correct:** Article 75 of the Constitution mentions that the Prime Minister shall be appointed by the President. In 1980, the Delhi High Court held that the **Constitution does not require that a person must prove his majority in the Lok Sabha before he is appointed as the Prime Minister.** The President may **first appoint him the Prime Minister and then ask him to prove his majority in the Lok Sabha within a reasonable period.** For example, **Charan Singh (1979),** V.P. Singh (1989), **P.V. Narasimha Rao (1991), A.B. Vajyapee (1996), Deve Gowda (1996), I.K. Gujral** (1997) etc. were appointed as Prime Ministers in this way.
- **Statement 2 is not correct:** In 1997, the Supreme Court held that a person who is not **a member of either House of Parliament can be appointed as Prime Minister for six months, within which, he should become a member** of either House of Parliament; **otherwise, he ceases to be the Prime Minister.**

77. (d)

- **Row I is not correctly matched:** A Starred Question requires **an oral answer** from the

concerned minister. Supplementary questions **are allowed** after the oral reply.

- **Row II is not correctly matched:** An **Unstarred Question** is answered in **writing,** and **NO supplementary** questions are permitted.
- **Row III is not correctly matched:** A Short Notice Question is asked without the usual **15-day notice due to urgency**. It is answered orally by the minister, and **supplementary questions are allowed.**

78. (a)

- **Article 191(1)** of the Constitution mentions the following **grounds for disqualification of a member of the State Legislature**:
  - If a person **holds any office of profit under the Union or State Government** (other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder). Thus, **Statement 1 is correct.**
  - If a **person is of unsound mind and so declared by a competent court**. Thus, **Statement 2 is correct.**
  - If a person is an undischarged insolvent,
  - If a person is not a citizen of India or has voluntarily acquired foreign citizenship, etc.
- **Article 191(2)** mentions another ground of disqualification, that is **disqualification under anti-defection law (X Schedule)**.
- **Statement 3 is not correct:** The ground of **disqualification upon conviction and sentence of imprisonment of 2 years or more is mentioned under the Representation of the People Act, 1951** and not the Constitution.

79. (b)

- **Statement 1 is not correct:** The **Appropriation Bill does not propose taxes; it authorizes withdrawal of funds from the Consolidated Fund of India** to meet government expenditure. Proposals for **taxation are included in the Finance Bill.**
- **Statement 2 is correct:** The **Appropriation Bill is introduced in Parliament only after the Demands for Grants have been voted upon**, ensuring that funds are sanctioned for government expenditure.
- The voting on demands for grants is the stage where the Lok Sabha discusses and approves the government's proposed expenditures for each ministry or department. The total amount approved in this process is then consolidated into the Appropriation Bill, which, once passed, legally authorizes the government to withdraw funds from the Consolidated Fund of India.
- **Additional Information:**
  - The Appropriation Bill is a money bill under Article 110 of the Constitution. It legally empowers the government to withdraw funds from the Consolidated Fund of India for the financial year, reflecting Parliament's approval of expenditure.

80. (c)

- **1 is not correct:** India signed the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment on 14 October 1997. However, India has not ratified the Convention.
- **2 is correct:** India has ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities on 01.10.2007.
- **3 is correct:** India ratified the The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights on 10 April, 1979.
- **4 is correct:** India has ratified The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women on 09 July, 1993.
- **5 is correct:** India ratified the The Convention on the Rights of the Child on 11 December 1992.

81. (b)

- **Option B is correct:** The term **Lame-duck Session** refers to the **final session** of the **outgoing Lok Sabha**, held **after the election of a new Lok Sabha**.
- The members of the **outgoing Lok Sabha** who **failed to get re-elected** to the **new House** are known as **lame-ducks**.

82. (d)

- **Statement 1 is not correct:** As per **Articles 200 and 201** of the **Constitution**: The **Governor** can **reserve** certain **Bills** (including **Money Bills**) for the **consideration of the President**. However, once a **Money Bill** is **passed by the State Legislature** and **reserved for the President**, the **President** has only two

options: **give assent** or **withhold assent**. There is **no provision** for the President to **return a Money Bill** to the **State Legislature** for **reconsideration**.

- **Statement 2 is not correct:** Under **Article 201**, if the **Governor reserves a Bill** for the **consideration of the President**, the **President** may either **assent** or **withhold assent**, or **return the Bill** (**if not a Money Bill**) for **reconsideration**. Even if the **State Legislature re-passes** the Bill, the **President is not bound** to **give assent**.

83. (d)

- **About SEBCs:** The Constitution (One Hundred and Second) Amendment Act 2018 has inserted Article 342-A in the Constitution of India. Article 342-A deals with the Central List of Socially and Educationally backward Classes (SEBCs - commonly known as other backward classes - OBCs).
- **Statement 1 is not correct:** The President is authorized to specify the Central list of the SEBCs, in relation to a particular State or Union Territory. Thus, it is not the Parliament but the President who declares the Central List of SEBCs.
- **Statement 2 is not correct:** Any modification to the central list of the SEBCs (OBCs) can be done only by the Parliament.

84. (c)

- **Statement 1 is correct: The ICJ is located at The Hague, Netherlands**, not in New York. **All other principal organs of the UN** (General Assembly, Security Council, ECOSOC, Secretariat, Trusteeship Council) **are based in New York.**
- **Statement 2 is correct:** The ICJ cannot impose jurisdiction unilaterally. Its jurisdiction exists if:
  - **Both parties consent to refer the case**, or
  - Both states have recognized compulsory jurisdiction of ICJ, or
  - It is provided in a treaty/agreement.

85. (b)

- **2 and 4 are correct:** Lebanon is a country in Western Asia, situated on the eastern shore of the Mediterranean Sea. It shares land borders with:
  - **Israel** to the south
  - **Syria** to the north and east

It does not share a border with Turkey, Iraq, or Iran.

86. (a)

- **Option (a) is the correct answer-** A **Hung Parliament** occurs when no party or pre-poll alliance has enough seats to form a government on its own.
- In such cases, parties may negotiate post-poll alliances or seek support from smaller parties or independent MPs to form a **coalition government**.

87. (b)

- **Context:** Recently, Tribal families from Neelabandha, a hilltop hamlet in Arla Panchayat of Rolugunta mandal in Anakapalli district, received electricity for the first time after Independence and performed 'Dhimsa', a popular tribal dance, in excitement under the lights.
- **Option (b) is the correct answer: 'Dhimsa',** which translates to 'sound of feet.' **is a popular tribal dance** performed mainly in the regions of **Andhra Pradesh and Odisha**. The dance is intricately intertwined with local culture, particularly in regions of Araku Valley and Borra Caves." **Historically, Dhimsa had been performed by young, unmarried women.** Each movement in the dance **emulates various daily tasks – gathering leaves or plants,**

doing agriculture, participating in marriage customs or defending oneself from wildlife.

88. (d)

- **Statement 1 is not correct:** The Constitution (Article 165) has provided for the office of the advocate general for the states. **He is appointed by the governor.**
- **Statement 2 is not correct:** The **Advocate General** may appear before **any court in the state** in the discharge of his duties. He has the **right to speak and participate** in the proceedings of the **State Legislature** and its **committees** (if a member), but **cannot vote**. He also enjoys the **privileges and immunities** of a **State Legislator**.
- **Statement 3 is not correct:** The **Constitution** does not prescribe a **fixed term of office** for the **Advocate General**, nor does it specify the **procedure or grounds for removal**. He holds office at the **pleasure of the Governor** and may also resign by submitting his resignation to the **Governor**. By convention, the Advocate General usually resigns when the **Council of Ministers** resigns or is replaced, since his appointment is made on their **advice**.

89. (a)

- **Statement 1 is correct: Article 67** mentions that the **Vice-President shall hold office for a term of five years** from the date on which he enters upon his office. It further states that **notwithstanding the expiration of his term, the Vice-President shall continue to hold office until his successor enters upon his office.**
- **Statement 2 is not correct:** As per **Article 71 of the Constitution**, all **disputes regarding the election of the President and Vice-President are inquired into and decided by** the **Supreme Court of India**, whose decision shall be final. They are not decided by the Election Commission.
- **Statement 3 is not correct: Article 100** states that **all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than** the Speaker or **person acting as Chairman** or Speaker. The **Chairman** or Speaker, or person acting as such, shall not vote in the first instance, but **shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes. Thus, while acting as Chairperson of the Rajya Sabha, the Vice-President has a casting vote in case of a tie.**

90. (b)

- **Statement 1 is correct:** An ordinance cannot be issued to amend a provision of the Constitution that requires amendment under Article 368.
- **Statement 2 is not correct:** The President can issue an ordinance when either or both Houses of Parliament are not in session. The term "not in session" includes when a House is prorogued or dissolved. So, if Lok Sabha is prorogued but Rajya Sabha is still in session, an Ordinance can be issued.
- **Statement 3 is correct:** The President can withdraw an Ordinance at any time. However, his power of ordinance-making is not a discretionary power, and he can promulgate or withdraw an Ordinance only on the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister.

91. (d)

- **Option (d) is the correct answer:** According to Article 330 of the Constitution, the present allocation of seats in the Lok Sabha reserved for the Scheduled Castes (SCs) and the Scheduled Tribes (STs) is based on the 2001 Census till the time relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published.

92. (b)

- **Statement 1 is correct:** A **Censure Motion** can be moved against an **individual minister** or against a specific policy/act of the government. In contrast, a **No-confidence Motion** can be moved against the entire **Council of Ministers.**
- **Statement 2 is not correct:** A **Censure Motion** can only be introduced in the **Lok Sabha**, not in either House. Similarly, a **No-confidence Motion** can also be introduced only in the Lok Sabha, since the Council of Ministers is collectively responsible to the **Lok Sabha**.

- **Statement 3 is correct:** If a **Censure Motion** is passed, the Council of Ministers is not bound to resign, as it only expresses disapproval or strong criticism. However, if a **No-confidence Motion** is passed, the entire **Council of Ministers must resign collectively,** as they lose the confidence of the House.

93. (d)

- **Statement 1 is correct:** Article 158(3) provides that the emoluments and allowances of the Governor shall be determined by **Parliament by law**. Until such law is made, they are as specified in the **Second Schedule**.
- **Statement 2 is correct:** Article 158(3A) says that if the same person is appointed as Governor of **two or more States**, the emoluments and allowances shall be allocated among the States in such proportion as the **President may determine**.
- **Statement 3 is correct:** The emoluments and allowances of the Governor are **charged on the Consolidated Fund of the State**, and they cannot be diminished during the Governor's term of office .

94. (d)

- **1 is correct:** The **State Election Commissioner** is appointed by the Governor. However, he/she can be removed only by the **President**, in the same manner and on the same grounds as a Judge of a High Court.
- **Statement 2 is correct:** Members of the **State Human Rights Commission** are appointed by the Governor but they can be removed only by the **President**, on grounds such as insolvency, infirmity of mind/body, or proven misbehavior.
- **Statement 3 is correct:** Members of the **State Public Service Commission (SPSC)** are appointed by the Governor. But they can be removed only by the **President** , usually after an inquiry by the Supreme Court in case of misbehavior.

95. (a)

- **Statement 1 is correct:** The **Constitution (Article 67(b))** states that the **Vice-President** can be **removed** by a **resolution** passed by the **Rajya Sabha** and **agreed to** by the **Lok Sabha**. However, it does **not specify any grounds for removal** (unlike the **President**, who can be **impeached** only for **"violation of the Constitution"**).
- **Statement 2 is not correct:** The **removal resolution can only be introduced in the Rajya Sabha** (Article 67(b)). The Lok Sabha only has to **agree** to it after Rajya Sabha passes it.
- **Statement 3 is not correct:** The resolution must be passed by a **majority of all the then members of the Rajya Sabha** (absolute majority), and then **agreed to by a simple majority** in the Lok Sabha. It is **not required** that both Houses pass it by an absolute majority.
- **Statement 4 is not correct: Nominated members can participate in the Vice-President's removal**. However, they can also participate in his election (unlike the President's election, where they cannot vote).

96. (a)

- **Statement 1 is correct:** The Inter-State Council is a **constitutional body**. Article 263 of the Constitution provides for the **establishment** of such a council, making this statement correct.
- **Statement 2 is correct:** Under Article 263, the **President** is empowered to **establish** the Inter-State Council if it appears that public interest would be served by such a body. The duties, structure, and procedure of the Council are also defined by the President. This confirms that the statement is correct.
- **Statement 3 is not correct:** There is **no mention** in Article 263 that the Inter-State Council is a **permanent body** or that it must meet **at least once every year**. Since this detail is not present in the raw content provided, the statement cannot be considered correct.

97. (d)

- **Statement 1 is not correct:** *Article 84(b)* prescribes the minimum age as **30 years for Rajya Sabha** and **25 years for Lok Sabha**. This applies to both elected and nominated members. There is **no requirement of 35 years** for nomination.
- **Statement 2 is correct:** A person must be an **elector for any Parliamentary constituency in India** to be qualified for election to Lok Sabha.
- **Statement 3 is correct:** The seats in Lok Sabha are allotted to States in such a manner that, as far as practicable, the ratio between the number of seats and the population of each State is the same throughout India.

98. (c)

- **Option (a) is not correct:** The Prime Minister takes the **oath of office and secrecy** under Article 75(4). The wording is: to "bear true faith and allegiance to the Constitution" and to "faithfully discharge duties," but **does not include the phrase 'to protect and defend the Constitution'**.
- **Option (b) is not correct:** Under Article 99, MPs take oath to "bear true faith and allegiance to the Constitution" and to "uphold the sovereignty and integrity of India."
- **Option (c) is correct:** As per Article 159, the Governor swears: *"...to **preserve, protect and defend the Constitution** and the law and to devote myself to the service and well-being of the people of the State."*
- Thus, the Governor's oath **explicitly mentions 'protect and defend the Constitution.'**
- **Option (d) is not correct:** Speaker is elected by members of Lok Sabha (Article 93).
- He/She does not take a **separate constitutional oath** as Speaker. The only oath taken is that of being a Member of Parliament under Article 99.

99. (d)

- **Statement 1 is not correct:** Article 249 empowers **Parliament** to **make laws** on a subject in the **State List**, if the **Rajya Sabha** passes a resolution (by 2/3rd majority of members present and voting) declaring it necessary in the **national interest**. But this is only an **enabling provision**, not a compulsion. Parliament is **not bound** to legislate; it only gets the **power** to do so.
- **Statement 2 is not correct:** Rajya Sabha (Council of States) may pass a resolution (by 2/3rd majority of members present and voting) declaring it necessary in the national interest for Parliament to legislate on. Once passed, Parliament is empowered (not bound) to make laws for the whole or any part of India on that matter. **A resolution remains in force for a maximum of one year (as specified in the resolution).** It can be renewed by passing a fresh resolution in the same manner, each renewal valid for one year. **A law made by Parliament under this Article ceases to operate after 6 months from the date the resolution itself ceases.** Hence, such laws are **not permanent** by default.

100. (d)

- **Statement I is not correct:** MPs enjoy freedom from arrest **only in civil cases** during a session of Parliament (and 40 days before and after).
- They can **be arrested in criminal cases** even during the session (e.g., murder, corruption, preventive detention).
- **Statement II is correct:** Privileges of MPs are to be defined by Parliament by law. Until then, they continue to be those which were in force **immediately before the commencement of the 44th Constitutional Amendment Act, 1978.**

■■■■

पेपर-I | सेक्शनल टेस्ट-2

राजव्यवस्था, शासन तथा समसामयिक मामले (फ़रवरी 2025)

1. (c)

- **कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है:** किसी भी सांसद (चाहे वे लोक सभा के हों अथवा राज्य सभा के) के मत का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों के कुल मूल्य को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। **फलस्वरूप, प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य समान होता है, चाहे वे किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हों अथवा किसी भी सदन से संबंधित हों।**

$$\text{Value of vote of an MP} = \frac{\text{Total value of votes of all MLAs}}{\text{Total elected MPs (LS + RS)}}$$

$$\text{सांसद के मत का मूल्य} = \frac{\text{सभी विधायकों के मतों का कुल मूल्य}}{\text{कुल निर्वाचित सांसद (लोक सभा + राज्य सभा)}}$$

- **कथन 3 सही है:** एक विधायक के मत का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि संबंधित राज्य की जनसंख्या को वहाँ के निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या से विभाजित कर, प्राप्त संख्या को 1/1000 से गुणा किया जाता है। सामान्यतः, एक सांसद के मत का मूल्य एक विधायक के मत से अधिक होता है, क्योंकि सभी विधायकों को आवंटित कुल मत-मूल्य अपेक्षाकृत कम संख्या में सांसदों के बीच विभाजित किया जाता है। इसी कारण, राजस्थान के एक लोक सभा सदस्य का मत-मूल्य राजस्थान के एक विधायक की तुलना में अधिक है। वर्तमान समय में प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य 700 है, जबकि विधायकों के मत का मूल्य राज्यों के अनुसार 7 (सिक्किम) से लेकर 208 (उत्तर प्रदेश) तक भिन्न होता है। राजस्थान के एक विधायक के मत का मूल्य वर्तमान में 129 है।

$$\text{Value of vote of an MLA} = \frac{\text{Population of State (1971 Census)}}{\text{Total elected MLAs of State} \times 1000}$$

$$\text{विधायक के मत का मूल्य} = \frac{\text{राज्य की जनसंख्या (1971 की जनगणना)}}{\text{राज्य के कुल निर्वाचित विधायक} \times 1000}$$

- **कथन 4 सही है: जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, किसी विधायक के मत का मूल्य संबंधित राज्य की जनसंख्या तथा उस राज्य की विधान सभा में निर्वाचित विधायकों की संख्या पर आधारित होता है। यही कारण है कि विभिन्न राज्यों के बीच विधायकों के मत का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है।** उदाहरणस्वरूप, उत्तर प्रदेश और बिहार की जनसंख्या तथा विधायकों की संख्या में अंतर होने के कारण उनके विधायकों के मत का मूल्य समान नहीं हो सकता।

- **अतिरिक्त जानकारी:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के तहत:
  - राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी।
  - समग्र रूप से राज्यों और संघ के मध्य समतुल्यता होनी चाहिए।

2. (b)

- **कथन 1 और 2 सही हैं: संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a)** में यह व्यवस्था की गई है कि **किसी राज्य की मंत्रिपरिषद् में, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, उस राज्य की विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं** होगी। तथापि, यह भी प्रावधानित है कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद् का आकार, **मुख्यमंत्री सहित, बारह से कम नहीं होगा।** यह संवैधानिक प्रावधान वर्ष **2003 में 91वें संशोधन अधिनियम** द्वारा शामिल किया गया था।
- **कथन 3 सही नहीं है:** अनुच्छेद 164(1) के अनुसार, जनजातीय कल्याण के लिए एक पृथक् मंत्री की व्यवस्था केवल छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में की गई है। यह प्रावधान पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक राज्य पर लागू नहीं होता। इन राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री को अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण अथवा किसी अन्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में किए गए 94वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बिहार राज्य को इस प्रावधान से हटा दिया गया था।
- **अतिरिक्त जानकारी:**
  - मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं।
  - राज्य की मंत्रिपरिषद् राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर बनी रहती है।
  - राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
  - राज्य मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते राज्य के विधानमंडल द्वारा विनिर्धारित किए जाते हैं, और जब तक ऐसा विनिर्धारण नहीं किया जाता, तब तक उनका निर्धारण संविधान की दूसरी अनुसूची के अनुसार होता है।

3. (b)

- **कथन 1 सही नहीं है:** मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन; विधान सभा (निम्न सदन) अथवा विधान परिषद् (उच्च सदन, जहाँ यह विद्यमान हो का सदस्य हो सकता है। ऐसा व्यक्ति, जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे भी मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तथापि, ऐसी स्थिति में उसे नियुक्ति की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर किसी भी सदन (चुनाव अथवा नामांकन के माध्यम से) की सदस्यता प्राप्त करनी अनिवार्य है; अन्यथा, निर्धारित अवधि के पश्चात् उसका मंत्री पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
- **कथन 2 सही है:** मुख्यमंत्री के साथ-साथ अन्य मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।

4. (a)

- **विकल्प (a) सही उत्तर है:** दिए गए विकल्पों में से केवल राज्य सभा के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य ही तीनों निर्वाचन प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं; भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन, तथा राज्य सभा के उप-सभापति का चुनाव।

विधायक की श्रेणी	राष्ट्रपति का निर्वाचन	उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन	राज्य सभा के उप-सभापति का चुनाव
राज्य सभा के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य	हाँ	हाँ	हाँ
लोक सभा के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित	हाँ	हाँ	नहीं

सदस्य			
राज्य सभा के मनोनीत सदस्य	नहीं	हाँ	हाँ
केंद्र-शासित प्रदेश दिल्ली की विधान सभा के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य	हाँ	नहीं	नहीं

5. (d)

- **कथन-I सही नहीं है:** लोक सभा में कार्यवाही संचालित करने हेतु गणपूर्ति (Quorum) कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ भाग होती है, जिसमें पीठासीन अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। 18वीं लोक सभा में, जहाँ कुल 543 सदस्य हैं, गणपूर्ति 54.3 होती है, जिसे पूर्णांकित कर 55 माना जाता है। चूँकि कथन में यह उल्लेखित है कि अध्यक्ष के अतिरिक्त 54 सदस्य उपस्थित हैं, अतः अध्यक्ष सहित कुल संख्या 55 हो जाती है। इस प्रकार, कार्यवाही का संचालन संभव है और कथन-I सही नहीं है।
- **कथन-II सही है:** संसद के किसी भी सदन की बैठक हेतु गणपूर्ति वास्तव में पीठासीन अधिकारी सहित, संबंधित सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ भाग होती है। इसका तात्पर्य है कि लोक सभा के लिए गणपूर्ति 55 सदस्यों की तथा राज्य सभा के लिए 25 सदस्यों की निर्धारित है।
- **अतिरिक्त जानकारी:**
  - **संयुक्त बैठक में गणपूर्ति:** संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का दसवाँ हिस्सा होती है।
  - **राज्य विधानमंडल में गणपूर्ति:** जब तक राज्य विधानमंडल कोई अलग व्यवस्था न करे, उसके किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति दस सदस्य या सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ हिस्सा (जो संख्या अधिक हो) मानी जाएगी।
  - **गणपूर्ति का अभाव:** यदि सदन की किसी बैठक में आवश्यक गणपूर्ति पूरी न हो, तो पीठासीन अधिकारी का दायित्व है कि वह बैठक को तुरंत स्थगित कर दे अथवा गणपूर्ति पूर्ण होने तक स्थगित रखे।

6. (b)

- **कथन 1 और 2 सही हैं:** भारत के संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार, राज्य सभा (राज्यों की परिषद्) में सीटों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं होगी। इसमें राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले बारह सदस्यों, और राज्यों के तथा संघ राज्यक्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों, से मिलकर बनेगी।
  - तथापि, राज्य सभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य विभिन्न राज्यों तथा दिल्ली, पुदुच्चेरी और जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र-शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं।
- **कथन 3 सही नहीं है:** अनुच्छेद 80(4) के अनुसार, राज्य सभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, न कि विधान सभा और विधान परिषद् दोनों द्वारा।
- **कथन 4 सही नहीं है:** संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र-शासित प्रदेशों को राज्य सभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। इन सीटों का आवंटन मुख्यतः प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तथापि, सभी केंद्र-शासित प्रदेशों को समान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। वर्तमान में राज्य सभा में केवल दिल्ली, पुदुच्चेरी और जम्मू-कश्मीर केंद्र-शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है।
- **अतिरिक्त जानकारी:**
  - **राज्य सभा में राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन:** राज्य सभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।

- **राज्य सभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन:** राज्य सभा में संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएँगे, जो संसद विधि द्वारा विहित करे।
- **12 सदस्यों का नामनिर्देशन:** राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्: साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा।

7 (c)

- **विकल्प (c) सही उत्तर है:** दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) तथा वर्तमान में लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अंतर्गत सभी अपराधों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: (i) संज्ञेय अपराध तथा (ii) गैर-संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वह अपराध है, जिसकी जाँच पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के कर सकता है और बिना वारंट के गिरफ़्तारी कर सकता है। ऐसे अपराधों में पुलिस का यह दायित्व होता है कि शिकायत प्राप्त होने या विश्वसनीय सूचना मिलने पर वह तुरंत कार्रवाई करे, अपराध स्थल का निरीक्षण करे, तथ्यों की जाँच करे, अपराधी को गिरफ़्तारी करे तथा उसे संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। सामान्यतः, संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं।
- असंज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं, जिनकी जाँच पुलिस बिना सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं कर सकती। ऐसे मामलों में पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त किए बिना जाँच आरंभ नहीं करती। असंज्ञेय अपराध सामान्यतः संज्ञेय अपराधों की तुलना में कम गंभीर प्रकृति के होते हैं।
- **अतिरिक्त जानकारी:**
  - **शमनीय अपराध:** शमनीय अपराध वह अपराध होता है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति (शिकायतकर्ता) अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को वापस लेने अथवा खारिज करने का निर्णय ले सकता है। किसी अपराध के शमन का परिणाम अनिवार्य रूप से अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के निरसन (खारिज होना) के रूप में होता है।

8. (c)

- **राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए आवश्यक योग्यताएँ संविधान के अनुच्छेद 173 में निर्दिष्ट की गई हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य योग्यताएँ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में विनिर्दिष्ट की गई हैं।**
- **कथन 1 सही है:** जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी राज्य की विधान परिषद् में निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीट के लिए तभी योग्य होगा, जब **वह संबंधित राज्य के किसी विधान सभा क्षेत्र का निर्वाचक** हो। यही प्रावधान राज्य विधान सभा का सदस्य बनने की योग्यता के लिए भी लागू होता है।
- **कथन 2 सही है:** संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, विधान परिषद् में राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्; साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित किए जाने हेतु राज्य की विधान परिषद् की किसी सीट के लिए तभी योग्य होगा, जब वह उस राज्य का सामान्यतः निवासी हो।

9. (a)

- **1 और 3 सही हैं:** संविधान के **अनुच्छेद 88 के तहत, प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा।**
- **2 सही नहीं है:** यद्यपि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग हैं, क्योंकि दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक उनकी स्वीकृति के बिना कानून का रूप नहीं ले सकता, तथापि राष्ट्रपति स्वयं किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। इस कारण उन्हें संसद में बैठने, उसकी बैठकों में उपस्थित होने अथवा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं है।

तथापि, संविधान के अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन अथवा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकते हैं। इसी प्रकार, अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति, लोक सभा के प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे।

- **4 सही नहीं है**: अध्यक्ष लोक सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं और स्वयं उस सदन के सदस्य होते हैं। उन्हें लोक सभा में बोलने तथा मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु वे राज्य सभा में न तो बोल सकते हैं और न ही मतदान कर सकते हैं।
- **5 सही नहीं है:** उप-सभापति राज्य सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं और स्वयं उसी सदन के सदस्य होते हैं। उन्हें राज्य सभा में बोलने तथा मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु वे लोक सभा में न तो बोल सकते हैं और न ही मतदान कर सकते हैं।

10. (a)

- **कथन 1 सही है:** संविधान के **अनुच्छेद 203** के अनुसार, **राज्यपाल की सिफ़ारिश के अलावा अनुदान की कोई माँग नहीं की जाएगी**।
- **कथन 2 सही है: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217** के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान नियुक्ति-पद्धति तथाकथित तीन-न्यायाधीश प्रकरण (Three Judges Case) से विकसित हुई है, जिसमें यह व्यवस्था स्थापित की गई कि राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत, संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा (यदि मामला उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का हो, मुख्य न्यायाधीश का नहीं) संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके नियुक्ति करेंगे।
- **कथन 3 सही नहीं है:** यद्यपि राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तथापि उनकी पदच्युति का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास निहित है, राज्यपाल के पास नहीं। **अनुच्छेद 317 के अनुसार, राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को उन्हीं आधारों और समान प्रक्रिया के माध्यम से हटा सकता है, जिन पर वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य को पद से हटा सकता है।** इन आधारों में निम्नलिखित शामिल हैं; यदि वह:
  - दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है,या
  - अपनी पदावधि में अपने पद के कर्त्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है या
  - राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा।

11. (c)

- **कथन 1 सही नहीं है:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद् की सलाह पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं मानी जाती।
  - तथापि, यह ध्यान देने योग्य है कि जब किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू करने की संस्तुति करता है, तो वह संस्तुति उसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आती है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दण्डादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। तथापि, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं, बल्कि मंत्रिपरिषद् की सहायता और सलाह पर करते हैं।
  - तथापि, यह ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करता है तथा इसके लिए उसे मंत्रिपरिषद् की सलाह की आवश्यकता नहीं होती।

- **कथन 3 सही है:** संविधान (44वाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह मंत्रिपरिषद् से प्राप्त किसी भी सलाह पर पुनर्विचार का अनुरोध कर सके, और इस प्रक्रिया में अपने विवेक का प्रयोग कर सके। तथापि, पुनर्विचार उपरांत मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदत्त अंतिम सलाह का पालन करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। यद्यपि मंत्रिपरिषद् पूर्ववत् अपनी वही सलाह पुनः प्रेषित कर सकती है, तथापि राष्ट्रपति द्वारा किया गया पुनर्विचार का अनुरोध संवैधानिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं सारगर्भित माना जाता है।

12. (b)

- सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भारत में संसदीय शासन-व्यवस्था की आधारशिला है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सरकार सदैव विधायिका के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह बनी रहे।
- **कथन 1 सही है:** यह सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रत्यक्ष परिणाम है कि यदि सरकार लोक सभा में बहुमत का विश्वास खो देती है, तो वह सत्ता में बनी नहीं रह सकती और उसे अनिवार्यतः त्याग-पत्र देना होता है। सामान्यतः यह स्थिति अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अभिव्यक्त होती है।
- **कथन 2 सही है:** यह भी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रत्यक्ष अनुपालन है। इसका आशय यह है कि लोक सभा की दृष्टि में संपूर्ण मंत्रिपरिषद् एक संयुक्त इकाई के रूप में कार्य करती है। निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, अतः सभी मंत्री उन निर्णयों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, चाहे वे आंतरिक विचार-विमर्श के दौरान व्यक्तिगत रूप से असहमत ही क्यों न रहे हों। इसी कारण मंत्रिपरिषद् के संदर्भ में कहा जाता है कि "वे साथ तैरते हैं और साथ डूबते हैं।"
- **कथन 3 सही है:** अविश्वास प्रस्ताव वह प्राथमिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से लोक सभा मंत्रिपरिषद् में अपने विश्वास की हानि व्यक्त करती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि मंत्रिपरिषद् लोक सभा में बहुमत का विश्वास खो देती है, तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद् को इस्तीफ़ा देना होगा।
- **कथन 4 सही नहीं है: मंत्रिपरिषद् द्वारा बहुमत खो देने की स्थिति में लोक सभा का भंग होना अनिवार्य नहीं है।** ऐसे प्रसंगों में राष्ट्रपति, संवैधानिक परंपरा के अनुसार, किसी अन्य दल अथवा गठबंधन को सरकार गठन हेतु आमंत्रित कर सकते हैं। अतः, सदन का विघटन स्वतःस्फूर्त परिणाम नहीं होता।

13. (d)

1, 2 और 3 सही हैं: भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार, प्रधानमंत्री का यह कर्त्तव्य होगा;

(क) संघ के कार्यकलाप **के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित** करे;

(ख) संघ के कार्यकलाप के **प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी, जो जानकारी** राष्ट्रपति माँगें, वह दे; और

(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है, किंतु मंत्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद् के समक्ष विचार के लिए रखे।

14. (a)

- **कथन 1 सही है: अनुच्छेद 163** में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि राज्यपाल को संविधान द्वारा निर्दिष्ट कुछ परिस्थितियों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने की अनुमति है। इसके विपरीत, राष्ट्रपति के संबंध में यह अपेक्षित है कि वे अनुच्छेद 74 के अधीन सदैव मंत्रिपरिषद् की सहायता और सलाह पर कार्य करेंगे। अतः, राज्यपाल के समान राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के लिए कोई प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रावधान विद्यमान नहीं है, यद्यपि व्यवहारतः राष्ट्रपति कुछ परिस्थितिजन्य विवेकाधिकारों का प्रयोग करते हैं।

- **कथन 2 सही नहीं है: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा मंत्रिपरिषद् की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया।** तथापि, यह व्यवस्था राज्यपाल पर लागू नहीं होती। राज्यपाल के पास अब भी अनुच्छेद 163 के अंतर्गत निर्दिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों में विवेकाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति विद्यमान है।

15. (b)

- **विधान परिषद् के बारे में:** यह द्विसदनीय राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। वर्तमान में भारत के केवल छह राज्यों में विधान परिषद् विद्यमान है; उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
- **कथन 1 और 2 सही हैं: राज्य विधान परिषद् की संरचना** इस प्रकार है:
  - लगभग **एक-तिहाई सदस्य** राज्य के स्थानीय निकायों (नगरपालिकाएँ, जिला परिषद् आदि) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। **इसलिए, कथन 1 सही है।**
  - लगभग **एक-तिहाई सदस्य** राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा, ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं, जो स्वयं विधान सभा के सदस्य न हों। **इसलिए, कथन 2 सही है।**
  - लगभग **एक-बारहवाँ हिस्सा** उन स्नातकों द्वारा चुना जाता है, जिनके पास कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव हो तथा जो राज्य के निवासी हों।
  - लगभग **एक-बारहवाँ हिस्सा** उन शिक्षकों द्वारा चुना जाता है, जिनके पास न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो और जिनका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम न हो। **इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।**
  - कुल सदस्यों का लगभग **एक-छठा भाग** राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हों। **इसलिए, कथन 4 सही नहीं है।**

16. (a)

- **कथन 1 सही है:** यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में सात सदस्य देशों द्वारा अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। **वर्तमान में इसके सदस्य देशों में आइसलैंड, लिचेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं। EFTA, यूरोप के तीन प्रमुख आर्थिक समूहों में से एक है, अन्य दो समूह यूरोपीय संघ और ब्रिटेन हैं।** EFTA देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार **स्विट्ज़रलैंड** है, जबकि इसके बाद **नॉर्वे** का स्थान आता है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** हाल ही में संपन्न भारत- EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA) एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, **क्योंकि इसके माध्यम से EFTA भारत के साथ औपचारिक व्यापार समझौता करने वाला पहला यूरोपीय ब्लॉक बन गया है।**
- **अतिरिक्त जानकारी:** भारत- EFTA TEPA की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ:
  - पहली बार भारत चार विकसित देशों, जो यूरोप का एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक समूह है, के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है।
  - इस एफटीए के इतिहास में पहली बार अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर के निवेश और 1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियों की बाध्यकारी प्रतिबद्धता दी गई है।
  - ईएफटीए ने अगले 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने और ऐसे निवेशों के माध्यम से भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार सृजन को सुगम बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेश शामिल नहीं है।

- एफटीए के इतिहास में पहली बार लक्ष्य-उन्मुख निवेश को बढ़ावा देने और रोज़गार सृजन के प्रति कानूनी प्रतिबद्धता व्यक्त की जा रही है।
- इस समझौते में 14 अध्याय शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से वस्तुओं से संबंधित बाज़ार पहुँच, उत्पत्ति के नियम, व्यापार सुविधा, व्यापार उपाय, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएँ, निवेश प्रोत्साहन, सेवाओं पर बाज़ार पहुँच, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार और सतत् विकास, तथा अन्य कानूनी और क्षैतिज प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

17. (a)

- **संदर्भ:** हाल ही में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में "जेवन्स विरोधाभास" की अवधारणा पर व्यापक चर्चा हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने भी इस 160 वर्षीय आर्थिक विरोधाभास के एआई के क्षेत्र में प्रकट होने पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है।
- **विकल्प (a) सही उत्तर है:** अर्थशास्त्री विलियम स्टेनली जेवन्स द्वारा वर्ष 1865 में प्रस्तावित “जेवन्स विरोधाभास” के अनुसार, किसी संसाधन के उपयोग की दक्षता में सुधार प्रायः उस संसाधन की कुल खपत को कम करने के बजाय बढ़ा देता है। इसका कारण यह है कि बढ़ी हुई दक्षता संसाधन के उपयोग की प्रभावी लागत को घटा देती है, जिससे उसकी माँग बढ़ती है और परिणामस्वरूप कुल उपयोग में वृद्धि होती है।
  - उदाहरण के लिए, अधिक ईंधन-कुशल वाहन चलाने से यात्रा की लागत कम हो जाती है, जिससे लोग अधिक यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। परिणामस्वरूप, दक्षता में वृद्धि के बावजूद कुल ईंधन की खपत में वृद्धि हो जाती है।
- यह विरोधाभास उस सामान्य धारणा को चुनौती देता है कि दक्षता में सुधार स्वचालित रूप से संसाधनों के संरक्षण की ओर ले जाता है, और इसका पर्यावरण तथा ऊर्जा नीतियों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

18. (a)

- **कथन 1 सही है:** अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत के महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहते हैं।
- **कथन 2 सही नहीं है:** हालाँकि परंपरागत रूप से भारत का महान्यायवादी तब इस्तीफ़ा देता है, जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद् इस्तीफ़ा देती है, क्योंकि वह इसी मंत्रिपरिषद् द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु **संविधान के अनुसार उसे इस्तीफ़ा देने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।**
- **कथन 3 सही नहीं है:** भारत का महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक अधिवक्ता नहीं होता और उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता। अतः उन्हें निजी वकालत करने की अनुमति प्राप्त है।
- **भारत के महान्यायवादी के बारे में अतिरिक्त जानकारी:**
  - भारत सरकार की अनुमति के बिना वह किसी भी कंपनी या निगम में निदेशक का पद स्वीकार नहीं कर सकता।
  - उसे भारत सरकार के विरुद्ध मामलों में सलाह या प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए।
  - वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमों में अभियुक्तों का बचाव नहीं कर सकते।

19. (a)

- **1 और 4 सही हैं:** संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकते हैं, यदि:
  - किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारेषित किए जाने के पश्चात्,
    - (क) दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकर कर दिया गया है, या
    - (ख) विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, या
    - (ग) दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तिथि से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना छह मास से अधिक बीत गए हैं।

- **कथन 2 सही नहीं है:** अनुच्छेद 108 स्पष्ट रूप से धन विधेयकों को संयुक्त बैठकों के दायरे से बाहर रखता है। धन विधेयक में संशोधनों पर असहमति उत्पन्न होने की स्थिति में सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की जा सकती। राज्य सभा के पास न तो धन विधेयक में संशोधन करने का अधिकार है और न ही इसे अस्वीकार करने का। इसके अतिरिक्त, राज्य सभा इस प्रकार के विधेयक को 14 दिनों से अधिक समय तक स्थगित भी नहीं कर सकती। अतः, धन विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं हो सकता।
- **कथन 3 सही नहीं है:** संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयकों पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 108 केवल साधारण विधेयकों पर लागू होता है और इसका विस्तार धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों पर नहीं होता। संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करने के लिए आवश्यक है कि दोनों सदन इन्हें अलग-अलग पारित करें।

20. (c)

- **विकल्प (c) सही उत्तर है: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003** के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद् में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

21. (c)

- **कथन 1 सही है:** लोक सभा की नियम समिति की अनुशंसाओं पर संसद में वर्ष 1993 में 17 विभाग-संबंधी स्थायी समितियाँ गठित की गई थी। वर्ष 2004 में ऐसी 7 और समितियों का गठन हुआ। इस प्रकार इन समितियों की संख्या बढ़कर 24 हो गई। स्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद् को) को अधिक उत्तरदायी बनाना है, विशेषकर वित्तीय दायित्व को। ये समितियाँ संसद की बजट पर अधिक सार्थक चर्चा में सहायक होती हैं। इन 24 स्थायी समितियों के कार्यक्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं।
- **कथन 2 सही है:** प्रत्येक स्थायी समिति में 31 सदस्य (21 लोक सभा तथा 10 राज्य सभा से) होते हैं।
- **कथन 3 सही नहीं है:** लोक सभा के सदस्यों का चुनाव लोक सभा अध्यक्ष सदस्यों में से करते हैं, जबकि राज्य सभा के सदस्य सभापति द्वारा चुने जाते हैं।
- **DRSCs के बारे में अतिरिक्त जानकारी:**
  - इन समितियों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता।
  - 24 स्थायी समितियों में से 8 समितियाँ राज्य सभा तथा 16 समितियाँ लोक सभा के अंतर्गत कार्य करती हैं।
  - किसी भी स्थायी समिति में कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता।

22. (b)

- **विकल्प (b) सही उत्तर है:** संविधान का अनुच्छेद 166 यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल राज्य सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए तथा मंत्रियों के बीच उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएँगे। यह उन कार्यों पर लागू होगा, जिनमें संविधान के अनुसार राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करना आवश्यक नहीं है।

23. (b)

- **कथन 1 सही नहीं है:** कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। कैबिनेट सचिवालय को आवंटित भारत सरकार का कार्य प्रधानमंत्री को आवंटित माना जाता है। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम,

1961 के अंतर्गत कैबिनेट सचिवालय को जो कार्य सौंपे गए हैं, उनमें शामिल हैं: (i) मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करना; और (ii) कार्य-नियमों से संबंधित कार्य।

- **कथन 2 सही है:** सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है।

24. (d)

- **बिंदु 1 सही नहीं है: अनुच्छेद 174** के तहत **राज्यपाल राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करता हैं।** राज्य विधानमंडल के दो सत्रों के बीच **अधिकतम अंतराल छह महीने से अधिक नहीं** हो सकता, अर्थात् राज्य विधानमंडल को वर्ष में कम-से-कम दो बार अधिवेशन करना चाहिए। राज्य विधानमंडल का एक सत्र कई बैठकों से मिलकर बनता है।
- **बिंदु 2 सही नहीं है: अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अर्थ है, राज्य विधानमंडल की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना। यह पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है।**
- **बिंदु 3 सही है: स्थगन किसी बैठक में कार्य को एक निश्चित समय के लिए स्थगित कर देता है**, जो घंटों, दिनों या हफ्तों तक हो सकता है। स्थगन और अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है।
- **बिंदु 4 सही नहीं है: अनुच्छेद 174** में उल्लेख है कि **राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदनों का सत्रावसान** करता है। इससे सदन का सत्र समाप्त हो जाता है, लेकिन सदन स्वयं नहीं। ऐसा **पीठासीन अधिकारी** द्वारा सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद किया जाता है।
- **बिंदु 5 सही है: अनुच्छेद 174** के अनुसार, **विधान सभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास** होती है। इससे मौजूदा सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नए चुनाव कराने की आवश्यकता होती है।

25. (c)

- **कथन 1 सही है:** केंद्र सरकार को भारत की संचित निधि के आधार पर भारत के भीतर तथा विदेश से ऋण लेने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त वह गारंटी भी दे सकती है। ये सभी शक्तियाँ संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन होती हैं, हालाँकि अब तक इस संबंध में कोई कानून पारित नहीं किया गया है।
- वहीं, राज्य सरकार को राज्य की संचित निधि के आधार पर केवल देश के भीतर ही ऋण लेने का अधिकार है। हालाँकि यह ऋण राज्य विधान-मंडल द्वारा कानून के माध्यम से निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही लिया जा सकता है।
- **कथन 2 सही है:** संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार, यदि कोई राज्य सरकार भारत सरकार की देनदार है, तो उसे नया ऋण लेने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है।
- **अतिरिक्त जानकारी:**
  - "राज्य का सार्वजनिक ऋण" भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत एक विषय है।

26. (c)

- **विकल्प (c) सही है:** भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता।

- **भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार हैं:**
  - राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते तथा उनके पद से संबंधित अन्य व्यय।
  - राज्य सभा के सभापति और उप-सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।
  - भारत सरकार पर देय ऋण-भार, जिसमें ब्याज, संचय निधि शुल्क (Sinking fund charges), मोचन शुल्क (Redemption charges) तथा ऋण लेने, ऋण की सेवा (Servicing) और मोचन से संबंधित अन्य व्यय शामिल हैं।
  - किसी भी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या पुरस्कार को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि।
  - उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में देय वेतन, भत्ते और पेंशन।
  - संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में देय पेंशन।
  - किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में देय पेंशन।
  - नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) का वेतन, भत्ते और पेंशन।
  - संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के व्यय, जिनमें आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों को या उनके संबंध में देय वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं।

27. (b)

- **कथन 1 और 2 सही हैं:** द्विसदनीय विधायिका शासन की एक ऐसी प्रणाली है, जहाँ विधायी निकाय दो अलग-अलग सदनों अथवा सभाओं में विभाजित होता है। भारत में, अधिकांश राज्य एकसदनीय हैं, किंतु कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था भी है। वर्तमान में, भारत में केवल छह राज्यों में विधान परिषद् है: **उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।**
- **नोट:** जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 से पहले, जम्मू-कश्मीर में भी द्विसदनीय विधायिका थी। हालाँकि, केंद्र-शासित प्रदेश बनने के बाद, अब यहाँ एक सदनीय विधायिका है।

28. (a)

- **कथन 1 सही है:** राज्य सभा धन विधेयक में संशोधन की सिफ़ारिश कर सकती है, लेकिन उसे न तो संशोधित कर सकती है और न ही अस्वीकार कर सकती है। लोक सभा चाहे तो राज्य सभा की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। यदि लोक सभा किसी भी सिफ़ारिश को स्वीकार नहीं करती, तो विधेयक उसी रूप में पारित माना जाता है, जैसा कि उसे प्रारंभ में लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।
- **कथन 2 सही है:** प्रत्येक धन विधेयक, जब अनुच्छेद 109 के तहत राज्य सभा को प्रेषित किया जाता है और जब अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर लोक सभा अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है, जिसमें यह घोषित किया गया हो कि यह एक धन विधेयक है।
- **कथन 3 सही नहीं है:** धन विधेयक केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

29. (a)

- **कथन 1 सही है:** अंतर-राज्यीय परिषद् भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 263 राज्यों और संघ तथा राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए ऐसी परिषद् की स्थापना का प्रावधान करता है।
- **कथन 2 सही है:** भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 263 के तहत आदेश द्वारा, जब भी सार्वजनिक हित में आवश्यक प्रतीत हो, **अंतर-राज्यीय परिषद्** की स्थापना करने का अधिकार है।
- **कथन 3 सही नहीं है:** संविधान अंतर-राज्यीय परिषद् को स्थायी निकाय नहीं बनाता है, न ही यह अनिवार्य करता है कि इसकी बैठक प्रति वर्ष कम-से-कम एक बार अवश्य हो।
- **अतिरिक्त जानकारी:** संविधान के अनुसार अंतर-राज्यीय परिषद् को निम्नलिखित कर्त्तव्य सौंपे जा सकते हैं:
  - राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच करना और उन पर सलाह देना;
  - ऐसे विषयों की जाँच और चर्चा करना, जिनमें कुछ या सभी राज्यों, या संघ और एक या अधिक राज्यों का साझा हित हो; अथवा
  - ऐसे किसी भी विषय पर सिफ़ारिशें करना, तथा विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफ़ारिशें करना।

30. (b)

कथन 1 सही नहीं है: यह समिति सर्वप्रथम वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम, 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित की गई थी और तब से अस्तित्व में है। वर्तमान में, इसमें 22 सदस्य (लोक सभा से 15 और राज्य सभा से 7) हैं।

कथन 2 सही है: इसके सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, इसमें सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता है।

कथन 3 सही नहीं है: सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। समिति का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जाँच करना है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखा जाता है।

31. (b)

विकल्प (b) सही है: दिए गए विकल्पों में से, राज्य सभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, लेकिन उसके निर्वाचन में नहीं।

सहभागी	राष्ट्रपति का निर्वाचन	राष्ट्रपति पर महाभियोग
राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य	हाँ	हाँ
राज्य सभा के मनोनीत सदस्य	नहीं	हाँ
राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य	हाँ	नहीं
राज्यों की विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य	हाँ	नहीं

32. (c)

कथन 1 और 2 दोनों सही हैं: अनुच्छेद 213 के तहत, 'राज्यपाल' राष्ट्रपति के निर्देश के बिना ऐसा कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा, जिसमें वही प्रावधान शामिल हों, जिन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ रखा जाना आवश्यक माना जाता हो। अनुच्छेद 200 के अनुसार, राज्यपाल की राय में, यदि प्रस्तावित विधेयक उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति, शक्तियों या क्षेत्राधिकार को प्रभावित करता है, तो उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना अनिवार्य है। चूँकि ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति का विचार करना अनिवार्य होता है, इसलिए उसी विषय पर अध्यादेश भी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश के बिना प्रख्यापित नहीं किया जा सकता है।

33. (b)

संदर्भ: 'भारत' वर्ष 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) में 180 देशों में से 96वें स्थान पर रहा, क्योंकि इसका कुल स्कोर एक अंक गिरकर 38 हो गया।

विकल्प (b) सही उत्तर है: भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) एक वार्षिक सूचकांक है, जो देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूद भ्रष्टाचार के आधार पर रैंक प्रदान करता है। इसे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए समर्पित एक गैर-सरकारी संगठन 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' द्वारा संकलित किया जाता है।

सूचकांक के बारे में अन्य जानकारी:

यह सूचकांक 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है, जहाँ "0" अति भ्रष्ट और "100" अत्यंत स्वच्छ है।

भारत के पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान (135) और श्रीलंका (121) की रैंकिंग निम्न रही, जबकि बांग्लादेश की रैंकिंग और भी नीचे 149 रही। चीन 76वें स्थान पर रहा।

डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र होने के करण सूची में सर्वोपरि है। उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर का स्थान है।

34. (d)

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY/पीएम-अजय) के बारे में: यह भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की गई एक व्यापक पहल है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों (SC) का सामाजिक-आर्थिक उत्थान करना है। यह तीन पूर्व केंद्र प्रायोजित योजनाओं, अर्थात् प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY), अनुसूचित जातियों की विशेष केंद्रीय सहायता उपयोजना (SCA to SCSP) और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY) का विलय है।

1 और 2 सही हैं: योजना के लिए पात्रता इस प्रकार है:

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति विभिन्न आय सृजन योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

बुनियादी ढाँचे के विकास के मामले में, 50% या उससे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गाँव इस योजना के तहत अनुदान के पात्र हैं।

जहाँ तक गरीबी रेखा की परिभाषा और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के चयन का संबंध है, पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जाता है।

3 सही है: यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

अतिरिक्त जानकारी: इस योजना के उद्देश्य हैं:

कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोज़गार के अवसर सृजित करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी कम करना।

अनुसूचित जाति बहुल गाँवों में पर्याप्त बुनियादी ढाँचा और अपेक्षित सेवाएँ सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करना।

विशेष रूप से, आकांक्षी जिलों/अनुसूचित जाति बहुल ब्लॉकों और भारत में अन्यत्र, गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएँ देना; आवश्यकतानुसार, आवासीय विद्यालय स्थापित करके साक्षरता बढ़ाना; और विद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों का नामांकन प्रोत्साहित करना।

35. (a)

कथन 1 सही है: एक निजी सदस्य वह सांसद होता है, जो मंत्री नहीं (अर्थात् सरकार/कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता) होता है। इसलिए, मंत्री 'निजी सदस्य विधेयक' पेश नहीं कर सकते हैं।

कथन 2 सही नहीं है: किसी निजी सदस्य द्वारा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

कथन 3 सही नहीं है: लोक सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के अनुसार, किसी निजी सदस्य को विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सूचीबद्ध करने से न्यूनतम एक माह पहले सूचना देनी होगी।

कथन 4 सही नहीं है: लोक सभा और राज्य सभा, दोनों के सदस्य (जो मंत्री नहीं हैं), निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत और पारित कर सकते हैं।

36. (c)

पंक्ति 1 सही सुमेलित है: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) के साथ-साथ राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) और राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (बराक नदी) के माध्यम से भी लंबी दूरी के माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए 'जलवाहक योजना' शुरू की है। 'जलवाहक योजना' भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (IBP) मार्ग के माध्यम से NW-1 (गंगा नदी), NW-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) और NW-16 (बराक नदी) पर जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन करते समय किए गए कुल परिचालन व्यय के 35% तक प्रतिपूर्ति प्रदान करती है।

पंक्ति 2 सही सुमेलित है: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 'समुद्रयान मिशन' शुरू किया है। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र की खोज के लिए वैज्ञानिक संवेदकों और उपकरणों के एक समूह के साथ समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक तीन मनुष्यों को ले जाने के लिए एक स्व-चालित मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित करना है।

पंक्ति 3 सही सुमेलित है: 'सागरमाला कार्यक्रम' भारत के 7,500 किमी लंबे समुद्र तट, 14,500 किमी लंबे संभावित नौगम्य जलमार्गों और प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थान का लाभ उठाकर देश में बंदरगाह-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है। यह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम बुनियादी ढाँचे के निवेश के साथ EXIM और घरेलू व्यापार के लिए रसद (Logistics) लागत को कम करना है।

37. (a)

कथन 1 सही है: किसान पहचान-पत्र एक आधार-लिंक्ड विशिष्ट डिजिटल पहचान है, जो राज्य के भू-अभिलेखों से गतिशील रूप से संबद्ध होती है। इसके अलावा, इसमें जनसांख्यिकी, बोई गई फ़सलों, पशुधन स्वामित्व और स्वामित्व विवरण जैसी जानकारी भी होती है।

कथन 2 सही नहीं है: किसान पहचान-पत्र का निर्माण और रख-रखाव राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

38. (c)

विकल्प (c) सही उत्तर है: लेखानुदान संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत एक संसदीय प्रावधान है। इसका उपयोग तब किया जाता है, जब:

केंद्रीय बजट नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले पारित नहीं होता है।

सरकार अपने नियमित व्ययों (वेतन, सहायिकी, ब्याज भुगतान आदि) को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन आहरण हेतु संसदीय अनुमोदन की माँग करती है।

39. (d)

कथन 1 और 2 सही हैं: भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 में प्रावधान है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेज़ी भाषा में किया जाएगा। संसद में अंग्रेज़ी का प्रयोग मूलतः संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद (अर्थात् 1965 के बाद) समाप्त होना था, जब तक कि संसद इसे आगे जारी रखने के लिए कोई कानून पारित न करे। हालाँकि, राजभाषा अधिनियम, 1963 को 26 जनवरी, 1965 के बाद भी, संघ के आधिकारिक उद्देश्यों और संसदीय कामकाज के लिए हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी के निरंतर उपयोग के लिए अधिनियमित किया गया था।

कथन 3 सही है: राज्य सभा सभापति या लोक सभा अध्यक्ष, या इस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, किसी भी सदस्य को, जो हिंदी या अंग्रेज़ी में पर्याप्त रूप से अपनी बात नहीं रख सकता, सदन को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

40. (c)

कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, मंत्रिपरिषद् के साथ-साथ प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे।

कथन 2 सही है: अनुच्छेद 356 के अनुसार, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद् का त्याग-पत्र स्वतः ही संवैधानिक तंत्र की विफलता का संकेत नहीं होता है। यदि मंत्रिपरिषद् त्याग-पत्र दे देती है, तो राज्य का राज्यपाल सबसे पहले वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना तलाशता है। यदि कोई अन्य दल या गठबंधन यह साबित करे कि उसके पास स्थिर सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत है, तो राज्यपाल उन्हें ऐसा करने के लिए आमंत्रित करेंगे। राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) केवल अंतिम उपाय के रूप में तब लगाया जाता है, जब राज्यपाल की राष्ट्रपति को दी गई रिपोर्ट यह संकेत देती है कि कोई स्थिर सरकार बनने की संभावना नहीं है और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है।

41. (c)

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 156 स्पष्ट प्रावधान करता है कि राज्यपाल अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

कथन 2 सही नहीं है: राज्यपाल की नियुक्ति के दौरान, राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक है, ताकि राज्य में संवैधानिक तंत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके। हालाँकि, यह संविधान में उल्लिखित आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक परिपाटी है, जो वर्षों से विकसित हुई है।

कथन 3 सही है: अनुच्छेद 157 के अनुसार, कोई व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी करने तक राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

कथन 4 सही है: अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।

42. (b)

1 और 3 सही हैं: निम्नलिखित मामलों में, विधान परिषद् की शक्तियाँ और स्थिति सामान्यतः विधान सभा के समान हैं:

साधारण विधेयकों का प्रस्तुतीकरण; हालाँकि, दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में, विधान सभा की इच्छा विधान परिषद् की अपेक्षा प्राथमिक होती है। अतः कथन 1 सही है।

राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों का अनुमोदन; अतः कथन 3 सही है।

राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक जैसे संवैधानिक निकायों की रिपोर्टों पर विचार।

राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार का विस्तार।

2 और 4 सही नहीं हैं: हालाँकि, विधान सभा को निम्नलिखित मामलों में अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं:

विधान परिषद् भारत के राष्ट्रपति और राज्य सभा में राज्य के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

धन विधेयक केवल विधान सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद् में नहीं। विधान परिषद् धन विधेयक में संशोधन कर सकती है या उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। उसे 14 दिनों के भीतर विधेयक को सिफ़ारिशों के साथ या सिफ़ारिशों के बिना, विधान सभा को वापस लौटाना होता है। अतः कथन 4 सही नहीं है।

43. (c)

विकल्प C सही उत्तर है: भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान देने और कुछ मामलों में सज़ा को निलंबित (Suspend), परिहार (Remit) या लघु (Commute) करने की शक्ति प्रदान करता है। परिहार का तात्पर्य सज़ा की अवधि को, उसके स्वरूप में परिवर्तन किए बिना, कम करना है। उदाहरण के लिए, दो वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा को एक वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।

अतिरिक्त जानकारी:

क्षमादान (Pardon): यह सज़ा और दोषसिद्धि, दोनों को समाप्त कर देता है और दोषी को सभी सज़ाओं, दण्डों और अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर देता है।

लघुकरण (Commutation): यह दण्ड के एक रूप को नरम रूप से प्रतिस्थापित करने को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, मृत्युदण्ड को कठोर कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे बाद में साधारण कारावास में भी परिवर्तित किया जा सकता है।

विराम (Respite): यह किसी विशेष कारण, जैसे- किसी अपराधी की शारीरिक अक्षमता या महिला अपराधी के गर्भवती होने के कारण मूल रूप से दी गई सज़ा के स्थान पर कम सज़ा देने को दर्शाता है।

प्रविलंबन (Reprieve): इसका तात्पर्य किसी दण्ड (विशेषकर मृत्युदण्ड) के निष्पादन पर अस्थायी अवधि के लिए रोक लगाना है। इसका उद्देश्य अपराधी को राष्ट्रपति से क्षमा या दण्ड में परिवर्तन हेतु समय प्रदान करना है।

44. (c)

कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार, लोक सभा, यदि पहले भंग न कर दी जाए, तो अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहती है। यह 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर, संविधान के अनुसार लोक सभा स्वतः भंग हो जाती है।

कथन 2 सही है: भारत का राष्ट्रपति लोक सभा को उसके पाँच वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने से पहले भी भंग कर सकता है। यह शक्ति राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद् की सलाह पर, या कुछ परिस्थितियों में, यदि सरकार बहुमत खो चुकी हो और कोई वैकल्पिक सरकार न बन सके, तो सदन को भंग करने की शक्ति प्रदान करती है।

45. (a)

कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(3) में स्पष्ट कहा गया है कि "यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।"

कथन 2 सही नहीं है: लाभ का पद धारण करने के लिए लोक सभा के किसी सदस्य को निरर्ह ठहराने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, अध्यक्ष के पास नहीं। हालाँकि, राष्ट्रपति भारत के चुनाव आयोग की सलाह पर निर्णय करता है। किसी सदस्य को निरर्ह ठहराने की अध्यक्ष की शक्ति दल-बदल विरोधी कानून (संविधान की 10वीं अनुसूची) के तहत अयोग्यताओं तक सीमित है।

46. (d)

कथन 1 सही है: आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (ICI) आर्थिक सलाहकार के कार्यालय (OEA) द्वारा प्रकाशित एक मासिक उत्पादन सूचकांक है। यह कार्यालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग' (DPIIT) के अंतर्गत आता है।

कथन 2 सही है: आठ प्रमुख क्षेत्रों में, पेट्रोलियम रिफ़ाइनरी उत्पादों का भारांश सर्वाधिक (28.04%) है, जबकि उर्वरकों का भारांश न्यूनतम (2.63%) है।

कथन 3 सही है: ICI आठ प्रमुख उद्योगों अर्थात् सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफ़ाइनरी उत्पाद और इस्पात के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। आठ प्रमुख उद्योग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल वस्तुओं के भारांश का 40.27% हिस्सा हैं।

47. (b)

विकल्प B सही है: भारत में पहला चिड़ियाघर-आधारित जैव बैंक पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र (CCMB) के साथ साझेदारी में जुलाई 2024 में चालू होगा।

यह संस्था - एक संस्थागत जैव बैंकिंग कोशिकीय प्रयोगशाला - संकटापन्न या मृत जानवरों के DNA, ऊतक, प्रजनन कोशिकाओं और युग्मकों को संरक्षित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक आनुवंशिक सुरक्षा के माध्यम से सहायक प्रजनन तकनीकों (ART) का उपयोग करके संरक्षण प्रजनन को मज़बूत करना है।

यह CCMBLaCONES के साथ सहयोग करता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण आनुवंशिकी सहायता और प्रशिक्षण संभव हो पाता है।

48. (c)

विकल्प (c) सही उत्तर है: यह एक AI-संचालित उप-समुद्री (Subsea) केबल प्रणाली है, जो 5 महाद्वीपों (एशिया, अफ़्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया) में 50,000 किमी तक विस्तृत है। यह अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ़्रीका और अन्य प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने वाला सबसे लंबी और उच्चतम क्षमता वाली उप-समुद्री केबल प्रणाली है। केबल गहरे पानी में 7,000 मीटर तक की गहराई पर बिछाए जाएँगे और उच्च जोख़िम वाले उथले जल में उन्नत दफ़न तकनीक (Advanced burial techniques) केबलों को जहाज़ों के बेड़े (Anchor) और पर्यावरणीय ख़तरों से बचाएगी। बेहतर कनेक्टिविटी से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, डिजिटल समावेशन और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।

49. (c)

संदर्भ: केंद्रीय बजट 2025-26 का एक प्रमुख आकर्षण 'परमाणु ऊर्जा मिशन' का शुभारंभ है, जो भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (BSMR) के अनुसंधान और विकास (R&D) पर केंद्रित है। सरकार ने इस पहल के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसका लक्ष्य वर्ष 2033 तक न्यूनतम 5 स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए और परिचालन-योग्य SMR विकसित करना है।

कथन 1 सही नहीं है: SMR ऐसे उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं, जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 30 मेगावाट से कम से लेकर 300+ मेगावाट तक होती है, जो पारंपरिक बड़े परमाणु रिएक्टरों के लिए एक लचीला, मापनीय और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं।

कथन 2 सही नहीं है: BSMR भारत के मौजूदा दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR) के संशोधित संस्करण हैं और प्रत्येक की क्षमता 200 मेगावाट (मेगावाट) होगी। इन्हें "अल्प संवर्धित यूरेनियम" से ईंधन दिया जाएगा और इन्हें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) द्वारा संयुक्त रूप से डिज़ाइन और विकसित किया जा रहा है।

कथन 3 सही है: भारत की बढ़ती ऊर्जा माँगों और विश्वसनीय, निम्न-कार्बन युक्त विद्युत आवश्यकता को देखते हुए, SMR अक्षय ऊर्जा स्रोतों के पूरक और ग्रिड स्थिरीकरण में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं। उनका मॉड्यूलर डिज़ाइन कारखाना-आधारित विनिर्माण की अनुमति देता है। यह निर्माण समय-सीमा और लागत को कम करता है, जिससे वे दूरस्थ स्थानों में तैनाती सहित ऑन-ग्रिड और ऑफ़-ग्रिड, दोनों अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हो जाते हैं।

50. (b)

संदर्भ: हाल ही में, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन ने आकाशगंगा NGC 6505 में एक आइंस्टीन वलय देखा, जो पृथ्वी से केवल 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है।

विकल्प (b) सही उत्तर है: आइंस्टीन वलय डार्क मैटर, आकाशगंगा या आकाशगंगाओं के समूह के चारों ओर मौजूद प्रकाश का एक वलय है। यह अनिवार्यतः गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का एक उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग एक ऐसी घटना है, जो तब होती है, जब कोई विशाल खगोलीय पिंड, जैसे- कोई आकाशगंगा या आकाशगंगाओं का समूह, एक गुरुत्वीय क्षेत्र बनाता है। यह क्षेत्र दूरस्थ आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश को विकृत और प्रवर्धित (Amplify) करता है, जो उसके पीछे तो होते हैं, लेकिन दृष्टि रेखा में समान होते हैं।

51. (a)

कथन-I सही है: अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की शक्तियों से व्यापक हैं।

कथन-II सही है और कथन-I की सही व्याख्या करता है: संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति को मृत्युदण्ड को क्षमा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 161 के तहत, राज्यपाल मृत्युदण्ड का केवल निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है; वह इसे पूर्णतः क्षमा (Pardon) नहीं कर सकता है। मृत्युदण्ड को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। यह राष्ट्रपति की व्यापक शक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

कथन-III सही है और कथन-I की सही व्याख्या करता है: कोर्ट-मार्शल (सैन्य न्यायालय) द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की सज़ा को क्षमा करने, स्थगित करने या कम करने की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत पूर्णतः राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल के पास सैन्य न्यायालयों पर कोई अधिकार नहीं है। यह एक और अंतर है, जो राष्ट्रपति की शक्ति को व्यापक बनाता है।

52. (a)

कथन 1 सही है: यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित प्रस्ताव द्वारा घोषित किया है कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं (एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित) के निर्माण का प्रावधान कर सकती है। यह एक साधारण विधि द्वारा किया जा सकता है और इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

कथन 2 सही नहीं है: यद्यपि एक संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन (लोक सभा या राज्य सभा) में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।

53. (c)

1, 2 और 3 सही हैं: कैबिनेट सचिवालय के कार्यों में शामिल हैं:

भारत सरकार प्रशासन (कार्य संचालन) नियम, 1961 और भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961, जो मंत्रालयों/विभागों में कार्य के सुचारू संचालन को सुगम बनाते हैं।

यह अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करके, मंत्रालयों/विभागों के बीच मतभेदों को दूर करके और सचिवों की स्थायी/तदर्थ समितियों के माध्यम से आम सहमति बनाकर सरकार में निर्णय लेने में सहायता करता है।

मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवालयी सहायता: इसमें शामिल हैं- प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल और उसकी समितियों की बैठकें बुलाना, कार्यसूची तैयार करना और उसका प्रसार करना, कार्यसूची में शामिल मामलों से

संबंधित दस्तावेज़ों का प्रसार करना, प्रधानमंत्री की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद चर्चाओं के रिकॉर्ड का प्रसार करना, मंत्रिमंडल और उसकी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

देश में प्रमुख संकट स्थितियों का प्रबंधन और ऐसी स्थिति में विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों का समन्वय करना।

4 सही नहीं है: 'मंत्रिमंडल सचिवालय' मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन आवंटित नहीं करता है। यह कार्य सामान्यतः वित्त मंत्रालय का है।

54. (c)

कथन 1 सही है: भारत का उप-राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। उप-राष्ट्रपति उच्च सदन की अध्यक्षता करता है, लेकिन वह राज्य सभा का सदस्य नहीं होता है।

कथन 2 सही है: लोक सभा का अध्यक्ष सदन के वर्तमान सदस्यों में से साधारण बहुमत द्वारा चुना जाता है। इस प्रकार, अध्यक्ष एक निर्वाचित प्रतिनिधि और लोक सभा का सदस्य होता है।

55. (b)

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 61(1) के अनुसार, राष्ट्रपति को केवल "संविधान के उल्लंघन" के लिए ही पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के लिए किसी अन्य आधार की अनुमति नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों की कम-से-कम एक-चौथाई संख्या द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद ही पेश किया जा सकता है।

कथन 2 सही नहीं है: जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाना हो, तो आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि ऐसा आरोप लगाने का प्रस्ताव किसी संकल्प (Resolution) में पेश न किया गया हो। यह संकल्प, सदन की कुल सदस्य संख्या के न्यूनतम एक-चौथाई सदस्यों द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित होना चाहिए और कम-से-कम चौदह दिन की पूर्व-सूचना के बाद प्रस्तावित किया जाना चाहिए, जिसमें संकल्प प्रस्तावित करने का आशय उल्लिखित हो।

कथन 3 सही है: राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाने वाला ऐसा संकल्प दूसरे सदन में जाँच के लिए भेजे जाने से पहले उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

56. (d)

विकल्प (d) सही उत्तर है: रिक्ति या अनुपलब्धता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन का वरीयता क्रम इस प्रकार है:

भारत का उप-राष्ट्रपति: संविधान के अनुच्छेद 65(1) के अनुसार, "राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग-पत्र या पद से हटाए जाने या अन्यथा किसी कारण से पद रिक्ति होने की स्थिति में, उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, या उसकी अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से उनके कार्यों का निर्वहन करेगा।"

भारत का मुख्य न्यायाधीश: यदि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति दोनों का पद मृत्यु, त्याग-पत्र, पदच्युति या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। संविधान में इस प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति (कार्य निर्वहन) अधिनियम, 1969 द्वारा इसे स्थापित किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश: यदि राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और भारत का मुख्य न्यायाधीश, तीनों का पद रिक्त हो जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति (कार्य निर्वहन) अधिनियम, 1969 द्वारा भी इसकी स्थापना की गई है।

57. (d)

क्षेत्रीय परिषदों के बारे में: पंडित नेहरू के दृष्टिकोण के आलोक में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-III के तहत पाँच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। इन क्षेत्रीय परिषदों में से प्रत्येक की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद्: इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं;

मध्य क्षेत्रीय परिषद्: इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं;

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्: इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं;

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्: इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य तथा दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं;

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्: इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य और पुदुच्चेरी संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं।

कथन-I सही नहीं है: क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। राज्य और संघ राज्यक्षेत्र, दोनों ही इनके सदस्य होते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं। इसी प्रकार, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद् में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य तथा दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं।

कथन II सही है: क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत गठित सांविधिक निकाय हैं।

58. (c)

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 110 के अनुसार, कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा, यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय से संबंधित प्रावधान हों, अर्थात्:--

(a) किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन;

(b) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनियमन, या भारत सरकार द्वारा लिए गए या लिए जाने वाले किसी वित्तीय दायित्व के संबंध में कानून में संशोधन;

(c) भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन का भुगतान या उससे धन का आहरण;

(d) भारत की संचित निधि से धन का विनियोग;

(e) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना;

(f) भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा से धन की प्राप्ति अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निर्गमन अथवा संघ या किसी राज्य के लेखाओं की लेखा परीक्षा; अथवा

(g) उप-खंड (a) से (f) में निर्दिष्ट किसी विषय से आनुषंगिक कोई विषय।

कथन 2 सही है: संविधान में कहा गया है कि 'विधि द्वारा किए गए विनियोग के अलावा, भारत की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा'। तद्नुसार, भारत की संचित निधि में से निम्नलिखित के लिए आवश्यक समस्त धनराशि के विनियोग का प्रावधान करने हेतु एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है:

(a) लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान।

(b) भारत की संचित निधि पर भारित व्यय।

इस प्रकार, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, यद्यपि लोक सभा में मतदान के अधीन नहीं होते, लेकिन अभिलेख प्रयोजनों के लिए विनियोग विधेयक में शामिल किए जाते हैं।

59. (d)

विकल्प (d) सही उत्तर है: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 ने भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची शामिल की, जिसमें दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधान हैं। यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में राजनीतिक दल-बदल को रोकने के लिए बनाया गया था। यह "आया राम गया राम" राजनीति

की प्रचलित परिघटना को रोकने के लिए लाया गया था, जहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि प्रायः व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदल लेते थे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती थी।

60. (a)

कथन 1 सही है: यदि एक सदन का वर्तमान सदस्य, दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित होता है, तो प्रथम सदन में उसका स्थान रिक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि राज्य सभा का कोई सदस्य लोक सभा के लिए निर्वाचित होता है, तो राज्य सभा में उसका स्थान रिक्त हो जाता है।

कथन 2 सही नहीं है: यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचित होता है, तो संसद में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, यदि वह 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल में अपनी सीट से त्याग-पत्र नहीं देता है। अतः, इस स्थिति में, राज्य सभा में स्थान रिक्त हो जाएगा, न कि राज्य विधान सभा में।

61. (b)

कथन 1 सही नहीं है: अनुच्छेद 170 के अंतर्गत, संविधान राज्य विधान सभा की न्यूनतम और अधिकतम दोनों सदस्य-संख्या निर्दिष्ट करता है। इसमें कहा गया है कि किसी विधान सभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य होंगे, हालाँकि सिक्किम (32 सदस्य), गोवा (40) आदि जैसे छोटे राज्यों के लिए कुछ अपवाद मौजूद हैं।

कथन 2 सही है: अनुच्छेद 171 के अनुसार, विधान परिषद् की सदस्य संख्या विधान सभा की सदस्य संख्या से संबद्ध होती है। विधान परिषद् में सदस्यों की कुल संख्या विधान सभा के कुल सदस्यों के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी।

कथन 3 सही है: उत्तर प्रदेश विधान सभा में 403 सदस्य हैं, जो सभी भारतीय राज्यों में सर्वाधिक है।

62. (b)

कथन 1 सही है: मंत्रिमंडल समितियों (Cabinet Committees) का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इनका गठन *भारत सरकार* (*कार्य आवंटन*) *नियम*, 1961 के अंतर्गत निर्णय-निर्माण में मंत्रिमंडल की सहायता हेतु किया जाता है।

कथन 2 सही है: गैर-केबिनेट मंत्री या अन्य अधिकारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य (Special invitees) के रूप में मंत्रिमंडल समितियों में भाग लेने के लिए बुलाया जा सकता है, यद्यपि वे औपचारिक सदस्य नहीं होते हैं।

कथन 3 सही नहीं है: आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs – CCEA) की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, न कि वित्त मंत्री।

अतिरिक्त जानकारी:

- मंत्रिमंडल समितियाँ त्वरित निर्णय निर्माण में सहायक होती हैं और संपूर्ण मंत्रिमंडल पर कार्यभार को कम करती हैं।
- इनके उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे - सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (Cabinet Committee on Security), राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (Cabinet Committee on Political Affairs), और आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs)
- समितियों की सदस्यता और संरचना का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।
- गैर-कैबिनेट मंत्रियों या विशेषज्ञों को कभी-कभी विशेष सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जाता है, किंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है।

63. (d)

कथन 1 सही नहीं है: *डोकरा शिल्प* लगभग 4000 वर्ष पुरानी पारंपरिक धातु ढलाई तकनीक है। इस कला में अत्यंत सटीक और बारीक कारीगरी की आवश्यकता होती है। इसकी वस्तुएँ सामान्यतः पीतल (Brass), निकेल (Nickel) और जस्ता (Zinc) मिश्रधातु से बनाई जाती हैं।

कथन 2 सही नहीं है: *डोकरा शिल्प* मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना राज्यों में प्रचलित है।

64. (c)

इलात की खाड़ी को *अक़ाबा की खाड़ी* भी कहा जाता है। यह लाल सागर के उत्तरी भाग का एक संकीर्ण विस्तार है। यह सिनाई प्रायद्वीप (मिस्र) और पश्चिमी सऊदी अरब के बीच स्थित है। इसके उत्तरी सिरे पर इज़राइल और जॉर्डन स्थित हैं।

इलात की खाड़ी अपने विशिष्ट और सहनशील प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र (Coral reef ecosystems) के लिए जानी जाती है। यहाँ के प्रवाल गर्म पानी में भी जीवित रहते हैं, जबकि अन्य स्थानों पर प्रवाल ब्लीचिंग हो रही है। यह विश्व की उत्तरीतम प्रवाल भित्तियों (29.5° उत्तर अक्षांश) में से एक है, क्योंकि यहाँ का जल समान अक्षांश वाले अन्य जल निकायों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक गर्म (22°C से 28°C) रहता है।

65. (a)

संदर्भ: हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने तस्मानिया के तट पर फँसी लगभग 100 झूठी किलर व्हेल (False killer whales) को मार दिया, क्योंकि उन्हें बचाना असंभव था।

कथन 1 सही है: झूठी किलर व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी डॉल्फ़िन प्रजातियों में से एक है। इसकी लंबाई 6 मीटर (19 फ़ीट) तक और वज़न 1.5 टन तक हो सकता है।

कथन 2 गलत है: ये अपने मज़बूत सामाजिक संबंधों के लिए जानी जाती हैं। इसी कारण सामान्यतः पूरा समूह (Pod) एक साथ फँस जाता है।

अतिरिक्त जानकारी:

- झूठी किलर व्हेल सामान्य तौर पर 30° दक्षिण से 30° उत्तर अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण समुद्रों में पाई जाती हैं। ये सामान्यतः गहरे खुले समुद्र में रहती हैं, लेकिन कभी-कभी तटीय क्षेत्रों के समीप भी आ जाती हैं।

66. (c)

कटौती प्रस्ताव के बारे में: अनुदान की किसी भी माँग को घटाने के लिए विधानमंडलों में सदस्यों द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है,उसे 'कटौती प्रस्ताव' कहा जाता है। कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं।

विकल्प (c) सही उत्तर है: सांकेतिक (टोकन) कटौती प्रस्ताव का उपयोग केवल किसी विशेष शिकायत या मुद्दे को प्रतीकात्मक रूप से उठाने के लिए लाया जाता है। यह प्रस्ताव माँग की राशि को केवल ₹100 घटाने की माँग करता है। इसलिए इसका स्वरूप प्रतीकात्मक हो जाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय कटौती नहीं, बल्कि संसद का उसके अधिकार क्षेत्र में किसी गंभीर विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना है।

अतिरिक्त जानकारी:

कटौती प्रस्ताव के अन्य प्रकार:

मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव: यह प्रस्तावित व्यय में की जा सकने वाली बचत को दर्शाता है। इसमें प्रस्ताव होता है कि माँग की राशि को एक निश्चित राशि से घटाया जाए (जो या तो माँग में एकमुश्त कटौती हो सकती है या माँग की किसी मद को हटाने या घटाने के रूप में हो सकती है)।

नीतिगत कटौती प्रस्ताव: यह किसी विशेष माँग के पीछे निहित नीति के प्रति असहमति व्यक्त करने के लिए लाया जाता है। इसमें प्रस्ताव किया जाता है कि माँग की राशि घटाकर ₹1 कर दी जाए। इससे सदस्यों को वैकल्पिक नीतियाँ सुझाने का अवसर मिलता है।

67. (b)

कथन 1, 2 और 4 सही हैं: निम्नलिखित मामलों में राज्य सभा की शक्तियाँ और स्थिति लोक सभा के समान है:

- साधारण विधेयकों का प्रस्तुतीकरण और पारित होना।
- संविधान संशोधन विधेयकों का प्रस्तुतीकरण और पारित होना। (अतः कथन 4 सही है)
- ऐसे वित्तीय विधेयकों का प्रस्तुतीकरण और पारित होना, जिनमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल हो।
- राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग। (अतः कथन 1 सही है)
- उप-राष्ट्रपति का चुनाव और पद से हटाना। हालाँकि, उप-राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्य सभा ही प्रारंभ कर सकती है। उप-राष्ट्रपति को राज्य सभा द्वारा प्रभावी बहुमत (जो विशेष बहुमत का एक प्रकार है) से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है और लोक सभा साधारण बहुमत से इसे अनुमोदित करती है।
- राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को हटाने की संस्तुति देना।
- राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों की स्वीकृति। (अतः कथन 2 सही है)
- राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार की आपात स्थितियों की स्वीकृति।
- मंत्रियों सहित प्रधानमंत्री का चयन। संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्य दोनों सदनों में से किसी एक के सदस्य हो सकते हैं। किंतु उनकी सदस्यता चाहे जिस सदन से हो, वे केवल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक आदि जैसे संवैधानिक निकायों की रिपोर्टों पर विचार।

कथन 5 सही नहीं है: यह **अनुच्छेद 249** के तहत राज्य सभा की विशेष शक्ति है। यदि राज्य सभा (उच्च सदन) उपस्थित और मतदान करने वाले कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से यह प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद को संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए ऐसे कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है, जब तक वह प्रस्ताव प्रभावी रहता है।

अतिरिक्त जानकारी:

(1) लोक सभा की तुलना में राज्य सभा की असमान स्थिति

1. **धन विधेयक और वित्तीय विधेयक**

- धन विधेयक केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है (अनु. 110)।
- राज्य सभा धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकृति नहीं कर सकती; उसे इसे 14 दिनों के भीतर, चाहे संस्तुति के साथ या बिना, वापस करना होता है।
- लोक सभा इन संस्तुतियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है; दोनों ही स्थितियों में विधेयक पारित माना जाएगा।
- यह तय करने का अंतिम अधिकार कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लोक सभा के अध्यक्ष के पास है।

2. **बजट संबंधी शक्तियाँ**

- राज्य सभा बजट पर चर्चा कर सकती है परंतु अनुदानों की माँगों पर मतदान नहीं कर सकती (यह केवल लोक सभा की शक्ति है)।

3. **संयुक्त बैठक**

- संयुक्त बैठक में लोक सभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है।
- अपनी अधिक संख्या के कारण लोक सभा सामान्यतः प्रभावी रहती है, जब तक कि सत्ताधारी दल दोनों सदनों में अल्पमत में न हो।

4. **सरकार पर नियंत्रण**

- केवल लोक सभा मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है (क्योंकि मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से केवल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है)।
- राज्य सभा केवल चर्चा और आलोचना कर सकती है।

5. **राष्ट्रीय आपातकाल**

- राष्ट्रीय आपातकाल को निरस्त करने का प्रस्ताव केवल लोक सभा ही पारित कर सकती है, राज्य सभा नहीं। (अतः कथन 3 सही नहीं है)

(2) राज्य सभा की विशेष शक्तियाँ

- **राज्य सूची पर विधायी शक्ति:** संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देती है (अनु. 249)। (अतः कथन 5 सही नहीं है)
- **अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना:** संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएँ स्थापित करने का अधिकार प्रदान कर सकती है (अनु. 312)।
- **उप-राष्ट्रपति को हटाना:** केवल राज्य सभा ही उप-राष्ट्रपति को हटाने हेतु प्रस्ताव प्रारंभ कर सकती है (अनु. 67)।
- **आपातकालीन स्थितियाँ:** जब लोक सभा भंग हो, तो केवल राज्य सभा की स्वीकृति ही पर्याप्त होती है कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रभावी बनी रहे (अनु. 352, 356, 360)।

68. (d)

बिम्सटेक (BIMSTEC – Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) के बारे में:

यह बंगाल की खाड़ी से लगे और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित सात सदस्य देशों का समूह है। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ने वाली एक विशिष्ट कड़ी है – दक्षिण एशिया के पाँच सदस्य (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका) तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के दो सदस्य (म्यांमार और थाईलैंड)। अतः, कथन 1 सही है।

भारतीय महासागर क्षेत्र संघ (IORA – Indian Ocean Rim Association) के बारे में:

यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य भारतीय महासागर से सटे देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और सतत् विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी और वर्तमान में इसके 23 सदस्य देश हैं। इसके सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ़्रांस, भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) आदि शामिल हैं। अतः, कथन 2 सही है।

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC – Colombo Security Conclave) के बारे में:

यह भारतीय महासागर क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। इसकी स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय ख़तरों और चुनौतियों का सामना किया जा सके। इसके वर्तमान सदस्य भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस और बांग्लादेश हैं। अतः, कथन 3 सही है।

69. (b)

सही उत्तर (b) है, अर्थात् 1–A, 2–B, 3–C

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) को निरस्त कर *भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023* से प्रतिस्थापित किया गया है। यह हत्या, चोरी, मॉब लिंचिंग, आतंकवाद आदि अपराधों पर केंद्रित है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) को *भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023* से प्रतिस्थापित किया गया है। यह जाँच, मुकदमा, अपील आदि की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। इसमें समयबद्ध मुकदमे, ई-एफआईआर, फॉरेंसिक साक्ष्य और आपराधिक प्रक्रिया का डिजिटलीकरण जैसी व्यवस्थाएँ जोड़ी गई हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को *भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023* से प्रतिस्थापित किया गया है। यह साक्ष्य की ग्राह्यता (Admissibility) को नियंत्रित करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों के दायरे का विस्तार किया गया है तथा दस्तावेज़ी साक्ष्य के नियमों को सुदृढ़ किया गया है।

70. (d)

कथन 1 सही है: भारत *आर्द्रभूमि अभिसमय (Convention on Wetlands)*, जिसे *रामसर कन्वेंशन* भी कहा जाता है, का 1 फ़रवरी, 1982 को पक्षकार बना।

कथन 2 सही है: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने *पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986* के प्रावधानों के अंतर्गत *आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017* अधिसूचित किए हैं, जो भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नियामक ढाँचा प्रदान करते हैं।

कथन 3 सही है: *विश्व आर्द्रभूमि दिवस* प्रतिवर्ष 2 फ़रवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों, प्रकृति और संस्कृति के लिए आर्द्रभूमियों की महत्ता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2025 का विषय है – *"हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा"*, जो हमें जैव-विविधता और मानव कल्याण के लिए आर्द्रभूमियों के लाभों की याद दिलाता है।

71. (a)

प्रसंग: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (उत्पादन लागत का निर्धारण) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया है और प्रतिस्पर्धा कानून के अंतर्गत स्वार्थचालित कीमत (Predatory Pricing) के निर्धारण के अपने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने हेतु हितधारकों से सुझाव माँगे हैं।

विकल्प (a) सही उत्तर है:

कानून "स्वार्थचालित कीमत" को इस प्रकार परिभाषित करता है — वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री "उत्पादन लागत से कम" मूल्य पर करना, ताकि प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सके या समाप्त किया जा सके।

नए मसौदा विनियम "लागत मानकों का आधुनिकीकरण" करने का प्रयास करते हैं, ताकि वे समकालीन आर्थिक सिद्धांतों, न्यायिक व्याख्याओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्रथाओं के अनुरूप हों।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, धारा 4(2)(a)(ii) के अंतर्गत स्वार्थचालित कीमत को प्रमुख उद्यमों (Dominant enterprises) द्वारा अपनाई जाने वाली एक दुरुपयोगी प्रथा (Abusive practice) के रूप में प्रतिबंधित करता है।

72. (c)

युग्म 1 सुमेलित नहीं है: ट्रोपेक्स (Tropex – Theatre Level Operational Readiness Exercise) एक घरेलू अभ्यास है, लेकिन इसमें केवल नौसेना ही नहीं, बल्कि कई बल शामिल होते हैं। यह भारतीय नौसेना द्वारा समन्वित एक त्रि-सेवा (Tri-service) अभ्यास है, जिसमें थल सेना, वायु सेना और तटरक्षक बल की इकाइयाँ भी भाग लेती हैं।

युग्म 2 सुमेलित है: धर्म गार्जियन (DHARMA GUARDIAN) एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, जो बारी-बारी से भारत और जापान में आयोजित होता है। इसमें दोनों देशों की थल सेनाएँ भाग लेती हैं और यह अर्ध-शहरी तथा जंगल क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों पर केंद्रित होता है।

युग्म 3 सुमेलित नहीं है: कोमोडो अभ्यास (Exercise Komodo) एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसकी मेज़बानी इंडोनेशिया करता है। इसमें विश्वभर की नौसेनाएँ भाग लेती हैं, जिनमें भारत भी शामिल है।

73. (a)

कथन 1 सही है: ब्रिक्स (BRICS) के प्रारंभिक सदस्य पाँच देश थे — ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ़्रीका। हालाँकि, बैंक के समझौता अनुच्छेद (Articles of Agreement) नए सदस्यों के प्रवेश की अनुमति देते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की सदस्यता केवल ब्रिक्स देशों तक सीमित नहीं है; यह अन्य देशों के लिए भी खुली है, जिससे भविष्य में विस्तार संभव है। अपनी स्थापना के बाद से, NDB ने अपनी सदस्यता का विस्तार कर बांग्लादेश, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और अल्जीरिया जैसे देशों को भी शामिल किया है।

कथन 2 सही नहीं है: NDB का स्थायी मुख्यालय चीन के शंघाई में स्थित है। यह इसके संचालन, निर्णय-निर्माण और प्रशासन का मुख्य केंद्र है।

अतिरिक्त जानकारी:

न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 2014 में ब्रिक्स देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ़्रीका) द्वारा की गई थी, ताकि अवसंरचना और सतत् विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों को जुटाया जा सके। यह बैंक मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के पूरक के रूप में कार्य करने और वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने का लक्ष्य भी रखता है।

74. (c)

विकल्प C सही है: *मनोनीत सदस्य (Nominated Member)* अपने पदभार ग्रहण करने के छह माह के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। यदि वह छह माह के बाद शामिल होता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यहाँ सदस्य चार माह बाद (छह माह की अवधि के भीतर) पार्टी में शामिल हुआ है।

अतिरिक्त जानकारी: दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) के अंतर्गत अयोग्यता

- **पार्टी सदस्यों के लिए:** यदि सदस्य उस राजनीतिक पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है, जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ था। यदि सदस्य सदन में अपनी पार्टी द्वारा जारी निर्देश (व्हिप) के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है।
- **निर्दलीय सदस्यों के लिए:** यदि कोई निर्दलीय सदस्य (जो बिना किसी दल के समर्थन के निर्वाचित हुआ हो) चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- **मनोनीत सदस्यों के लिए:** यदि कोई मनोनीत सदस्य नामांकन की तिथि से छह माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।

निर्णय का अधिकार:

राज्य सभा के सदस्यों के मामले में इसके सभापति और लोक सभा के सदस्यों के मामले में इसके अध्यक्ष को अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार है। यह शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है।

न्यायिक पुनरावलोकन:

किहोटो होलोहान बनाम ज़ाचिल्लू (1992) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अयोग्यता पर सभापति/अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial review) के अधीन होगा।

75. (c)

कथन 1 सही है: संविधान के अनुसार, निवर्तमान लोक सभा का अध्यक्ष (Speaker) नव-निर्वाचित सदन की पहली बैठक से ठीक पहले पद छोड़ देता है। प्रोटेम स्पीकर (Speaker Pro Tem) के पास अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ होती हैं। वह नव-निर्वाचित लोक सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है।

कथन 2 सही नहीं है: राष्ट्रपति लोक सभा के किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर सकता है, और सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है।

कथन 3 सही है: प्रोटेम स्पीकर की मुख्य ज़िम्मेदारी नव-निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष के चुनाव की कार्यवाही कराना होती है। जैसे ही सदन अपना नया अध्यक्ष चुन लेता है, प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है।

76. (d)

प्रधानमंत्री के बारे में: संसदीय शासन प्रणाली में, जो संविधान द्वारा प्रदत्त है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका (De facto executive) तथा सरकार का मुखिया होता है।

कथन 1 सही नहीं है: संविधान का अनुच्छेद 75 उल्लेख करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। वर्ष 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले लोक सभा में बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य हो। राष्ट्रपति पहले किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और फिर उसे एक उचित समयावधि में लोक सभा में बहुमत सिद्ध करने को कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, चरण सिंह (1979), वी.पी. सिंह (1989), पी.वी. नरसिम्हा राव (1991), अटल बिहारी वाजपेयी (1996), एच.डी. देवगौड़ा (1996), आई.के. गुजराल (1997) आदि इस प्रकार से प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे।

कथन 2 सही नहीं है: वर्ष 1997 में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन केवल छह महीने के लिए। इस अवधि के भीतर उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा वह प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार खो देगा।

77. (d)

पंक्ति I सुमेलित नहीं है: एक तारांकित प्रश्न (Starred Question) का उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। मौखिक उत्तर के बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

पंक्ति II सुमेलित नहीं है: एक अतारांकित प्रश्न (Unstarred Question) का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है और इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती।

पंक्ति III सुमेलित नहीं है: एक अल्पसूचना प्रश्न (Short Notice Question) सामान्यतः 15 दिन की सूचना अवधि के बिना तात्कालिकता (लोक महत्त्व के तात्कालिक विषय) के कारण पूछा जाता है। इसका उत्तर मंत्री मौखिक रूप से देते हैं और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है।

78. (a)

संविधान का अनुच्छेद 191(1) राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता के निम्नलिखित आधारों का उल्लेख करता है:

- यदि कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद (Office of profit) धारण करता है (सिवाय उन पदों के, जिन्हें राज्य विधानमंडल ने विधि द्वारा अयोग्यता से मुक्त घोषित किया हो)। अतः, कथन 1 सही है।
- यदि कोई व्यक्ति विकृत मस्तिष्क का हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो। अतः, कथन 2 सही है।
- यदि कोई व्यक्ति अवमुक्त दिवालिया (Undischarged insolvent) हो।
- यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक न हो या स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, इत्यादि।

अनुच्छेद 191(2) एक और अयोग्यता का आधार बताता है, अर्थात् — दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) के अंतर्गत अयोग्यता।

कथन 3 सही नहीं है: दोषसिद्धि (Conviction) और 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सज़ा मिलने पर अयोग्यता का प्रावधान संविधान में नहीं, बल्कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) में है।

79. (b)

कथन 1 सही नहीं है: विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) कर प्रस्तावित नहीं करता; यह केवल भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से सरकार के व्यय हेतु धन निकालने की अनुमति देता है। कर संबंधी प्रस्ताव वित्त विधेयक (Finance Bill) में शामिल होते हैं।

कथन 2 सही है: विनियोग विधेयक संसद में तभी प्रस्तुत किया जाता है, जब अनुदान की माँगों (Demands for Grants) पर मतदान हो चुका होता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी व्यय हेतु धन स्वीकृत है।
अनुदान की माँगों पर मतदान वह चरण है, जहाँ लोक सभा प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के प्रस्तावित व्यय पर चर्चा करती है और उसे स्वीकृत करती है। इस प्रक्रिया में स्वीकृत कुल राशि को फिर विनियोग विधेयक में शामिल किया जाता है, जो पारित होने पर सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने की कानूनी अनुमति देता है।

अतिरिक्त जानकारी:
विनियोग विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत एक धन विधेयक (Money Bill) है। यह सरकार को वित्तीय वर्ष के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की विधिक शक्ति प्रदान करता है, जो संसद की व्यय स्वीकृति को दर्शाता है।

80. (c)

1 सही नहीं है: भारत ने यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार अथवा दण्ड के विरुद्ध अभिसमय (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) पर 14 अक्टूबर, 1997 को हस्ताक्षर किए थे। हालाँकि, भारत ने इस अभिसमय का अनुमोदन (Ratification) नहीं किया है।

2 सही है: भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) का 01.10.2007 को अनुमोदन किया।

3 सही है: भारत ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार (The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) का 10 अप्रैल, 1979 को अनुमोदन किया।

4 सही है: भारत ने महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) का 09 जुलाई, 1993 को अनुमोदन किया।

5 सही है: भारत ने बाल अधिकार अभिसमय (The Convention on the Rights of the Child) का 11 दिसंबर, 1992 को अनुमोदन किया।

81. (b)

विकल्प B सही है: "लेम डक" सत्र शब्द का प्रयोग लोक सभा के अंतिम सत्र के लिए होता है, जो नई लोक सभा के चुनाव के बाद आयोजित किया जाता है।

वे सदस्य, जो नई लोक सभा में पुनः निर्वाचित नहीं हो पाते, उन्हें लेम डक (Lame-ducks) कहा जाता है।

82. (d)

कथन 1 सही नहीं है: संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के अनुसार: राज्यपाल कुछ विधेयकों (जिसमें धन विधेयक भी शामिल हैं) को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं। परंतु, एक बार जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास केवल दो विकल्प होते हैं: या तो वह अपनी स्वीकृति दें अथवा अस्वीकृति दें। राष्ट्रपति के पास धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है।

कथन 2 सही नहीं है: अनुच्छेद 201 के अंतर्गत, यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखते हैं, तो राष्ट्रपति या तो स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृति दे सकते हैं, अथवा (यदि वह धन विधेयक नहीं है) उसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। यहाँ तक कि यदि राज्य विधानमंडल उस विधेयक को पुनः पारित कर देता है, तब भी राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं हैं।

83. (d)

SEBCs के संबंध में: संविधान (102वाँ) संशोधन अधिनियम, 2018 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 342(a) जोड़ा है। अनुच्छेद 342(a) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों [SEBCs - जिन्हें सामान्यतः अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के नाम से जाना जाता है] की केंद्रीय सूची से संबंधित है।

कथन 1 सही नहीं है: राष्ट्रपति को किसी विशेष राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची निर्दिष्ट करने का अधिकार है। इस प्रकार, SEBCs की केंद्रीय सूची की घोषणा संसद नहीं, बल्कि राष्ट्रपति करता है।

कथन 2 सही नहीं है: SEBCs (OBCs) की केंद्रीय सूची में कोई भी संशोधन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है।

84. (c)

कथन 1 सही है: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) न्यूयॉर्क में नहीं, बल्कि नीदरलैंड्स के हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य सभी प्रमुख अंग [महासभा, सुरक्षा परिषद्, ECOSOC, सचिवालय, न्यास (ट्रस्टीशिप) परिषद्] न्यूयॉर्क में स्थित हैं।

कथन 2 सही है: ICJ एकतरफ़ा ढंग से न्यायनिर्णयन (Jurisdiction) लागू नहीं कर सकता। इसका न्यायनिर्णयन तब लागू होता है, जब:

दोनों पक्ष मामले को संदर्भित करने के लिए सहमत हैं, या

दोनों राज्यों ने ICJ के अनिवार्य न्यायनिर्णयन को मान्यता दी है, या

इसका प्रावधान एक संधि/समझौते में किया गया है।

85. (b)

2 और 4 सही हैं: लेबनान पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। इसकी भूमि-सीमाएँ निम्नलिखित देशों के साथ मिलती हैं:

दक्षिण में इज़राइल

उत्तर और पूर्व में सीरिया

इसकी सीमा तुर्की, इराक़ या ईरान से नहीं मिलती।

86. (a)

विकल्प (a) सही उत्तर है - त्रिशंकु संसद (Hung Parliament) तब होती है, जब किसी भी पार्टी या चुनाव-पूर्व गठबंधन के पास अकेले सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं होती हैं।

ऐसे मामलों में, पार्टियाँ चुनाव के बाद गठबंधन के लिए बातचीत कर सकती हैं या गठबंधन सरकार बनाने के लिए छोटी पार्टियों या स्वतंत्र सांसदों से समर्थन माँग सकती हैं।

87. (b)

संदर्भ: हाल ही में, अनकापल्ली जिले के रोलुगुंटा मंडल के अरला पंचायत में पहाड़ी पर स्थित एक गाँव नीलाबाँधा के आदिवासी परिवारों को आज़ादी के बाद पहली बार विद्युत सुविधा मिली और उन्होंने रोशनी के नीचे उत्साह में लोकप्रिय आदिवासी नृत्य 'धीमसा (Dhimsa)' का प्रदर्शन किया।

विकल्प (b) सही उत्तर है: 'धीमसा', जिसका अर्थ है, 'पैरों की ध्वनि', एक लोकप्रिय आदिवासी नृत्य है। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के क्षेत्रों में प्रचलित है। यह नृत्य स्थानीय संस्कृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से अराकू घाटी और बोर्रा गुफ़ाओं के क्षेत्रों में।" ऐतिहासिक रूप से, धीमसा का प्रदर्शन युवा, अविवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता था। नृत्य में प्रत्येक गतिविधि विभिन्न दैनिक कार्यों का अनुकरण करती है - पत्ते या पौधे इकट्ठा करना, कृषि करना, विवाह संबंधी रीति-रिवाज़ों में भाग लेना या वन्यजीवों से अपनी रक्षा करना।

88. (d)

कथन 1 सही नहीं है: संविधान (अनुच्छेद 165) में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

कथन 2 सही नहीं है: महाधिवक्ता अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकता है। उसे राज्य विधानमंडल और उसकी समितियों (यदि वह सदस्य है) की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। उसे राज्य विधायक के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ भी प्राप्त हैं।

कथन 3 सही नहीं है: संविधान में महाधिवक्ता के लिए कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, न ही इसमें पद से हटाने की प्रक्रिया या आधार निर्दिष्ट किया गया है। वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और राज्यपाल को अपना त्याग-पत्र देता है। परंपरा के अनुसार, महाधिवक्ता सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद् के त्याग-पत्र देने या उसके स्थान पर किसी अन्य के नियुक्त होने पर त्याग-पत्र दे देता है, क्योंकि उनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद् की सलाह पर की जाती है।

89. (a)

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 67 में उल्लेख है कि उप-राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक पद पर बना रहेगा। इसमें आगे कहा गया है कि अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी, उप-राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।

कथन 2 सही नहीं है: संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जाँच और निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। इनका निर्णय चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता।

कथन 3 सही नहीं है: अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि किसी भी सदन की बैठक या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का निर्धारण लोक सभा अध्यक्ष या सभापति अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या लोक सभा अध्यक्ष, या इस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमदृष्टया मतदान नहीं करेगा, किंतु मतों की बराबरी की स्थिति में उसे निर्णायक मत प्राप्त होगा और वह इसका प्रयोग करेगा। इस प्रकार, राज्य सभा के सभापति के रूप में कार्य करते हुए, बराबर मतों की स्थिति में उप-राष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।

90. (b)

कथन 1 सही है: संविधान के किसी ऐसे प्रावधान में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, जिसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की आवश्यकता हो।

कथन 2 सही नहीं है: राष्ट्रपति उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है, जब संसद का कोई एक या दोनों सदन सत्र में न हों। "सत्र में नहीं" शब्द में वह स्थिति भी शामिल है, जब सदन को स्थगित या भंग कर दिया गया है। इसलिए, यदि लोक सभा का सत्रावसान हो गया है, लेकिन राज्य सभा का सत्र अभी भी जारी है, तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है।

कथन 3 सही है: राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। हालाँकि, अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति विवेकाधीन शक्ति (Discretionary power) नहीं है। वह केवल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही अध्यादेश जारी कर सकता या वापस ले सकता है।

91. (d)

विकल्प (d) सही उत्तर है: संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार, अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए लोक सभा में आरक्षित सीटों का वर्तमान आवंटन वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित है, जब तक कि वर्ष 2026 के बाद की जाने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक आँकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते।

92. (b)

कथन 1 सही है: निंदा प्रस्ताव (Censure Motion) किसी व्यक्तिगत मंत्री या सरकार की किसी विशिष्ट नीति/कार्य के विरुद्ध लाया जा सकता है। इसके विपरीत, अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion) संपूर्ण मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध लाया जा सकता है।

कथन 2 सही नहीं है: निंदा प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में नहीं। इसी प्रकार, अविश्वास प्रस्ताव भी केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

कथन 3 सही है: यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद् इस्तीफ़ा देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि इसमें केवल अस्वीकृति या कड़ी आलोचना व्यक्त की जाती है। हालाँकि, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद् को सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा देना होगा, क्योंकि वे सदन का विश्वास खो देते हैं।

93. (d)

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 158(3) में प्रावधान है कि राज्यपाल की परिलब्धियाँ एवं भत्ते संसद द्वारा कानून के माध्यम से निर्धारित किए जाएँगे। जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता, तब तक वे द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

कथन 2 सही है: अनुच्छेद 158(3)(a) में कहा गया है कि यदि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो परिलब्धियाँ एवं भत्ते राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएँगे, जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे।

कथन 3 सही है: राज्यपाल की परिलब्धियाँ एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उन्हें कम नहीं किया जा सकता।

94. (d)

1 सही है: राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हालाँकि, उसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही उसी तरीके से और उसी आधार पर हटाया जा सकता है, जिस तरह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

कथन 2 सही है: राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें दिवालियापन, मानसिक/शारीरिक अशक्तता या सिद्ध कदाचार जैसे आधारों पर केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है।

कथन 3 सही है: राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, सामान्य तौर पर कदाचार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच के बाद।

95. (a)

कथन 1 सही है: संविधान [अनुच्छेद 67(b)] में कहा गया है कि उप-राष्ट्रपति को राज्य सभा द्वारा पारित तथा लोक सभा द्वारा सहमत प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। हालाँकि, इसमें पद से हटाने के लिए कोई आधार निर्दिष्ट नहीं किया गया है (राष्ट्रपति के विपरीत, जिस पर केवल "संविधान के उल्लंघन" के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है)।

कथन 2 सही नहीं है: पदच्युति प्रस्ताव" या "हटाने का प्रस्ताव (Removal resolution) केवल राज्य सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है [अनुच्छेद 67(b)]। राज्य सभा द्वारा इसे पारित करने के बाद ही लोक सभा को इस पर सहमति देनी होगी।

कथन 3 सही नहीं है: प्रस्ताव को राज्य सभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत [पूर्ण बहुमत (Absolute majority)] द्वारा पारित किया जाना चाहिए, और तत्पश्चात् लोक सभा में साधारण बहुमत द्वारा उस पर सहमति होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि दोनों सदन इसे पूर्ण बहुमत से पारित करें।

कथन 4 सही नहीं है: मनोनीत सदस्य उप-राष्ट्रपति को हटाने में भाग ले सकते हैं। हालाँकि, वे उसके मतदान में भी भाग ले सकते हैं (राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत, जहाँ वे मतदान में भाग नहीं ले सकते)।

96. (a)

कथन 1 सही है: अंतर-राज्यीय परिषद् एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 263 में ऐसी परिषद् की स्थापना का प्रावधान है, जिससे यह कथन सही सिद्ध होता है।

कथन 2 सही है: अनुच्छेद 263 के तहत, राष्ट्रपति को अंतर-राज्यीय परिषद् की स्थापना करने का अधिकार है, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी संस्था से जनहित की पूर्ति होगी। परिषद् के कर्त्तव्य, संरचना और प्रक्रिया भी राष्ट्रपति द्वारा परिभाषित की जाती है। इससे यह पुष्टि होती है कि कथन सही है।

कथन 3 सही नहीं है: अनुच्छेद 263 में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अंतर-राज्यीय परिषद् एक स्थायी निकाय है या इसकी बैठक प्रति वर्ष कम-से-कम एक बार होनी चाहिए। चूँकि यह विवरण उपलब्ध कराई गई मूल सामग्री में मौजूद नहीं है, इसलिए इस कथन को सही नहीं माना जा सकता।

97. (d)

कथन 1 सही नहीं है: अनुच्छेद 84(b) में राज्य सभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोक सभा के लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है। यह निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों पर लागू होता है। मनोनीत होने के लिए 35 वर्ष की आयु सीमा की कोई आवश्यकता नहीं है।

कथन 2 सही है: लोक सभा के लिए निर्वाचन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।

कथन 3 सही है: लोक सभा में राज्यों को सीटें इस प्रकार आवंटित की जाती हैं कि, जहाँ तक संभव हो, सीटों की संख्या और प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात संपूर्ण भारत में समान हो।

98. (c)

विकल्प (a) सही नहीं है: प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75(4) के तहत पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। शब्द हैं: "संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना" और "कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना", लेकिन इसमें 'संविधान की रक्षा और बचाव करना' वाक्यांश शामिल नहीं है।

विकल्प (b) सही नहीं है: अनुच्छेद 99 के तहत, सांसद “संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने” और “भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने” की शपथ लेते हैं।

विकल्प (c) सही है: अनुच्छेद 159 के अनुसार, राज्यपाल शपथ लेता है: “...संविधान और कानून का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करने तथा राज्य के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की।”

इस प्रकार, राज्यपाल की शपथ में स्पष्ट रूप से ‘संविधान की रक्षा और बचाव’ का उल्लेख है।

विकल्प (d) सही नहीं है: अध्यक्ष का चुनाव लोक सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है (अनुच्छेद 93)।

वह अध्यक्ष के रूप में अलग से संवैधानिक शपथ नहीं लेता है। एकमात्र शपथ अनुच्छेद 99 के तहत संसद सदस्य होने की ली जाती है।

99. (d)

कथन 1 सही नहीं है: अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, यदि राज्य सभा एक प्रस्ताव पारित कर दे (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से) कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। लेकिन यह सिर्फ़ एक अनुज्ञात्मक उपबंध (Enabling provision) है, कोई बाध्यता नहीं। संसद कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं है; उसे सिर्फ़ ऐसा करने की शक्ति प्राप्त है।

कथन 2 सही नहीं है: राज्य सभा (राज्य परिषद्) एक प्रस्ताव पारित कर सकती है (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से) जिसमें यह घोषित किया जा सकता है कि राष्ट्रीय हित में संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है। एक बार पारित हो जाने पर, संसद को उस मामले पर संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार (बाध्य नहीं) प्राप्त हो जाता है। कोई भी प्रस्ताव अधिकतम एक वर्ष तक प्रभावी रहता है (जैसा कि प्रस्ताव में निर्दिष्ट है)। इसे उसी तरीके से एक नया प्रस्ताव पारित करके नवीनीकृत किया जा सकता है, प्रत्येक नवीनीकरण एक वर्ष के लिए वैध होगा। इस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, प्रस्ताव की समाप्ति की तिथि से 6 महीने बाद प्रभावी नहीं होता। इसलिए, ऐसे कानून स्वतः स्थायी नहीं होते।

100. (d)

कथन I सही नहीं है: सांसदों को केवल संसद सत्र के दौरान (तथा सत्र से 40 दिन पहले और बाद में) सिविल मामलों में ही गिरफ़्तारी से छूट प्राप्त होती है।

उन्हें सत्र के दौरान भी आपराधिक मामलों (जैसे, हत्या, भ्रष्टाचार, निवारक निरोध) में गिरफ़्तार किया जा सकता है।

कथन II सही है: सांसदों के विशेषाधिकार संसद द्वारा कानून के माध्यम से परिभाषित किए जाते हैं। जब तक संसद इस पर कोई नया कानून नहीं बनाती तब तक, विशेषाधिकार वही रहेंगे, जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के लागू होने से ठीक पहले लागू थे।

■■■■